Combined discussion on General Budget; on the budget of Union Territory of Jammu and Kashmir for 2024-25 and Demand for Grants in respect of Union Territory of Jammu and Kashmir 2024-25

श्रीमती डिम्पल यादव **(मैनपुरी) :** सभापति महोदया, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं । हमारा देश किसान प्रधान और कृषि प्रधान देश है । अगर हम हमारे किसान और युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं समझती हूं कहीं न कहीं हम सब अपने फर्ज से डगमगा रहे हैं । वित्त मंत्री जी ने 9 प्राथमिकताओं की बात की और कृषि को जहां पहला स्थान दिया गया, वहीं मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहती हूं कि कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या है? जहां यह कहा गया था कि वर्ष 2022 तक आप किसान की आय दुगुनी कर देंगे और एमएसपी का वायदा किया गया था, तो मैं कृषि मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि आज एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर में कितना बजट सरकार द्वारा दिया जा रहा है? यूपी को इस बजट के तहत क्या मिला है? क्या एक भी मंडी पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश में बनी है? किसान की जरूरी चीजों पर क्या इस सरकार ने जीएसटी माफ की है या खाद में सब्सिडी देने में सरकार कायम रह पाई है? जहां खुद प्रधान मंत्री उत्तर प्रदेश के विधान सभा चुनाव में आए थे, उत्तर प्रदेश की जनता से वहां के लोगों से उन्होंने वायदा किया था कि वह आवारा मवेशियों की समस्या से किसानों को निजात दिलाएंगे । आवारा पशुओं की जो समस्या है, जिसकी वजह से आज हमारा देश चौकीदार बन गया है, रात भर सो नहीं पा रहा है । इस समस्या को लेकर क्या कोई प्रावधान बजट में रखा गया है? इसी के साथ जहां किसान आंदोलन में लगभग 700 किसानों ने अपनी जान गंवाई, जहां उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को मंत्री जी के बेटों द्वारा रौंदा गया । हम इस सरकार को बताना चाहते हैं कि वर्ष 2014 से 2022 तक लगभग एक लाख किसानों ने आत्म हत्या की है । मैं कृषि मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि प्रधान मंत्री फसल बीमा के तहत कुल किसान लाभ कितना मिला है और यदि इसमें गिरावट आई है, तो कितनी आई है? यह सरकार लगातार एक दशक से किसानों की अवहेलना कर रही है । गांवों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है । इसकी एक बड़ी वजह महंगाई है । जहां मनरेगा में सरकार ने 89 हजार करोड़ का बजट दिया है, हमारी मांग है कि कम से कम 100 दिन का वेजेज मनरेगा के तहत लोगों को सुनिश्चित किया जाए और मनरेगा का लगभग 20 प्रतिशत बजट बढ़ाया जाए। इसी के साथ शिक्षा में भी लगातार हमारा बजट घट रहा है । जहां यह आज टोटल बजट स्पेंडिंग एलोकेशन का केवल ढाई प्रतिशत है । जहां यूनेस्को ने यह बेंचमार्क दिया है कि यह लगभग 4 से 6 प्रतिशत होना चाहिए, वहीं यूजीसी के फंड्स लगातार घटाए जा रहे हैं और इसको इस बार लगभग 60 से 61 प्रतिशत घटा दिया गया है । जहां हम सस्ती और अच्छी शिक्षा की बात करते हैं, वहां यह सरकार लगातार शिक्षा का बजट कम कर रही है । मैं समझती हूं कि हमारे देश के युवाओं और स्टूडेंट्स के प्रति इनकी नीयत साफ नहीं है, मंशा सही नहीं है ।

महोदया, आज हमारे देश का युवा निराश है । जहां निराशा संभव को भी असंभव बना देती है । मैं समझती हूं कि रोजगार को लेकर जो वायदे किए गए थे, सरकार पूरी तरह इसमें विफल रही है और लगातार बेरोजगारी दर बढ़ रही है । जहां आज बेरोजगारी दर 9.2 प्रतिशत है, महिलाओं की बेरोजगारी दर 18.5 प्रतिशत है । मैं

समझती हूं कि लगातार युवाओं का मनोबल गिराने का काम इस सरकार ने किया है । अग्निवीर जैसी योजना लाकर इस सरकार ने नौजवानों का, युवाओं का, इस देश की प्रतिष्ठा का सम्मान गिराने का काम किया है ।

जो सरकार सोशल जस्टिस की बात करती है, वह आज भी जातिगत जनगणना से मुंह मोड़ रही है । अनुसूचित जाति, जनजाति पर होने वाले अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में यह अपराध नंबर वन पर है । साथ ही महिलाओं के साथ जघन्य अपराध लगातार बढ़ रहे हैं । उत्तर प्रदेश आज इसमें भी टॉप लिस्ट पर है । मैं पूछना चाहती हूं कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यह सरकार क्या कर रही है? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने 1090 जैसी सेवा चलाकर माताओं, बहनों, बेटियों को सम्मान दिलाने, उनको उनका हक दिलाने का काम किया था, तो इस बजट में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या प्रावधान रखा गया है?

महोदया, आज अगर स्वास्थ्य की बात करें, तो लगभग 1.9 प्रतिशत ऑफ जीडीपी का खर्च आज यह सरकार स्वास्थ्य के लिए दे रही है । There is no focussed agenda for the health care of the country irrespective of the fact that we are speaking about India being the fifth largest economy and moving towards the third largest economy. If we see the fast-growing population of the country, 1.9 percentage of the Budget is very less for the health services of the country. A decision to exempt three cancer drugs is a welcome move by the Finance Minister.

But it is a very small step in the right direction.

महोदया, हमारे उत्तर प्रदेश लखनऊ में एक कैंसर इंस्टिट्यूट है, जिसमें लगभग एक हजार करोड़ रुपये लगे हैं और वह तैयार है, लेकिन केंद्र की सरकार और स्टेट की सरकार यह सुनिश्चित नहीं कर पा रही है कि वह कैंसर इंस्टिट्यूट सुचारु रूप से चल सके । कैंसर के केसेज लगातार देश में बढ़ रहे हैं । मेरा मानना है कि अगर यह कैंसर इंस्टिट्यूट सही ढंग से सरकार चला लेती है कि तो सस्ता इलाज हम अपने देशवासियों को दे पाएंगे । There is a massive gap between the demand and supply in the healthcare infrastructure. डॉक्टर्स, नर्सेज और टेक्निशियन्स की बहुत भारी कमी है । ये जो बड़े-बड़े वायदे कर रहे हैं और जो बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़े-बड़े एम्स और मेडिकल कॉलेजेज बना लिये हैं, लेकिन 100 परसेंट तरीके से कोई भी मेडिकल कॉलेज या एम्स सुचारु रूप से प्रदेश में नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि उनमें भारी डॉक्टर्स, नर्सेज और टेक्निशियन्स की कमी है ।

इसी के साथ टीचिंग फैकल्टी में भी टीचर्स की भारी कमी है । सरकार जो कुपोषण की बात कर रही थी, भारत को जो एनीमिया मुक्त बनाने के बारे में बात कर रही थी तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आप सभी अपने वायदों में विफल हुए हैं । आपने लोगों से जो भी वायदे किए थे, आपने सारे वायदे जनता के साथ तोड़ने का काम किया है ।

महोदया, जहां ये जीडीपी की बात करते हैं, जहां ये थर्ड इकोनॉमी की बात करते हैं कि हमारा देश तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, वहीं हमें पर कैपिटा इनकम की बात करनी है, हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करनी है, हमें महंगाई को बांधने की बात करनी है, हमें इलाज मुफ्त और सस्ता दिलाने की बात करनी है । आप जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं तो मैं समझती हूं कि इसमें भी समय-सीमा तय होनी चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, उनकी समय-सीमा निर्धारित होनी चाहिए, क्योंकि यह टैक्स की मनी है ।

माननीय सभापति **:** धन्यवाद माननीय सदस्या ।

SHRIMATI DIMPLE YADAV: Madam Chairperson, I will take two minutes. यह जनता का पैसा है । इसे सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं ।

महोदया, मैं इसी के साथ कहना चाहूंगी कि reformative and evolutionary changes can come in the country even after eleven years. But dedication and concentration are required from the Government. Nothing can alter the past but responsible behaviour by the Government. I am not playing a blame game here. I am saying a responsible behaviour is the behaviour in which we are responding to the present situation. And if the Government plays a responsible behaviour, then formative changes can come in the country.

Thank you, hon. Chairperson Madam.

श्री सुरेश कुमार कश्यप **(**शिमला**) :** माननीय सभापति महोदया, मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया । सर्वप्रथम मैं इस बजट का समर्थन करता हूं । साथ ही साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि एक सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बजट इस सदन में प्रस्तुत किया गया है । मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को उनकी तीसरी टर्म का पहला बजट और साथ ही साथ श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का यह सातवां बजट भाषण है, मैं उनको बहुत-बहुत बधाई देता हूं । इस बार का बजट इस देश को एक नई दिशा देने वाला बजट है, जो इस देश के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा । देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है । निश्चित रूप से यह एक गरीब कल्याण वाला बजट है ।

माननीय सभापति महोदया जी, पिछले 10 वर्षों के दौरान 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले हैं । मैं उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं । यह बजट गरीब कल्याण का बजट है । इसके साथ ही साथ 80 करोड़ गरीबों को लगातार मुफ्त राशन मिल रहा है । इस बजट में ?प्रधानमंत्री आवास योजना? के तहत तीन करोड़ अतिरिक्त घर बनाने की घोषणा की गई है । निश्चित रूप से गरीबों के लिए यह एक बहुत बड़ा तोहफा है ।

शिक्षा के क्षेत्र सहित रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में मोदी सरकार ने विशेष रूप से इस बजट में प्रावधान किया है । निश्चित रूप से इस देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है । आने वाले पांच वर्षों के दौरान कौशल विकास के माध्यम से 4.1 करोड़ युवाओं को इसका लाभ मिलेगा । निश्चित रूप से देश में बेरोजगारी की जो समस्या है, वित्त मंत्री जी ने एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने के साथ-साथ वेतन देने का भी एलान किया है । मैं समझता हूं कि यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है ।

केन्द्रीय बजट में जिस प्रकार से युवाओं, महिलाओं, श्रमिकों, किसानों, शिक्षा, कौशल विकास तथा एमएसएमई के लिए विशेष तोहफे दिए गए हैं । इसके साथ ही साथ प्रदेशों को बाढ़ प्रबंधन और उससे जुड़ी परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और विशेष रूप से माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ।

सभापति महोदया, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में हिमाचल प्रदेश को सहायता राशि दी है । हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्ष आपदा आई थी, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश को बुहत नुकसान हुआ था । देवभूमि में बादल फटने और भूस्खलन से विकास की गति शून्य हो गई थी । उसने हिमाचल प्रदेश को दशकों पीछे धकेल दिया था, जिसमें 509 लोगों की मृत्यु हुई थी । ऐसा जख्म बहुत सारे परिवारों को मिला है, जिसको ताउम्र नहीं भरा जा सकता है । प्राकृतिक आपदा के समय पुनर्वास के लिए आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं ।

मुझे यह भी कहना है कि हमारे सामने विपक्ष के बहुत सारे साथीगण बैठे हुए हैं । जब हिमाचल प्रदेश की बात हो रही थी, तब बहुत सारे लोग टिप्पणी कर रहे थे । मैं कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और मैं समझता हूं कि आज वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, अगर हिमाचल प्रदेश को किसी प्रकार की मदद मिलती है, तो अच्छा है । यह तो ?इंडी? गठबंधन का हिस्सा है, इसलिए इन लोगों को भी खुशी होनी चाहिए । मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बात को लेकर बहुत सारे लोग काफी दुखी नजर आए थे । मैं समझता हूं कि यह अच्छी बात नहीं है । उनको भी अपने क्षेत्र और प्रदेश की बात यहां रखनी चाहिए ।

मैं विशेष रूप से केन्द्र सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आपदा के कारण हिमाचल प्रदेश को जो क्षति पहुंची थी, हिमाचल प्रदेश के लिए ?प्रधानमंत्री आवास योजना? के तहत 16,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं । जिनके घर बह गए थे या ढह गए थे, मैं समझता हूं कि उनको बहुत बड़ी सहायता मिली है । केन्द्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को एनडीआरफ के तहत 1,732 करोड़ रुपये मुहैया कराए हैं, ताकि जो क्षति हुई है, उसकी भरपाई की जा सके । इसके साथ ही साथ 2,643 करोड़ रुपये ?प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तृतीय? के तहत दिए गए हैं । हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात के कारण सड़कें और पुल खराब हो गए थे, उनको फिर से बनाया जा सकेगा । मैं समझता हूं कि यह एक बहुत बड़ा कदम है ।

हिमाचल प्रदेश को हर प्रकार की सहायता पहले भी दी गई है और आने वाले समय में भी केन्द्र सरकार ने और भी सहायता देने की घोषणा की है । यह निश्चित रूप से एक बड़ा कदम है । इस बार के बजट में हिमाचल प्रदेश को 10,351 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि स्वीकृत की गई है, यह एक बड़ा कदम है । हम चाहे रेल क्षेत्र की बात करें, एयर कनेक्टिविटी की बात करें या फिर इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की दिशा में काम होंगे, यह एक बहुत बड़ा कदम है ।

विशेष रूप से 2,968 करोड़ रुपये रेलवे के तहत स्वीकृत हुए हैं, जिसमें मेरे संसदीय क्षेत्र के लिए 300 करोड़ रुपये चंडीगढ़-बद्दी रेलवे लाइन के निर्माण के लिए स्वीकृत हुए हैं । मैं इसके लिए माननीय रेल मंत्री जी और केन्द्रीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं । ?अमृत योजना? में चार रेलवे स्टेशंस हैं, जिसमें शिमला का रेलवे स्टेशन शामिल है, उसका भी उन्नयन किया जाएगा । यह एक बहुत बड़ा कदम है ।

सभापति महोदया, मुझे थोड़ा समय और चाहिए । मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पहाड़ी क्षेत्रों में और विशेष रूप से उन राज्यों की जो भौगोलिक स्थिति है, जहां पर बार-बार बादल फटने की घटनाएं होती हैं, भूकम्प आता है, ओलावृष्टि होती है और ऐसी प्राकृतिक आपदाएं समय-समय पर आती रहती हैं, जिससे जान-माल का भारी नुकसान होता है । इन राज्यों और मैं विशेष रूप से पहाड़ी राज्यों की बात करना चाहूंगा, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, असम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा जैसे राज्य हैं, इनके लिए पूर्वोदय की तर्ज पर एक अलग मंत्रालय या मंत्रालय में एक विभाग गठित किया जाए, जो

इन क्षेत्रों में इस प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उनका निरीक्षण करे और समय-समय पर इन प्रदेशों की आवश्यकतानुसार सहायता भी मुहैया करवाए । मैं केन्द्र सरकार के ध्यान में इस बात को लाना चाहता हूं ।

महोदया, मैं प्रदेश से रिलेटेड बातें भी कहना चाहूंगा । आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जो 18 महीने पहले सत्ता में आई थी । इन्होंने सत्ता में आने के लिए गारण्टियां दी थीं, वायदे किए थे, लेकिन 18 महीने बीतने के बाद एक भी वायदा यह सरकार पूरा नहीं कर पाई है । विकास को ग्रहण सा लग गया है । पूर्व सरकार ने जो योजनाएं हिमाचल प्रदेश में स्वीकृत की थीं, उन योजनाओं को बंद करने का काम किया है । मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर स्वास्थ्य योजना प्रदेश सरकार ने शुरू की थी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई थी, लेकिन इस सरकार ने सत्ता में आने के बाद उस योजना को बंद कर दिया । आज प्रदेश के लोगों के लगभग 370 करोड़ रुपये के बिल्स, विभिन्न हॉस्पिटल्स के हैं, को देना बाकी है, लेकिन सरकार ने इस योजना को स्क्रैप कर दिया है और प्रदेश की जनता के ऊपर एक बहुत बड़ा कुठाराघात किया है । इसी प्रकार से जो योजनाएं प्रदेश में शुरू हुई थीं, उन योजनाओं को आगे बढ़ाने के स्थान पर वे बंद कर दी हैं । इन्होंने महिलाओं के खातों में 1500 रुपये देने का वायदा किया था, वह पूरा नहीं कर पाए । इन्होंने प्रति वर्ष एक लाख रोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी से देने का वायदा किया था, लेकिन एक भी रोजगार नहीं दे पाए । इन्होंने किसानों से दूध खरीदने का वायदा किया था और गोबर खरीदने का वायदा किया था, वह भी पूरा नहीं कर पाए । इन्होंने 300 यूनिट बिजली देने की भी बात कही थी, लेकिन उसको भी पूरा नहीं कर पाए ।

माननीय सभापति **:** आप अपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्री सुरेश कुमार कश्यप **:** एक ऐसी सरकार, जो झूठ बोलकर सत्ता में आई । वह आज प्रदेश को पीछे धकेलने का काम कर रही है । ? (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से प्रदेश सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो जनकल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको जारी रखा जाए और हिमाचल प्रदेश के हितों को आगे बढ़ाया जाए ।

सभापति महोदया, मैं आपके सामने अपने क्षेत्र की कुछ मांगें भी रखना चाहूंगा, जो हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए विशेष रूप से आवश्यक है ।

माननीय सभापति **:** माननीय सदस्य, आप अपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्री सुरेश कुमार कश्यप **:** सभापति महोदया, मैं दो मिनट और लेना चाहूंगा ।

माननीय सभापति **:** आप अपनी बात एक मिनट में पूरी कीजिए ।

श्री सुरेश कुमार कश्यप **:** सभापति महोदया, मैं एक मिनट में अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं । हिमाचल प्रदेश एक टूरिस्ट प्रदेश है । बाढ़ के कारण हिमाचल प्रदेश को बहुत नुकसान हुआ है । मेरा यह आग्रह रहेगा कि हिमाचल प्रदेश को टूरिज्म की दृष्टि से विकसित करने के लिए और अधिक सहायता दी जाए, ताकि हिमाचल प्रदेश का और विकास हो सके । पीएमजीएसवाई-3 की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में विकास हो । अब इस बजट में पीएमजीएसवाई-4 की घोषणा की गई है । इससे हिमाचल प्रदेश में अटल टनल की तर्ज पर टनल्स बनाकर सड़कें बनाई जाएं, ताकि समय की बचत हो या जाम की स्थिति से छुटकारा मिल सके । मेरा ऐसा निवेदन रहेगा ।

महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र में एक सीसीआई सीमेंट प्लांट लगा है, जो जिला सिरमौर राजबन में है । यह काफी छोटा प्लांट है । इसको उन्नत किया जाए, क्योंकि वहां पर रॉ मैटेरियल की कमी नहीं है । इससे वहां पर ज्यादा उत्पादन हो सकेगा । इसी प्रकार से सीआरएफ और पीएमजीएसवाई में हिमाचल प्रदेश पर विशेष ध्यान दिया जाए । हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे छोटे नदी-नाले हैं, उनका चैनलाइजेशन किया जाए । मेरे संसदीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र पाँवटा साहिब काला अम्ब को रेलवे के साथ जोड़ा जाए । आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद) : मैडम, आपका शुक्रिया । बजट की स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने चार बिरादरियों का जिक्र किया । भारत की सबसे बड़ी अकलियत मुसलमान है, जो 17 करोड़ हैं । मैं हुकूमत से जानना चाहता हूं कि क्या 17 करोड़ मुसलमानों में गरीब नहीं हैं, नौजवान नहीं हैं, किसान नहीं हैं, ख्वातीन नहीं हैं? वतन-ए-अजीज में सबसे गरीब मुसलमान हैं । सबसे ज्यादा नाखवानगी मुस्लिम ख्वातीन में हैं । एआईडीएस और पीएलएफएस का डेटा यह बताता है कि मुसलमानों में सबसे कम असासे हैं और कंजम्शन लेवल दूसरे मजहबी ग्रुपों के बरइजबा सबसे कम है ।

मैडम, तालीमी इदारों में 15 और 24 साल की उम्र में एनरोलमेंट में मुसलमानों की सिर्फ 29 फीसद, शेड्यूल्ड कास्ट की 44 फीसद, हिन्दू ओबीसी की 51 फीसद और हिन्दी अपर कास्ट की 59 फीसद है । हायर एजुकेशन में मुसलमानों का एनरोलमेंट सिर्फ 5 फीसद है । पीएलएफएस का वर्ष 2018-19 का डेटा वेज एम्प्लॉय बताता है कि मुसलमान 22 फीसद थे, वर्ष 2022-23 में यह 15 फीसद हो चुका है । सेल्फ इम्प्लॉयमेंट में मुसलमान, हिन्दू और सिक्ख से ज्यादा 58.4 परसेंट हैं । रेग्युलर वेज एम्प्लॉयमेंट में सबसे कम मुसलमान 15 फीसद हैं और केजुअल लेबर में सबसे ज्यादा मुसलमान 26 फीसद हैं । मुसलमानों का रेग्युलर इम्प्लॉयमेंट में शेयर लॉस हो रहा है । मुसलमान नौजवानों को न रोजगार मिलता है, न तालीम के मवाके, न हुकुमत उनको तरबीयत सहुलियत दी जाती है । मोदी हुकूमत ने मुसलमानों को अछूत बना दिया है, न कोई सियासी नुमाइंदगी है, न मुल्क की तरक्की में उनको कोई हिस्सा दिया जा रहा है ।

मैडम, माइनोरिटी वेलफयर मिनिस्ट्री के बजट में वर्ष 2023-24 में 38 फीसद की कमी कर दी गयी । इसको पांच हजार करोड़ से तीन हजार करोड़ कर दिया गया । इस साल के बजट में सिर्फ चंद सौ करोड़ रुपये का इज़ाफा किया गया है । मगर वर्ष 2023-24 के बजट के लेवल पर पैसे मुक्तसर नहीं किए गए । यह मोदी हुकूमत की ?* कमिटमेंट है अक्लियतों के ताल्लुक से ।

मैडम, अक्लियती स्कॉलरशिप- अक्लियतों के गरीब तुलबा और तालीबात को दी जाने वाली रकम में कमी कर दी गयी है । वर्ष 2019 में मोदी जी ने कहा था कि एक करोड़ स्कॉलशिप्स दी जाएंगी, लेकिन अभी सिफ 58 लाख दी जा रही हैं । 47 फीसद अक्लियती एप्लीकेंट्स को हर साल स्कॉलरशिप्स से महरूम कर दिया जा रहा है । 10 साल से मैं कह रहा हूं कि डिमांड ड्रिवन करो । डिमांड ड्रिवन के लिए सिर्फ तीन हजार करोड़ रुपये की जरूरत है, मगर यह हुकूमत सच्चाई और ईमानदारी से काम नहीं कर रही है । वर्ष 2007-08 से माइनोरिटी स्कॉलशिप नंबर्स में इज़ाफ़ा नहीं हुआ है । प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप में कुंडु कमेटी ने कहा था कि मुसलमानों में ड्रॉप आउट रेट प्राइमरी लेवल पर होता है । हुकूमत 9 वीं क्लास से प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप के पैसे दे रही है । एनडीएमसी की इक्वैटी 800 करोड़ रुपये एक मज़ाक है । पीएमजेवीके में 910 करोड़ रुपये दिए गए । सारी दुनिया जानती है कि जहां मुसलमान बसता है, गांव में और शहर में, वह अंडर डेवल्प्ड एरिया है और आप ऊंट के

मुंह में जीरा देकर मज़ाक कर रहे हैं । हज में 97 करोड़ रुपये । हज कमेटी एक रिश्वत का मरकज बन चुकी है । प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के एक लाइसेंस के लिए पैसे देना पड़ता है । बिल्डिंग सिलेक्शन के लिए पैसे देने पड़ते हैं । मीना मुजल्फा में कंपनी के सिलेक्शन के लिए पैसे देने पड़ते हैं । मैं हुकुमत से मुतालिबा करता हूं कि इसे खत्म किया जाए और सीबीआई इंक्वायरी करवायी जाए । मोदी हुकूमत को मुसलमानों से नफरत को खत्म करना पड़ेगा । मुसलमानों को उनका दस्तूरी हक मिलना चाहिए । आप कैसे विकसित भारत बनाएंगे, अगर 17 करोड़ मुसलमानों से नफरत करेंगे ।

मैडम, फाइनेंस मिनिस्टर की पूरी स्पीच में बच्चों का जिक्र नहीं है । आज हमारे देश में 67 लाख बच्चे रोज़ भूखे सोते हैं । 46 मिलियन बच्चे माल-न्यूट्रिशिन की वजह से स्टेंटेड हैं । 25 मिलियन बच्चे वेस्टेड हैं । इन मासूम बच्चों की यह बदकिस्मती और बदबख्ती है कि एक शख्स चाय बेचकर वजीरेआज़म बन गया ।

The long-term capital gains tax was decreased from 20 per cent to 12.5 per cent. However, the indexation benefit has been removed and it would not apply to any property purchased after 2001. This will be detrimental to growth of real estate, limit household capital formation, and impact employment generation in construction sector. This change in the LTCG is a quasi-wealth tax on households, particularly, on the middle class.

As far as internship programme is concerned, अब पांच साल में एक करोड़ लोगों को इंटर्न कराएंगे यानी एक कंपनी को चार हजार लोगों को ट्रैन्ड करना पड़ेगा । मैं जानना चाहता हूं कि बड़ी कम्पनी के मायने क्या हैं? It is unachievable. Will it be based on market cap revenue or employee size? Maybe the Prime Minister Modi is asking Agniveer to do Internship after four years of service in Armed Forces.

Madam, 21 million people have given up all hopes and stopped looking at jobs. This brings down to 9 per cent the eligible population that is either employed or are looking for jobs. Maybe, the Finance Minister can introduce a *berozgaar* tax and tax on unemployed as well. There is no significant increase in the budget for social welfare and health care. It looks like Prime Minister Modi is saying: ?देश के मिडिल क्लास की सम्पत्ति पर पहला हक हमारे एलाइज़ का है ।?

In real terms, the allocation in health sector, in AB-PMJAY, has declined. The Prime Minister said during G20: ?In reality, India is hurting?. This Government wants to increase FDI from China. Is the Prime Minister not concerned that our Armed Forces cannot patrol 26 patrolling points out of 65 in Ladakh? Maybe the Prime Minister wants the Chinese monopoly in the Indian markets. Import from China has crossed $101 billion in 2024. The Prime Minister Modi says Khelo India but in reality, the Budget has shown that the Modi Government?s policy is *jhelo* India. गरीब, मिडिल क्लास, फार्मिंग, सिटी डेवलर्स, मैन एंड विमिन, सब मोदी जी को झेल रहे हैं ।

In the current financial year, till 5th February, 15,993 MSMEs have closed down and a total number of 35680 MSMEs have been closed down.

As far as Andhra Pradesh bifurcation is concerned, this Parliament has passed a law. For the last 10 years, the Modi Government has shown their intellectual dishonesty by not giving ITR, IIM, Bayyaram Steel Factory, Railway Coach Factory Kazipet, and recognition of Palmaru as a national project. This shows the intellectual dishonesty of this Government.

Madam, I end my speech by quoting a famous poet, in which I am amending certain verses:

?133 करोड़ इंसानों जिंदगी से बेगानों,

सिर्फ हुक्मरानों ने तुम्हारा हक छीना है,

खाक ऐसे जीने पर यह भी कोई जीना है,

बेशऊर भी तुमको बेशऊर कहते हैं,

सोचता हो ये नादान कैसे हवा में रहते हैं,

133 करोड़ इंसानों, कब तक यह खामोशी,

चलते फिरते जिंदानों गरीब, ख्वातीन, नौजवानों,

किसानों से रोने की सदाएं आती हैं,

जब शबाब पर आकर खेत लहलहाता है,

किसके नयन रोते हैं, कौन मुस्कुराता है,

काश तुम भी समझो, काश तुम भी जानो,

किस कदर भयानक है, जुल्म का यह ढप देखो,

रक्त से आतिश व आहन देखते ही जाओगे,

देखते ही जाओगे होश में न आओगे ।?

सभापति महोदया, अनएम्प्लॉयमेंट पर अभी बोला गया कि हम नौकरियां दे रहे हैं, तो शायर ने इनके बारे में अच्छा कहा है ।

?फूल शाखों पर खिलने लगे तुम कहो,

जान जिंदो को मिलने लगे तुम कहो,

चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो,

इस खुली झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता ।?

[جناب اسدالدین اویسی (حیدرآباد): ، میڈم آپکا بہت شکریہ بجٹ کی اسپیچ میں فائننس منسٹر نے چار برادریوں کا ذکر کیا، بھارت کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان ہے، جو 17 کروڑ ہیں، میں حکومت سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا 17 کروڑ مسلمانوں میں غریب نہیں ہیں، نوجوان نہیں ہیں، کسان نہیں ہیں، خواتین نہیں ہیں، وطنِ عزیز میں سب سے غریب مسلمان ہیں، سب سے زیادہ ناخواندگی مسلم خواتین میں ہیں۔ اے۔آئی۔ڈی۔ایس۔ اور پی۔ایل۔ایف۔ایس۔ کا ڈاٹا یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں میں سب سے کم اثاثے ہیں اور کنزمپشن لیول دوسرے مذہبی گروپوں کے بہ نسبت سب سے کم ہے۔

میڈم تعلیمی اداروں میں 15 اور 24 سال کی عمر میں اینرولمینٹ میں مسلمانوں کی صرف 29 فیصد، شیڈیولڈ کاسٹ کی 44 فیصد، ہندو او۔بی۔سی۔ کی 51 فیصد اور ہندو اپر کاسٹ کی 59 فیصد ۔ ہائر ایجوکیشن میں مسلمانوں کا اینرولمینٹ صرف 5 فیصد ہے۔ پی۔ایل۔ایف۔ایس۔ کا سال 19-2018 کا ڈاٹا ویج ایمپلائی بتاتا ہے کہ مسلمان 22 فیصد تھے، سال 23-2022 میں یہ 15 فیصد ہو چکا ہے۔ سیلف ایمپلائمنٹ میں مسلمان، ہندو اور سکھ سے زیادہ 58.4 ہیں۔ ریگولر ویج ایمپلائمنٹ میں سب سے کم مسلمان 15 فیصد ہیں اور کیزول لیبر میں سب سے زیادہ مسلمان 26 فیصد ہیں۔ مسلمانوں کا ریگولر ایمپلائمنٹ میں شیئر لوس ہو رہا ہے۔ مسلمان نوجوانوں کو نہ روزگار ملتا ہے، نہ تعلیم کے مواقع، نہ حکومت ان کوتربیتی سہولیات دی جاتی ہیں۔ مودی حکومت نے مسلمانوں کو اچھوت بنا دیا ہے، نہ کوئی سیاسی نمائندگی ہے، نہ ملک کی ترقی میں ان کو کوئی حصہ دیا جا رہا ہے۔

میڈم، مائینوریٹی ویلفئر منسٹری کے بجٹ میں سال 24-2023 میں 38 فیصد کی کمی کر دی گئی، اس کو 5000 کروڑ سے 3000 کروڑ کر دیا گیا۔ اس سال کے بجٹ میں صرف چند سو کروڑ روپئے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ مگر سال 24-2023 کے بجٹ کے لیول پر پیسے مختص نہیں کئے گئے۔ یہ مودی حکومت کی (کاروائی میں شامل نہیں) کمیٹمینٹ ہے، اقلیتوں کے تعلق سے۔

میڈم، اقلیتی اسکالرشِپ اقلیتوں کے غریب طلباء اور طالبات کو دی جانے والی رقم میں کمی کر دی گئی ہے۔ سال 2019 میں مودی جی نے کہا تھا کہ ایک کروڑ اسکالرشِپ دی جائیں گی، لیکن ابھی صرف 58 لاکھ اسکالرشِپ دی جا رہی ہیں۔ 47 فیصد اقلیتی ایپلیکینٹس کو ہر سال اسکالرشِپ سے محروم کر دیا جا رہا ہے۔ دس سال سے میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیمانڈ ڈریون کرو، ڈیمانڈ ڈریون کے لئے صرف 3 ہزار کروڑ روپئے کی ضرورت ہے، مگر یہ حکومت سچائی اور ایمانداری سے کام نہیں کر رہے ہے۔ سال 08-2007 سے مائنوریٹی اسکالرشِپ نمبرس میں اضافہ نہیں ہوا ہے۔ پری۔میٹرک اسکالرشِپ میں کُنڈو کمیٹی نے کہا تھا کہ مسلمانوں میں ڈروپ آؤٹ ریٹ پرائمری لیول پر ہوتا ہے۔ حکومت 9 کلاس سے پری۔میٹرک اسکالرشِپ کے پیسے دے رہی ہے۔ این۔ڈی۔ایم۔سی۔ کی ایکویٹی 800 کروڑ روپئے ایک مزاق پی۔ایم۔جے۔وی۔کے۔ میں 910 کروڑ روپئے دئے گئے ۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ جہاں مسلمان بستا ہے، گاؤں میں اور شہر میں، وہ انڈر ڈیولپ ایریا ہے اور آپ اونٹ کے منہ میں ذیرہ دے کر مزاق کر رہے ہیں، حج میں 97 کروڑ روپئے۔ حج کمیٹی ایک رشوت کا مرکز بن چکی ہے۔ پرائیویٹ ٹور آپریٹرس کے ایک لائسنس کے لئے پیسے دینا پڑتا ہے۔ بلڈنگ سیلیکشن کے لئے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ مِنیٰ مزدلفہ میں کمپنی کے سیلیکشن کے لئے پیسے دینے پڑتے

ہیں۔ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اسے ختم کر دیا جائےاور سی۔بی۔آئی۔ انکوائری کراوائی جائے۔ مودی حکومت کو مسلمانوں سے نفرت کو ختم کرنا پڑے گا۔ مسلمانوں کو ان کا دستوری حق ملنا چاہئیے۔ آپ کیسے وِکست بھارت بنائیں گے، اگر 17 کروڑ مسلمانوں سے نفرت کریں گے۔

میڈم، فائننس منسٹر کی پوری اسپیچ میں بچوں کا ذکر نہیں ہے۔ آج ہمارے دیش میں 67 لاکھ بچے روز بھوکے سوتے ہیں۔ 46 ملین بچے مالنیوٹریشن کی وجہ سے اسٹینٹینڈ ہیں۔ 25 ملین بچے ویسٹیڈ ہیں۔ ان معصوم بچوں کی یہ بد قسمتی اور بد بختی ہے کہ ایک شخص چائے بیچ کر وزیرِ اعظم بن گیا۔

اب پانچ سال میں ایک کروڑ لوگوں کو انٹرن کرائیں گے، یعنی ایک کمپنی کو چار ہزار لوگوں کو ٹرینڈ کرنا پڑے گا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ بڑی کمپنی کے معنیٰ کیا ہیں؟ دیش کے مِڈل کلاس کی سمپتّی پر پہلا حق ہمارے ایلائز کا ہے۔ غریب، مِڈل کلاس، فارمنگ، سِٹی ڈیولرس، مین اور وومین، سب مودی جی کو جھیل رہے ہیں۔

133 کروڑ انسانوں، زندگی سے بیگانوں

صرف حکمرانوں نے تمہارا حق چھینا ہے

خاک ایسے جینے پر یہ بھی کوئی جینا ہے

بے شعور بھی تم کو بے شعور کہتے ہیں،

سوچتا ہوں یہ نادان کیسے ہوا میں رہتے ہیں،

133 کروڑ انسانوں، کب تک یہ خاموشی،

چلتے پھرتے زندانوں، خواتین، نوجوانوں،

کسانوں سے رونے کی صدائیں آتیں ہیں

جب شباب پر آکر کھیت لہلہاتا ہے،

کس کے نین روتے ہیں، کون مسکراتا ہے،

کاش تم بھی سمجھو، کاش تم بھی جانوں،

کس قدر بھیانک ہے، ظلم کا یہ ڈھپ دیکھو،

رکت سے آتش و آہن دیکھتے ہیں جاؤ گے،

دیکھتے ہی جاؤ گے ہوش میں نہ آؤ گے۔

چیرمین صاحبہ، ان ایمپلائمنٹ پر ابھی بولا گیا کہ ہم نوکریاں دے رہے ہیں، تو شاعر نے ان کے بارے میں اچھا کہا ہے

پھول شاخوں پر کھلنے لگے تم کہو،

جان زندوں کو ملنے لگے تم کہو،

چاک سینوں سے سلنے لگے تم کہو

اس کھُلی جھوٹ کو، ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا،]

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Madam Chairperson, for affording me this opportunity to take part in the discussion on the Budget for the Financial Year 2024-25. I rise to oppose the Budget proposals for the year 2024-25 as it is not truly addressing the concerns of the common people of this country.

Madam Chairperson, this is the first Budget of the third term of the Modi Government. We, the Members of the Opposition, while taking part in the discussion on the Motion of Thanks on the President?s Address, had discussed and observed that this is not an NDA Government but an ?N-square DA? Government because this is a Government, totally dependent on Naidu-Nitish, and is totally a dependent alliance Government. ? (*Interruptions*) That is why the stability of this Government is a question. ? (*Interruptions*)

Madam Chairperson, if you see the Budget proposals announced by Madam Nirmala Sitharaman ji, the hon. Finance Minister has substantiated and ratified the observations made by the Opposition that this is a Government whose survival and existence is at the political pleasure of these two parties, Janata Dal (U) and the TDP, led by Nitish and Naidu respectively. That is why, my first submission is that the stability of the Government is at question, and that this Government can collapse any time before completing its term in office. That is the first point I would like to make. ? (*Interruptions*)

Madam Finance Minister has presented the Interim Budget with the full confidence that they will be coming back with ?400 paar?, with brutal majority. But after the elections, Madam had presented the Budget, giving a political message that the Government is lacking confidence. That is the reason by which the Government has succumbed to the pressure of the two political parties and violating the federal principles of our Constitution by giving thrust to only two States and discriminating other States. This is totally against the basic principles of the Constitution as the federal character of the Constitution is not complied with the pronouncement of the Budget proposals for the year 2024-25.

Madam Chairperson, I am confining my speech to four points. So, kindly allow me time. I have given more than 100 cut motion notices for which I am not getting an opportunity to speak. So, kindly give me some time so that I can move all these things.

Madam, the first point is the lack of transparency in the Budget. Kindly examine the Interim Budget, the total size of which was Rs. 47,65,000 crore. The full Budget is of Rs. 48,20,000 crore. That means, there is an additional expenditure of Rs. 55,000 crore.

Madam, what about the gross borrowings? Kindly see, it was Rs. 16,85,000 crore in the Interim Budget but in the full Budget, it is just Rs. 16,10,000 crore. That means, it is Rs. 75,000 crore less in the full Budget. So, my specific question to the hon. Finance Minister is this. From where does the additional allocation come?

Kindly explain to the House, where from the additional amount, which you have announced for so many programs in the full Budget, will come. No amount is allocated for the new projects or schemes announced in the full Budget. For example, at para 39 of the Budget speech, the Government announced a new scheme called Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan for improving the socio-economic conditions of the tribal communities covering 63000 villages benefiting five crore people. But the amount allocated in the Interim Budget, as well as in the full Budget, for the tribal affairs, is the same as Rs.13,000 crore. Where will the further allocation come from?

Also, you have declared an additional allocation of Rs.56,000 crore for Bihar and Rs.15,000 crore for Andhra Pradesh. But in the Budget allocation, the same amount of Rs.2,78,000 crore has been kept in the interim Budget as well as in the full Budget. So, it is very clear that the amount of allocation prescribed and presented in the Budget speech is not reflected in the figures of the Budget. That means, the Budget is lacking transparency, and hence it is to be opposed. The hon. Finance Minister has to explain regarding the transparency of the Budget.

Secondly, the focus point, and the flagship program of this Budget is nothing but employment and skilling. Madam, kindly note that the Government is indirectly admitting the fact that the 10-years rule of Narendra Modi ji's Government has established that the country had a growth but the growth is without having employment generation. It was a jobless growth. It is admitted.

Madam, corporate investment is not creating employment. Without employment, consumption and wealth will not increase. In the present situation, capital labour ratio is increasing, and the ratio of capital production is decreasing. Madam, if we examine the period from 1994 to 2002, the ratio of capital was 2.8 for generating employment, and from 2003 to 2017, it was 5.6. That means, the employment growth rate is decreasing. It will further enhance as the artificial intelligence is coming.

The Economic Survey presented by the hon. Finance Minister in the House points out that the Indian economy needs to generate an average of 78.5 lakh jobs annually until 2030 in the non-farm sector to address the unemployment problem. Unemployment is the biggest challenge. How is it going to be addressed? According to the CEIM, the unemployment rate stood at 9.2 per cent. But I am not going to dispute all the figures and all these things. I just want to know whether the Employment Linked Incentive and the Internship is sufficient to address the problem of unemployment.

You have announced three programs with regard to Employment Linked Incentive. I have no time. I know it very well. So, I will put it in brief. There is a Scheme-A. What is it? According to Scheme-A, the first month?s salary up to Rs.15,000 will be paid to the employer for an employee who is being recruited in the company, and that too, it will be given in three instalments. That is the first scheme.

The second scheme, which is known as Scheme-B, is in terms of EPFO contributions by both the employer and the employee for the first four years. Under Scheme-C, the Government will reimburse the provident fund contribution of employers up to Rs.3,000 per month for two years.

So, if you examine these three schemes, the incentive is for the employer, not for the employees. These three schemes are applicable to those who are employed. This Incentive scheme is applicable to those who are employed in the company. But where is the employment opportunity? No employment opportunity can be created out of these three schemes. Another question to the hon. Finance Minister is whether any employer will recruit anyone in his establishment to get one month?s wages, that is, up to Rs.15,000 in three instalments. Will he create an employment opportunity for a jobless youth for this amount? Who will pay him for the next 11 months? Will any employer recruit an unemployed youth for the sole reason that he will be getting Rs.3,000 per month for two years, and that too as the PF contribution? Is it for that reason that employment opportunities will be

generated? No, Madam. That is why, I am saying that the schemes which you have announced are not going to create any employment opportunity in the country.

Madam, I do appreciate the Government for the internship program. It is a very good program. I do fully appreciate it. That is also given in the Congress manifesto. But I have only one suggestion to give in this regard. What happened to the Production Linked Incentive Scheme? In the Financial Year 2021-22, an amount of Rs.1,97,000 crore was announced under the PLI scheme by the Government. But how much amount has been spent so far?

It is just Rs. 9,700 crore because it is not having a legal backing. My point is that any welfare programme in a developing economy has to be legally guaranteed for enforcement and implementation. So, my suggestion to the Government is to come with a legislation before the House so as to make it mandatory and compulsory as we have done in the case of Corporate Social Responsibility Fund. This has to be done.

Madam, I will conclude in only two minutes.

माननीय सभापति **:** माननीय सदस्य, आप एक मिनट के अंदर अपनी बात कम्प्लीट कीजिए ।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Okay, Madam.

I want a specific answer from the Madam Finance Minister regarding MSMEs. Paras 43 to 50 speak about new programmes to promote MSMEs. What is the budget allocation for it? In 2022-23, it was Rs. 23,583 crore. In 2023-24, it was Rs. 22,137 crore. There was a reduction of Rs. 1,446 crore. What about the Interim Budget? It allocated Rs. 22,137 crore. What is in the full Budget? It is the same amount. I would like to know from the hon. Finance Minister how she is going to implement the new programmes which are envisaged in the MSME sector, as described in the full Budget.

Now, I come to my final point of discrimination against the States. Madam, I represent the State of Kerala. We are having a vast potential of tourism, but none of the projects have been declared in the Budget for Kerala. We have been continuously suffering from floods and so many other natural calamities. Nothing has been declared in the Budget proposals for Kerala while so many announcements have been made in respect of other States. There are so many other aspects also. The financial situation of the State is also very difficult. In such a situation, the State of Kerala is totally discriminated against. That is why, I would

like to say that discrimination of certain States which are politically opposing the Government and giving fruitful benefits to the States which are supporting the Government is totally against the political ethos of our country and the basic constitutional thesis of our country.

With these words, I conclude. Once again, I would like to request the Government to see the issues of the Kerala State also along with other States.

Thank you very much.

SHRI K. RADHAKRISHNAN (ALATHUR): I am going to speak in my mother tongue. I oppose the Budget presented by the Hon. Finance Minister. We cannot say that this budget is going to improve the economic wellbeing of this country. We know, that during the elections and on several other occasions, our Prime Minister and the BJP leaders had told us that our country is moving rapidly towards economic growth. But the reality, as can be understood from the economic survey report and the Budget is quite contrary to this. The country is not developing, nor is the life of the common man improving qualitatively. We realize now, that we are going back, instead of moving forward. Therefore, as the former members said this budget is creating road block in our march to progress.

The most important failure is that the budget has failed to see this country impartially. A few States have been given preferential treatment, while, the majority of States are being discriminated against. We all know that the budget is an instrument to achieve economic growth, and the well-being of the common man. As I said, this Budget is not taking us forward.

All the promises made during the elections remain empty promises. BJP Government came to power in 2014. All the promises made before the 2014 elections, were forgotten when they formed the Government.

Governments are expected to show the commitment and responsibility to fulfill the promises they have given the people. But without fulfilling the promises, they faced the 2019 elections.

In 2019, when they were asked by the people whether they had fulfilled the promises made to the people, the BJP leaders said that the promises made before the elections are not meant to be fulfilled, but they are just promises. In 2019, they again came to power, and now in 2024, they have again made several promises.

But there are to signs in this budget that their promises are going to fulfilled this time as well.

The majority of our people are going to suffer. Earlier, our Hon. M.P. Shri Premachandran indicated one thing. During the election our Prime Minister went all over the country saying that his Party will get a mandate of 400 seats and return to power. But the Prime Minister?s Party has got a mandate of only 240 seats.

Therefore, the Party has not got a majority. And due to that, they have to succumb to pressures from other allies. This is reflected in the budget. Our Central Government budget has become a compromised budget, by succumbing to pressures. This is the plight of the BJP. Their arrogant claim of getting 400 seats, was rejected by the Indian electorate.

The people?s reaction, is also due to the fact that the Government has not fulfilled their promises. Despite the tall claims made by the Government, we can see that the life of the common man is worsening from day to day. Sir, scheduled castes and schedule tribes contribute, one fourth of our population. We have to examine their plight.

We are completing 77 years of our Independence. Their life is a misery even today. We claim that several programmes and policies were implemented to improve their quality of life. But we could not undertake any true assessment regarding the plight of our scheduled castes and scheduled tribe brethren. No serious attempts are made to mitigate their sufferings.

Therefore, I ask the Finance Minister whether she has any concrete programmes to improve their plight?

Are there any measures to improve the life of common people? The statistics are indicating that no measures are being taken. We know that the recent statistics and studies are showing that poverty is increasing in our country.

The Survey reports are showing that the suffering of the poor has increased. Where is our position in poverty index? What about the inequality index? Why are we discriminating?

So, in every aspect, the majority is continuing to suffer from backwardness. And no constructive programmes are there in the Budget to tackle this situation.

I come from the State of Kerala. Kerala, is a model for the rest of the country. But now our development has become a bane for us.

Sir, if we see this budget one would wonder whether a State called Kerala exists in this country. We have been demanding time and again, for financial aids in different sectors. That is why, the Kerala Government has directly approached the Finance Minister and gave her our demands.

We need a special package of 24,000 crores. Sir, I am concluding. Not a single pie has been earmarked in this budget. We are again requesting. Twenty Members of Parliament from Kerala are asking the Finance Minister the amount which Kerala needs should be allowed.

Sir, Kerala also is a part of India. Let me remind it once again.

One final point, our great poet and freedom fighter Vallathol had written in his poem during the freedom struggle.

?When you hear the name Bharat, your mind should swell with pride,

when you hear the name Kerala, your blood must pulsate in your veins?.

I am not instigating people. There should be a change in this attitude of neglect towards Kerala. With this request, I once again oppose this budget.

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Thank you, Madam, for allowing me to speak on the Union Budget 2024. Let me start by congratulating the Finance Minister for presenting the Union Budget for the sixth consecutive time. We are all really proud of you, Madam. There were some unsavoury comments that were made regarding not being educated in Harvard or Cambridge or something. All the Members should remember that there is a tall leader who came from Tamil Nadu, namely Kamraj who was not educated and did not finish his schooling also. But he is the one who has come forward and started the mid-day meal scheme and done something great for this country. So, education and leadership are not totally related. I hope and wish that the Opposition realises it.

Coming to the Budget, there were three issues raised here mainly by the Opposition with regard to ?सरकार बचाओ बजट?, upholding of federalism and Andhra Pradesh being given some special treatment. Let me talk about ?सरकार बचाओ बजट?.

But when we talk about that, I think that the Opposition should remember that they had formed the Government three times, namely in 2009, 2004 and 1991 wherein in 2009, they got 206 seats; in 2004, they got 145 seats; and in 1991, they got 232 seats. But here the NDA has won more than 272 seats and the BJP has won more than 240 seats, and we are very sure that this Government will run for the next five years. Be rest assured and there is nothing to worry about it. These are the different unprecedented times when Prime Minister Modi has been elected for the third time.? (*Interruptions*) So, this is an unprecedented time when we are seeing Modi ji being elected for the third time. Of course, Nehru ji has done it in the past, and there is nothing to take away from that.

But those were different times when the Opposition was listening much more than today, and the media was also considerate. Today, the Opposition is not listening and the media has been replaced by social media. Everyone is looking at every move. However, for winning the third time, we should congratulate Shri Narendra Modi. With regard to federalism that the Opposition is talking about in this Budget, when the UPA-II was formed in 2009, Andhra Pradesh gave 33 seats to UPA. In 2004, when the UPA-I was formed, Andhra Pradesh gave 29 seats out of 145 seats. What did we get in return? Andhra Pradesh was bifurcated in 2004 unscientifically. Even though Andhra Pradesh Assembly vehemently rejected the idea of bifurcation of the State, the UPA-II went ahead and bifurcated the State. This is not federalism.

Coming to the third argument regarding Andhra Pradesh being given special treatment, there is no special treatment that has been given to Andhra Pradesh in the Budget. For example, the grant of Rs. 50,000 crore that has been given to Andhra Pradesh was mentioned in the A. P. Reorganisation Act, 2014, itself, wherein section 94 of the A. P. Reorganisation Act clearly states that a special grant has to be given to the State of Andhra Pradesh for building the Capital. Regarding Polavaram Project, again in section 90 of A. P. Reorganisation Act, it was clearly mentioned that Polavaram Irrigation Project, which is a national project, a lifeline of Andhra Pradesh, is to be completed. So, there is nothing special about it.

Coming to industrial infrastructure development grant that has been given to us, it is also mentioned in section 94(1) of the A. P. Reorganisation Act that for the industrial development of the State, which Andhra Pradesh is very much lacking because all the industries are there in the State of Telangana, a grant will be given. Regarding the grant for the backward region of North Coastal Andhra and Rayalaseema, it is also mentioned in section 94(2) of the A. P. Reorganisation Act. I

wish and I hope that the Opposition does not have selective amnesia because they only drafted this Act and they should read this Act before making unsavoury comments about Andhra Pradesh being given special treatment. We had been unscientifically bifurcated in 2014. When the first Budget was presented in the State Assembly of Andhra Pradesh, the revenue deficit in that Budget was almost Rs. 24,000 crore. From then, our debt has increased and as of June, 2024, it has reached Rs. 9.74 lakh crore. In 2019, the debt was Rs. 3.75 lakh crore. So, for the State that is so young and only ten years old, we need a lot of handholding. We want to stand up. We want to run with the other States of this country. We want to be part of this development that is happening in the other parts of the country. For this, we need more support from the Central Government. Getting grants or making debt is one thing but where we are spending money is more important. We are spending it on welfare and infrastructure. But the problem was that from 2019-24, in the Department of Water Resources, only Rs. 20,000 crore was spent. From 2014-19, the same Department of Water Resources spent almost Rs. 47,000 crore. So, it has gone down by almost 60 per cent in the capital expenditure in the Department of Water Resources. When it comes to transport, roads and buildings, in 2014-19, Andhra Pradesh spent Rs. 8,800 crore but from 2019-24, it has come down to Rs. 1,357 crore. It has almost come down by 70 per cent.

13.58 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

So, taking a debt or borrowing money is a different thing but where we are spending is the most important thing. We are very much confident that we will be part of this development. We want to reconstruct and rebuild the State. We need more support from the Union Government. We are looking forward to it. We were on the knees before 2024 election. Now, we are standing up. We want to stand with the other States of the country. We need more support from the Union Government, which we look forward to in the next five years of the NDA Government.

-

14.00 hrs

SHRI RAHUL GANDHI (RAEBARELI): Hon. Speaker, Sir, thank you for allowing me to speak on the Budget 2024-25.

In my last speech, I spoke about some religious concepts, Shivji?s concept of *ahinsa*, the fact that the trishool is placed behind the back and is not held in the

hand. I spoke about the snake on Shivji?s neck, and I also said how all religions in our country propose the idea of non-violence, and can be encapsulated in the phrase ?डरो मत, डराओ मत? ।

I also said that there is an idea beyond the personal, the idea of the *abhay mudra* that transmits this notion of *ahinsa* and affection and fearlessness to everybody else.

Sir, as I said in my speech, there is an atmosphere of fear, हिन्दुस्तान में डर का माहौल है, and that fear has pervaded every aspect of our country. My friends are smiling, but they are also scared. ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्य, आप बजट पर बोलिए ।

? (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी **:** सर, मैं बजट पर आ रहा हूँ । ? (व्यवधान) मैं बजट पर ही बोल रहा हूँ । ? (व्यवधान) Sir, you see the problem is, in the BJP, only one man is allowed to dream to be the Prime Minister. If the Defence Minister decides he wants to be the Prime Minister, there is a big problem. There is a fear. So, this fear has spread throughout the country, and the question I was asking myself was why is this fear spreading so deeply? Why is it that my friends in the BJP are terrified, the Ministers are terrified, the farmers of India are terrified. ? (*Interruptions*) workers, youngsters are terrified ? (*Interruptions*) मैंने इसके बारे में काफी सोचा और इसका एक जवाब मैं आज प्रपोज़ करता हूँ ।

स्पीकर सर, आज से हज़ारों साल पहले हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को छह लोगों ने चक्रव्यूह में फंसा कर मारा था । सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है और अभिमन्यू को चक्रव्यूह में फंसा कर, ट्रैप कर के छह लोगों ने मारा था । मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है, जिसको पद्मव्यूह कहते हैं, जिसका मतलब लोटस फॉर्मेशन होता है । स्पीकर सर, जो चक्रव्यूह होता है, वह लोटस की शेप में होता है, कमल के फूल की शेप में होता है ।

सर, 21 वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है । स्पीकर सर, वह भी लोटस की शेप में है और उसका चिन्ह प्रधान मंत्री जी अपनी छाती पर लगा कर चलते हैं । सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जिस तरह से अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिन्दुस्तान के साथ किया गया है । हिन्दुस्तान के युवाओं के साथ, हिन्दुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं-बहनों के साथ, स्माल बिज़नेसिज़ के साथ, मीडियम साइज़ बिज़नेसिज़ के साथ किया गया है ।

सर, अभिमन्यु को छह लोगों ने मारा था । उनके नाम ? द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वथामा और शकुनि हैं ।

सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में छह लोग हैं ।? (व्यवधान) चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं, लेकिन उसके बिल्कुल सेंटर में छह लोग कंट्रोल करते हैं । जैसे उस टाइम छह लोग करते थे, वैसे आज भी छह लोग कंट्रोल कर रहे हैं । चक्रव्यूह को नरेन्द्र मोदी जी, अमित शाह जी, ... * कंट्रोल कर रहे हैं ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** प्लीज, एक मिनट ।

? (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी **:** सर, मुझे बोलने दीजिए ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** नो, आप बैठिए ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्य, आप संवैधानिक पद पर हैं । आपके कई माननीय सदस्यों ने यहां पर मुझे लिख कर दिया है कि जो माननीय सदस्य इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनका नाम नहीं लेना है । आपने लिख कर दिया है ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** नो, क्या आप उसकी पालना करना चाहते हो?

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** मैं प्रतिपक्ष के नेता से तो यह अपेक्षा करूंगा कि वह सदन के नियम-मर्यादा की पालना करें । यह मैं आपसे अपेक्षा करता हूं । आप चाहें नहीं करें, लेकिन मैं अपेक्षा करता हूं ।

? (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी **:** सर, अगर आप चाहते हैं तो मैं ... * का नाम इस लिस्ट से निकाल देता हूं । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्य, फिर आप ऐसा कर रहे हैं ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** ऐसा मैं नहीं चाहता । सदन के नियम व प्रक्रियाओं से यह सदन चलता है ।

? (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी **:** सर, अगर आप कहते हैं तो इसे मैं निकाल देता हूं ।? (व्यवधान) मैं तीन ही नाम यूज करूंगा ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आप सब सीट से मत उठिए ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्य, आप उनको समझाइए ।

? (व्यवधान)

SHRI RAHUL GANDHI: Speaker Sir, the *chakravyuh* that has captured India has three forces behind it. The first is the idea of monopoly capital that two people should be allowed to own the entire Indian wealth. So, one element of the *chakravyuh* is coming from the concentration of financial power. ? (*Interruptions*)

सर, मैं बजट को एक्सप्लेन कर रहा हूं ।? (व्यवधान) मैं वहीं आ रहा हूं । One element is financial power. The second element is the institutions, the agencies, CBI, ED and the Income Tax Department, of this nation. The third is the political executive. These three together are at the heart of the *chakravyuh* and they have devastated this country. My expectation was that this Budget would weaken the power of this *chakravyuh*, that this Budget would help the farmers of this country, would help the youth of this country, would help the labourers, and the small business of this country. But what I have seen is that the sole aim of this Budget, इसकी जो नीयत है is to strengthen this framework: the framework of big business, monopoly business, the framework of a political monopoly that destroys the democratic structure, and finally the framework of what one can call the deep state or the agencies. The result of this has been this. पहला काम इस चक्रव्यूह ने क्या किया, जो हिन्दुस्तान को रोजगार देते हैं, स्मॉल एंड मिडियम बिजनेसेस हैं, जो करोड़ों युवाओं को रोजगार देते थे, उन पर इस चक्रव्यूह ने आक्रमण किया, कैसे किया- नोटबंदी, जीएसटी और टैक्स टेररिजम । आप लोग आतंकवाद की बात करते हो, पूरे देश में कोई भी व्यक्ति अगर छोटा बिजनेस चलाता है तो रात को उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी से फोन कॉल आता है और टैक्स टेररिजम का वह शिकार बनता है । इस टैक्स टेररिजम को रोकने के लिए बजट में आपने कुछ भी नहीं किया है । टैक्स टेररिजम के कारण और आपकी जो नीतियाँ हैं, कोविड के समय आपने बड़े बिजनेसेस की मदद की और जो स्मॉल एंड मिडियम बिजनेसेस थे, उनको खत्म किया । उसके कारण आज हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है ।? (व्यवधान) एक युवा को रोजगार नहीं मिल सकता है ।

फाइनेंस मिनिस्टर सदन में उपस्थित हैं । आपने युवाओं के लिए क्या किया? बजट में आपने इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात कही । यह शायद एक मजाक है, क्योंकि आपने कहा कि यह इंटर्नशिप प्रोग्राम सिर्फ हिंदुस्तान की पांचों सबसे बड़ी कंपनियों में होगा । 99 पर्सेंट हमारे जो युवा हैं, उनका इस इंटर्नशिप प्रोग्राम से कुछ लेना-देना नहीं है, कोई फायदा नहीं होने वाला । आपने पहले टांग तोड़ दी और उसके ऊपर बैंडेड लगाने की कोशिश कर रहे हैं ।

आज युवाओं का मेन मुद्दा एग्जाम पेपर लीक है । आपने इनके लिए बेरोजगारी का चक्रव्यूह बना दिया । जहां भी हम जाते हैं, वे कहते हैं कि बेरोजगारी है, मगर पेपर लीक भी होता है । एक साइड पेपर लीक चक्रव्यूह, दूसरी साइड बेरोजगारी चक्रव्यूह ।? (व्यवधान) अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बताता हूं कि 10 साल में 70

बार पेपर लीक हुआ ।? (व्यवधान) पेपर लीक के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में एक शब्द नहीं कहा । युवाओं के लिए पेपर लीक सबसे जरूरी मुद्दा है । ?(व्यवधान) उन्होंने पेपर लीक के बारे में एक शब्द नहीं कहा है और उल्टा जो एजुकेशन बजट में पैसा देना चाहिए था, वह आपने बीस सालों में सबसे कम पैसा दिया है, 2.5 per cent of budget is allocated to education. ? (*Interruptions*) दूसरी तरफ आपने सेना के जवानों को अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया । इस बजट में अग्निवीरों की पेंशन के लिए एक रुपया नहीं है । आप अपने आपको देशभक्त कहते हैं, मगर जब अग्निवीरों की मदद करने की बात आती है, जवानों को पैसे देने की बात है, तो बजट में एक रुपया नहीं दिखाई देता, उनकी पेंशन के लिए एक रुपया आपने नहीं दिया । उनको आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया ।

जो अन्नदाता हैं, वे आपके चक्रव्यूह से निकलने के लिए, जो आपने तीन काले कानून बनाए, जमीन अधिग्रहण बिल को आपने कमजोर किया, उनको आप सही दाम नहीं देते हैं, इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए उन्होंने आपसे सिर्फ एक चीज मांगी है । दो चीजें नहीं मांगी, सिर्फ एक चीज मांगी है । उन्होंने कहा है कि हमें लीगल गारंटीड एमएसपी दे दो । आपने उनको बार्डर पर रोक दिया, आज तक रोड बंद है । आप उनसे बात करने को तैयार नहीं हैं । वे यहां मुझसे मिलने आए, आप उनको अंदर नहीं आने दे रहे हैं ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्य, आप सदन में असत्य नहीं कहें ।

? (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी **:** सर, मैं आपको फैक्ट बताता हूं, फिर आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा ।?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** अपने माननीय सदस्यों को कह दें कि वे सदन पर आरोप न लगाएं ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: उनको बोलने दीजिए ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप अपने माननीय सदस्यों को कह दें कि सदन पर आरोप न लगाएं ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं रिपोर्ट से बोलता हूं, बिना रिपोर्ट के नहीं बोलता हूं ।

? (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी **:** स्पीकर सर, मुझसे मिलने के लिए एक फार्मर्स का डेलिगेशन आया, मुझे बताया गया कि फार्मर्स के डेलिगेशन को अंदर नहीं आने देंगे । मैं जब उनसे मिलने गया तब उनको अंदर आने दिया गया, यह फैक्ट है । पता नहीं कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ, वह अलग बात है । किन्तु फैक्ट यही है कि जब मैं मीडिया के साथ वहां गया तब पार्लियामेंट के दरवाजे उनके लिए खुले, उससे पहले वह बंद थे । आप उनसे भी पूछ लीजिए ।

माननीय अध्यक्ष **:** आपने यह विषय उठाया, इसलिए मैं बोल रहा हूं । वैसे सदन की व्यवस्थाओं पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, किसको आने दें, किसको एलाऊ नहीं करें, यह स्पीकर का जूरिस्डिक्शन होता है । जब यह सूचना आई, आप उनसे मिले, आप उनसे पार्लियामेंट के अंदर मिले, लेकिन उसमें सदन की मर्यादा का उल्लंघन हुआ । कभी भी सदन में माननीय सदस्य के अलावा कोई व्यक्ति बाइट नहीं दे सकता और आपकी मौजूदगी में उन्होंने बाइट दी । यह क्लियर करना चाहता हूं ।

श्री राहुल गांधी **:** स्पीकर सर, यह टेक्नीकलिटीज थी, मुझे मालूम नहीं था । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आप मत बोलिए, आपके नेता बोल रहे हैं ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आपको बैठे-बैठे टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आपके सदस्य कमेंट्री कर रहे हैं, फिर वह कहते हैं कि इधर के लोग क्यों कमेंट्री कर रहे हैं ।

? (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी **:** स्पीकर सर, हम चाहते थे, हमारा एक्सपेक्टेशन था, जो अन्नदाता है, सरकार से सिर्फ एक चीज मांग रहा है, लीगल गारंटीड एमएसपी । हमें लगता था कि यह कोई बड़ा काम नहीं है, यह इतना बड़ा काम नहीं है, अगर सरकार बजट में इसका प्रोविजन कर देती तो जो हमारे किसान आपके चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, वह निकल पाते, यह हमारी थिकिंग थी । मगर आपने नहीं किया, मैं इंडिया गठबंधन की तरफ से गारंटी देता हूं कि हम यह काम करके दिखा देंगे । जो आपने अपने बजट में नहीं किया । मैं हिन्दुस्तान के सब किसानों से कहना चाहता हूं गारंटीड लीगल एमएसपी हम इस सदन में पास करके आपको देंगे ।

माननीय अध्यक्ष **:** आप बैठे-बैठे टिप्पणी मत करो, आप टिप्पणी करेंगे तब वह भी करेंगे ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आप फिर टिप्पणी कर रहे हैं ।

? (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी **:** स्पीकर सर, जो मिडल क्लास है, वह शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था, जब प्रधानमंत्री जी ने कोविड के समय उनसे थाली बजवायी थी तो उन्होंने दबाकर थाली बजायी, धड़ा-धड़, थाली बजाओ, थाली बजाओ, उन्होंने थाली बजायी । हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री जी ने मिडल क्लास को आर्डर दिया तो मिडल क्लास ने थाली बजायी । उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने उसी मिडल क्लास से कहा कि मोबाइल फोन की लाइट जलाओ तो मोबाइल फोन की लाइट जली, मिडल क्लास ने पूरे हिन्दुस्तान में मोबाइल फोन की लाइट जला दी । अब इस बजट में आपने उसी मिडल क्लास को एक छुरा और दूसरा छुरा छाती में मारा । एक

इधर मारा, और एक उधर मारा, इंडेक्शेसन आपने कैंसिल की, यह पीठ में छुरा था । कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया, वह छाती में छुरा था । आपने लांग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10 परसेंट से बढ़ाकर 12.5 परसेंट किया । यहां छुरी मारी, शार्ट टर्म में 15-20 परसेंट छुरी मारी । यह दुख की बात है, मगर इंडिया गठबंधन के लिए हिडन बेनिफिट है, मिडल क्लास अब आपको छोड़ने जा रही है और इस साइड आ रही है ।

मेरा कहना है, जहां भी आपको मौका मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो । एक चांस मिलता है, आप चक्रव्यूह बना देते हो, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं । हमारे बजट में किसानों का कर्जा माफ हुआ, चक्रव्यूह तोड़ा, मनरेगा हुआ, चक्रव्यूह तोड़ा, हम तो चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं और आप चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो । आप चाहते हो कि हिंदुस्तान छोटे-छोटे खांचों में रहे और हिंदुस्तान के गरीब लोग सपना न देख पाएं । सिर्फ ?* ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्य, आप देखें ।

? (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी **:** सर, मैं कैसे बोलूं? ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्यगण, आपके उपनेता मुझे लिखित में पत्र देकर गए हैं कि कोई भी माननीय सदस्य, जो इस सदन का सदस्य नहीं है, उसके बारे में टिप्पणी न करें । यह लिखित में देकर गए हैं ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आप बैठ जाइए ।

? (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी **:** स्पीकर सर, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं? ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आप मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते ।

? (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी **:** सॉरी, सर । मैं फिर थ्री और फोर कह देता हूं । ? (व्यवधान) क्या थ्री और फोर ठीक है? ? (व्यवधान) नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो कहना पड़ेगा, थ्री और फोर कह देता हूं । कोई और नंबर देना है तो बता दीजिए । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्य, मुझे बता दें कि क्यों लिखित में चिट्ठी देकर गए थे?

? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई **:** हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री पर जब इस प्रकार के आक्रमण करते हैं, ? (व्यवधान) हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के संदर्भ पर चिट्ठी भेजी, ? (व्यवधान) एक पूर्व मुख्यमंत्री को उद्योगपति से जोड़ना चाहते हैं । एक किसान नेता, जो हरियाणा के हैं? (व्यवधान) उनको उद्योगपति के साथ जोड़ना चाहते हैं । क्या यह सदन की मर्यादा है? ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** क्या आपको अलाऊ किया है? आपने मुझे जो चिट्ठी लिखी है, उसकी क्या मर्यादा है?

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** यह आपको बोलने नहीं दे रहे हैं ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आपसे मेरी यह अपेक्षा है, आप सदन के प्रतिपक्ष नेता है । सदन की यह अपेक्षा रहती है कि हम सदन का डेकोरम और डिसिप्लिन को बनाकर रखें, इसलिए आप जो विषय रखें उसे नियम और प्रक्रिया के अंदर रखें ।

? (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी **:** मैं कैसे कहूं और इनका इंडीकेशन कैसे दूं? आप मुझे बता दीजिए । ? (व्यवधान) कोई दूसरा तरीका हो, ? (व्यवधान) नाम नहीं लेने हैं तो कोई और तरीका दे दीजिए ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** एक मिनट, आप उनको ज्ञान मत बांटो, वह ज्ञानी हैं ।

? (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी **:** सर, ए 1, ए 2 चलेगा? ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय प्रतिपक्ष नेता, मैं आपसे फिर अपेक्षा कर रहा हूं कि कम से कम आप नियम और प्रकिया की पालना करेंगे । आप प्रतिपक्ष के नेता हैं ।

? (व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, whenever the hon. PM or the hon. Home Minister speaks, you do not say this to them. You are only advising the LoP. ? (*Interruptions*) How can it be possible? ? (*Interruptions*) क्या रूल तोड़ना चाहिए? ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** मैं तो सबसे यही अपेक्षा करता हूं ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आप बैठ जाइए । आप जानते हैं कि प्वाइंट ऑफ आर्डर क्या होता है? आप बैठ जाएं । आपके नेता बोल रहे हैं ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आप बैठ जाएं ।

? (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी **:** स्पीकर सर, ये जो दो लोग हैं, ये हिंदुस्तान के इन्फ्रास्ट्रकचर को और बिजनेस को कंट्रोल करते हैं । इनके पास एयरपोर्ट्स हैं, टेलीकॉम का सिस्टम है, पोर्ट्स हैं और अब रेलवेज़ में जा रहे हैं । ? (व्यवधान)

उपभोक्ता मामले**,** खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री**;** तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री **(**श्री प्रहलाद जोशी**) :** तेलंगाना में इतना बड़ा कांट्रेक्ट दिया, वह भी बोल दो । ? (व्यवधान)

श्रम और रोजगार मंत्री**;** तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री **(**डॉ**.** मनसुख मांडविया**) :** राजस्थान वाला भी बोल दो । ? (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी **:** सर, इनके पास हिंदुस्तान के पूरे धन की मोनोपली है । ? (व्यवधान) मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इनके बारे में मैं इंडिकेट कैसे करूं? ? (व्यवधान) इनके बारे में बोलना तो पड़ेगा । अगर आप हमें कहें कि इन दोनों के बारे में आप बोल ही नहीं सकते, तो वह हमें एक्सेप्ट नहीं है । हमें तो बोलना है । ? (व्यवधान) आप चाहते हैं कि नाम न लें, तो कोई और सिस्टम हमें दे दीजिए ।

माननीय अध्यक्ष **:** संसदीय कार्य मंत्री जी ।

? (व्यवधान)

SHRI RAHUL GANDHI: I am not yielding. *....(Interruptions)*

संसदीय कार्य मंत्री**;** तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री **(**श्री किरेन रिजिजू**) :** आपने प्रधान मंत्री जी को न राज्य सभा में बोलने दिया न लोक सभा में बोलने दिया । आप अनाप-शनाप बातें करते हैं । पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का रूल आप नहीं मानते । आप स्पीकर को चैलेंज करते हैं । ? (व्यवधान)

आपको नियम नहीं मालूम है । इस सदन का सदस्य होने के नाते नियम जानना जरूरी है । नेता प्रतिपक्ष को सदन के नियम के बारे में पता नहीं है । ? (व्यवधान) यह बहुत दुख की बात है । हम लोग, जो इस सदन के सदस्य हैं, नियम से चलते हैं । लोक सभा स्पीकर को चैलेंज करके आज सदन के नेता प्रतिपक्ष ने इस गरिमा को गिराया है । ऐसा नहीं चलता है । देश नियम से चलता है, सदन नियम से चलता है, संविधान से चलता है । ऐसा नहीं होता है । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आपके सदस्य ही आपको नहीं बोलने देना चाहते हैं ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** वह बैठकर टिप्पणी कर रहे हैं । कोई सदस्य खड़ा है । यही आपको सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं ।

? (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी **:** स्पीकर सर, मैं समझता हूं कि मंत्री जी को ... *, सॉरी ए वन और ए टू की रक्षा करनी है । नो प्रॉब्लम । ऊपर से ऑर्डर आया है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा । ? (व्यवधान)

Sir, he is permitted to defend them. ....*(Interruptions)* It is a democracy. .... *(Interruptions)* He can defend A-1 and A-2. ....*(Interruptions)* They can do it happily, Sir. ....*(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके सदस्य आज बैठे-बैठे बहुत टिप्पणियां कर रहे हैं और उठ रहे हैं । वह सबसे ज्यादा टिप्पणी कर रहे हैं । क्या किसी नियोजित तरीके से आप आए हैं?

? (व्यवधान)

SHRI RAHUL GANDHI: So, we are happy, Sir. If the Minister is protecting A-1 and A-2, it helps us only. ....*(Interruptions)* No problem. ....*(Interruptions)* We like it, Sir. .... *(Interruptions)* Please do it again. ....*(Interruptions)*

श्री किरेन रिजिजू **:** मैं तो व्यवस्था की बात कर रहा था ।

श्री राहुल गांधी **:** आप फिर शुरू हो गए ।

माननीय अध्यक्ष **:** संसदीय कार्य मंत्री जी ।

श्री किरेन रिजिजू **:** सर, मैं जो परिस्थिति बनी, उस पर कहने के लिए खड़ा हुआ हूं । ? (व्यवधान) उन्होंने बोला कि मैंने यील्ड नहीं किया । यह नियम होता है कि अगर हम समय मांगते हैं, तो यील्ड करना परंपरा है । ? (व्यवधान)

SHRI RAHUL GANDHI: You do not yield. ....*(Interruptions)* The Prime Minister does not yield. ....*(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष **:** उन्होंने तो व्यवस्था का प्रश्न उठाया था ।

? (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू **:** सर, मैं स्पीकर की परमिशन से खड़ा हुआ था ।

श्री राहुल गांधी **:** बिल्कुल सही बोला । मैंने यील्ड नहीं किया ।

श्री किरेन रिजिजू **:** आपने कहा मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं । मैंने जबरदस्ती नहीं बोला ।

श्री राहुल गांधी **:** आप बोल रहे हैं । ? (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू **:** मैंने स्पीकर सर की परमिशन ली । ? (व्यवधान) स्पीकर सर ने मेरा नाम लिया । आपने यील्ड नहीं किया, तभी मुझे लगा कि मुझे कहना चाहिए कि आपने प्रधान मंत्री जी को पूरे भाषण तक डिस्टर्ब किया, बोलने नहीं दिया । आज हम आपसे यील्ड मांग रहे हैं, 10 सेकेंड टाइम । आप बोल रहे हैं कि हम यील्ड नहीं करेंगे । यह कौन सी परम्परा है? मैं जबरदस्ती नहीं, बल्कि नियम के तहत बोल रहा हूं और स्पीकर की परमिशन पर खड़ा हुआ हूं । ? (व्यवधान) यह परम्परा होती है । एक-दूसरे को इज्जत देनी होती है । राहुल जी, इतनी तो कर्टसी होनी चाहिए । ? (व्यवधान)

SHRI RAHUL GANDHI: Sir, I will respond to that.

Sir, if when we raise our hand and ask for the Prime Minister and the Ministers to yield and they yield, we will yield every time. The moment you yield, I guarantee that we will yield.

In fact, I am ready, Mr. Speaker, Sir ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष **:** देखिए, आप सभी लोग नेता प्रतिपक्ष को डिस्टर्ब कर रहे हैं । आप बार-बार डिस्टर्ब कर रहे हैं । वेणुगोपाल जी सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं । आप नोट कर लीजिए ।

? (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी **:** स्पीकर सर, देश में तकरीबन 73 परसेंट दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं । ये हिन्दुस्तान की मेन स्ट्रैंग्थ हैं और सच्चाई यह है कि इनको कहीं भी जगह नहीं मिलती है । इनको बिजनेस में जगह नहीं मिलती है, इनको कॉर्पोरेट इंडिया में जगह नहीं मिलती है और इनको सरकारों में भी जगह नहीं मिलती है । ? (व्यवधान)

सर, आप ये फोटो देखिए ।

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय प्रतिपक्ष नेता, एक मिनट सुन लीजिए । मैंने पहले भी आपसे अपेक्षा की थी । अब आप प्रतिपक्ष के नेता हैं और संवैधानिक दायित्वों पर हैं ।

? (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी **:** सर, मैं एक फोटो दिखा रहा हूं । आपने टी.वी. ऑफ कर दिया है ।

माननीय अध्यक्ष **:** कोई टी.वी. ऑफ नहीं है । वह मेरा फोटा दिखा रहा है ।

श्री राहुल गांधी **:** सर, टी.वी. ऑफ है । आप दिखाइए । ? (व्यवधान) आप टी.वी. ऑफ कर देते हैं । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** प्लीज आप बैठ जाइए, मेरी एक बात सुनिए ।

SHRI RAHUL GANDHI: Sir, I apologize.

माननीय अध्यक्ष **:** नो अपोलोजाइज, मैं आपको अपोलोजाइज करने के लिए नहीं कह रहा हूं । आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, मेरी यह अपेक्षा रहती है कि आप सदन की मर्यादा को बनाए रखिए ।

श्री राहुल गांधी **:** सर, ये देखिए बंद हो गई । ? (व्यवधान) ये फोटों से क्यों डर रहे हैं? ये शिव जी की फोटो से डरते हैं । ये इस फोटो से डरते हैं । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** मैं पोस्टर नहीं आने दूंगा । यह गलत तरीका है । हम पोस्टर नहीं आने देंगे और सदन में नहीं लहराने देंगे । यह गलत तरीका है ।

? (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी **:** सर, फोटो दिखाना गलत नहीं है । आपकी परमिशन लेकर दिखाया है । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आपको कोई परमिशन नहीं है । नियम के तहत परमिशन नहीं है ।

श्री राहुल गांधी **:** सर, मैं यह फोटो दिखाना चाहता हूं, इससे मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** नियम के तहत परमिशन नहीं है ।

श्री राहुल गांधी **:** अच्छा सर । मैं इस फोटो से समझाना चाह रहा हूं । इसमें बजट का हलवा बंट रहा है । इस फोटो में मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा है, एक आदिवासी और एक भी दलित अफसर नहीं दिख रहा है । ? (व्यवधान) यह हो क्या रहा है?

सर, देश का हलवा बंट रहा है और इसमें 73 परसेंट के एक भी लोग नहीं हैं । आप लोग हलवा खा रहे हैं और बाकी को हलवा मिल ही नहीं रहा है । ? (व्यवधान)

स्पीकर सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया है । यह हमने पता लगाया है । ? (व्यवधान) आप लोग शांत हो जाइए । 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप उनके नाम जानना चाहते हैं, मैं आपको दे दूंगा । 20 अफसरों ने हिन्दुस्तान का बजट तैयार किया है । इसका मतलब हिन्दुस्तान का जो हलवा है, उसको 20 लोगों ने बांटने का काम किया है ।

स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से, 90 परसेंट लोगों में से सिर्फ दो हैं । एक मॉइनोरिटी और एक ओबीसी, लेकिन इस फोटो में एक भी नहीं है । इसका मतलब फोटो में आपने उनको पीछे कर दिया । आपने फोटो में तो आने ही नहीं दिया । कोई नहीं आ सकता । मैं चाहता था कि बजट में जाति जनगणना की बात उठे, जो पूरा देश चाहता है, 95 परसेंट लोग जातीय जनगणना चाहते हैं । कौन चाहते हैं? दलित चाहते हैं, आदिवासी चाहते हैं, पिछड़ा वर्ग चाहता है, गरीब जेनरल कास्ट के लोग चाहते हैं, मॉइनोरिटी चाहते हैं, सब चाहते हैं, क्योंकि सब लोगों को यह पता लगाना है कि हमारी भागीदारी कितनी है और हमारी हिस्सेदारी कितनी है । ? (व्यवधान)

सर, मगर मैं देख रहा हूं कि सरकार हलवा बांटती जाती है, बांटती जाती है, बांटती जाती है और बांटता कौन है, वही 2-3 प्रतिशत लोग और बंटता किसको है, वही 2-3 प्रतिशत लोगों को । ?(व्यवधान) वित्त मंत्री जी मुस्कुरा रही हैं । कमाल की बात है, ये हंसने की चीज नहीं है । ये हंसने की बात नहीं है । यह जातीय जनगणना है । इससे देश बदल जाएगा ।?(व्यवधान)

सर, ये जो पद्मव्यूह वाले हैं, चक्रव्यूह को पद्मव्यूह भी कहा जाता है, जो पद्मव्यूह वाले हैं, इनको गलतफ़हमी है । ये सोचते हैं के देश के युवा, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु हैं । देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं हैं, अर्जुन हैं । जो आपका चक्रव्यूह है, वे उसको फोड़कर फेंक देंगे, फेंकने वाले हैं । ?इंडिया? गठबंधन ने पहला कदम ले लिया है । हमने आपके प्रधानमंत्री जी के कॉन्फिडेंस को उड़ा दिया, मतलब आपके प्रधानमंत्री जी भाषण के दौरान आ ही नहीं पा रहे हैं । मैं आपको एडवांस में बता देता हूं कि अब वे मेरे भाषण के दौरान कभी नहीं आएंगे । सर, इसमें क्या गलती है?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आप एक बात बताइए । आप बोलिए ।

? (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी **:** सर, जो पद्मव्यूह वाले लोग हैं, जो कमल फॉर्मेशन वाले लोग हैं, उनको हिन्दुस्तान का नेचर नहीं समझ आया है । हिंसा और नफ़रत हिन्दुस्तान का नेचर नहीं है, चक्रव्यूह हिन्दुस्तान का नेचर नहीं है । हिन्दुस्तान का नेचर अलग है ।

अब मैं आपको हिन्दुस्तान के नेचर के बारे में बताना चाहता हूं । हर धर्म में चक्रव्यूह के खिलाफ फॉर्मेशन होता है । आप जानते हैं कि हिन्दू धर्म में चक्रव्यूह का अपोजिट क्या होता है??(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्य, आप चेयर को एड्रेस करके बोलिए ।

? (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी **:** सर, मैं बताता हूं कि शिव की बारात होती है । शिव की बारात में कोई भी आ सकता है । किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति बारात में आ सकता है, नाच सकता है, गा सकता है, अपना सपना देख सकता है ।

सर, अगर सिखों की बात की जाए, तो सेवा करने से किसी को नहीं रोका जा सकता है, लंगर से किसी को बाहर नहीं फेंका जा सकता है । इस्लाम में है कि कोई भी मस्जिद में आ सकता है, चर्च में कोई भी घुस सकता है, समुदाय में कोई भी आ सकता है । मगर इनके चक्रव्यूह में सिर्फ 6 लोग हैं । ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है । हम चक्रव्यूह तोड़ते हैं ।

हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं - मनरेगा, हरित क्रांति, आज़ादी, संविधान, ये चक्रव्यूह को तोड़ने के काम हैं । इससे देश में खुशी आती है, डर मिटता है, कॉन्फिडेंस आता है । आप पद्मव्यूह, चक्रव्यूह बनाने का काम करते हैं । चक्रव्यूह शिव की बारात को हरा ही नहीं सकता है । आप अपने इतिहास को देखिए । आप अपने आपको हिन्दू कहते हो । आप हिन्दू धर्म को नहीं समझते हो । ?(व्यवधान) आप चक्रव्यूह बनाने वाले लोग हो ।? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में यह कहना चाहता हूं । आप शांत हो जाइए, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं । घबराइए मत, डरो मत ।?(व्यवधान) जो चक्रव्यूह बनाए गए हैं । मैंने कोई अपमान नहीं किया है । मैं कभी अपमान नहीं कर सकता हूं । मैं ज़िंदगी भर, मरने तक अपमान नहीं कर सकता हूं । आप क्या बात कर रहे हैं?...(व्यवधान)

आपने ये छोटे-छोटे चक्रव्यूह बना रखे हैं, मैं इनको अपने छोटे से तरीके से समझने की कोशिश करता हूं । मैंने कुछ महीने पहले 6-7 घण्टे बढ़इयों के साथ काम किया । वहां विश्वकर्मा जी थे । मैंने उनसे एक सवाल पूछा । मैंने उनसे कहा कि आपको किस चीज से दुख होता है, किस चीज से दर्द होता है । उन्होंने मुझसे कहा कि राहुल ? (व्यवधान) आप बात सुनिए, समझ आ जाएगी और समझिए । सर, ये इंटरप्ट कर रहे हैं । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आप बोलिए ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आप इतना इंटरप्ट करते हो और बैठे-बैठे बोलते हो । आप तो पूरे भाषण में वेल में आ जाते हो और इंटरप्ट करने का सवाल करते हो ।

? (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी **:** स्पीकर सर, मैंने विश्वकर्मा जी से पूछा कि आप यहां सालों से बढ़ई का काम कर रहे हैं । ? (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर **(**हमीरपुर**) :** विश्वकर्मा जी कहां मिले?

श्री राहुल गांधी **:** पूरे देश में हैं । अगर आप देखोगे तो मिलेंगे । आप ढूंढो । आपको अपने घर में नहीं मिलेंगे, पूरे देश में मिलेंगे, जाकर ढूंढिये । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आप बोलिए । आप उनका जवाब मत दीजिए ।

श्री राहुल गांधी **:** मैंने उनसे पूछा कि विश्वकर्मा जी आपको दर्द किस बात का होता है, दुख किस बात का होता है तो उन्होंने कहा कि राहुल मैं यह टेबल बना रहा हूं । ? (व्यवधान) राहुल जी कहा । अब कहा, लेकिन वह मुझे अच्छा नहीं लगा । वह मुझे अच्छा नहीं लगा, मगर कहा । यह सच्चाई है । उन्होंने कहा कि राहुल जी मुझे दुख इस बात का होता है कि मैं यह टेबल बनाता हूं, मगर जिस शोरूम में यह टेबल रखी जाती है, मैं उस शोरूम में अंदर जा ही नहीं सकता हूं । मैं कुछ दिन पहले सुल्तानपुर के रास्ते में एक मोची भाई के साथ बैठा, उससे मैंने यह सवाल पूछा कि आपको दुख किस बात का होता है तो वह कहता है कि राहुल जी मेरा सम्मान सिर्फ मेरे पिता ने किया था और किसी ने नहीं किया ।

सर, मेरा कहना है कि जो आपने यह चक्रव्यूह बनाया है, इस चक्रव्यूह से करोड़ो लोगों को नुकसान हो रहा है, दर्द पहुंच रहा है । हम इस चक्रव्यू को तोड़ने जा रहे हैं । तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका, जिससे आप लोग डरते हो, कांपते हो, वह जाति जनगणना है । जैसा, मैंने कहा था कि इंडिया गठबंधन गारण्टीड लीगल एमएसपी इस सदन में पास करेगा, वैसे ही मैं कह रहा हूं, आपको अच्छा लगे या न लगे, हम जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके दिखाएंगे । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आप बैठे-बैठे टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? फिर वह टिप्पणी करेंगे ।

श्री राहुल गांधी **:** स्पीकर सर, आपने ये जो छोटे-छोटे खांचे बनाए हैं, यह जो सिस्टम बनाया है, चक्रव्यूह का सिस्टम बनाया है, यह जाति जनगणना से टूट जाएगा । इसके लिए हम पूरा दम लगाकर, पूरा इंडिया गठबंधन दम लगाकर काम करेगा । धन्यवाद । जय हिन्द ।

रक्षा मंत्री **(**श्री राज नाथ सिंह**) :** अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने बजट से संबंधित जो भी भ्रांतियां पैदा की हैं तो जब बजट से संबंधित जवाब देने के लिए वित्त मंत्री जी खड़ी होंगी, उन भ्रांतियों को लेकर जो भी क्लेरिफिकेशन देना है, जो कुछ भी देश को संदेश देना है, वह अपनी तरफ से संदेश देंगी । मैं मानता हूं कि बजट को लेकर कई भ्रांतियां पैदा की गई हैं, लेकिन देश की सीमा की सुरक्षा जिन सेना के बहादुर जवानों के हाथों में रहती है, यह इस देश की सुरक्षा का संवेदनशील मुद्दा है । सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, मैं उस संबंध में कहना चाहता हूं कि जब भी आपका आदेश होगा, इस सदन के समक्ष मैं अग्निवीरों को लेकर पूरी तरह से अपना स्टेटमेंट देने को तैयार हूं ।

श्री राहुल गांधी **:** स्पीकर सर, मुझे जवाब देना है ।

माननीय अध्यक्ष **:** उन्होंने कुछ नहीं कहा है । उन्होंने आपके शब्दों को लेकर बोला है ।

श्री राहुल गांधी **:** स्पीकर सर, उन्होंने मेरा नाम लिया है ।

माननीय अध्यक्ष : उन्होंने कहा है कि वे अग्निवीर के विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं ।

श्री राहुल गांधी : सर, डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि मैंने अग्निवीर की बात उठायी । पहले भी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि शहीद अग्निवीर परिवारों को कम्पसेशन दिया गया है । उन्होंने हाउस में कहा कि एक करोड़ रुपये कम्पसेशन दिया गया है । मगर, सर, वह गलत था । सर, उस शहीद के परिवार को इंश्योरेंस दिया गया था, कम्पसेशन नहीं दिया गया था ।

माननीय अध्यक्ष : नो ।

श्री राहुल गांधी : सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सच है । सर, कम्पसेशन दिया गया था । यह सच है ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो ।

श्री राहुल गांधी : सर, यह सच्चाई है और इसको कोई नकार नहीं सकता है । सर, मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं कि आपने एक चक्रव्यूह बना दिया है और मीडिया वालों को आपने पिंजरे में बंद कर दिया है, उनको बाहर निकाल दीजिए । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप प्रतिपक्ष के नेता हैं ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप क्यों हंस रहे हैं?

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आपका यह तरीका सही है?

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठे-बैठे टिप्पणी न करें ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप प्रतिपक्ष के नेता हैं । मैं आपसे यह अपेक्षा करता हूं कि आप नियम-प्रक्रिया को कृपया पूरा पढ़ लें । मुझे अच्छा लगेगा अगर आप नियम-प्रक्रिया को पूरा पढ़ लेंगे ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कभी भी सदन के मामले में कोई भी माननीय सदस्य टिप्पणी नहीं कर सकता है । यह व्यवस्था अध्यक्ष के तहत होती है ।

? (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : सर, बेचारे मीडिया वाले हैं ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** वे बेचारे नहीं हैं । आप उनके लिए ?बेचारा? शब्द मत बोलिए ।

श्री राहुल गांधी **:** नॉन-बेचारे मीडिया वाले ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** वे बेचारे नहीं हैं ।

? (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी **:** नॉन-बेचारे, नॉट बेचारे मीडिया वाले । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** मैं यहा बैठा हूं । वह आसन से बात कर रहे हैं तो आसन को बात करने दीजिए ।

? (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी **:** सर, नॉट बेचारे मीडिया वालों ने मुझ से कहा है कि आपसे हाथ जोड़कर कहें कि उनको निकलने दें । क्योंकि वे बड़े डिस्टर्बेंस में हैं ।

माननीय अध्यक्ष **:** आप सदन के नेता हैं ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आपको बैठे-बैठे बोलने की इजाजत नहीं है ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आप लोग बैठे-बैठे टिप्पणी मत कीजिए ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** मैंने पहले भी कहा है कि आप नियम-प्रक्रिया का पूरा अध्ययन कर लें । सदन की किसी भी व्यवस्था के मामले में, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप मुझे चैम्बर में आपकर मिलें, कोई परेशानी हो, किसी को एलाऊ न किया हो, कोई भी बात हो तो हमें बताएं । लेकिन सदन के अंदर, सदन की व्यवस्थाओं पर प्रश्न न उठाएं । यह मेरी आपसे अपेक्षा है ।

श्री विष्णु दत्त शर्मा ।

श्री विष्णु दत्त शर्मा **(**खजुराहो**) :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बजट, 2024-25 पर इस सदन में बोलने का मौका दिया ।

महोदय, आज पूरा देश गौरवान्वित है कि भारत के संसदीय लोकतंत्र में लगातार तीसरी बार भारत के प्रधान मंत्री के तौर पर किसी ने शपथ ली तो भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने शपथ ली है । मैं इस सदी के राष्ट्र

नायक प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को और हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को इस अभूतपूर्व ऐतिहासिक बजट के लिए हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं ।

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो बजट प्रस्तुत हुआ है, यह वर्ष 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है । अब यह बात अलग है कि मैं अभी इस सदन का माहौल देख रहा था और मुझे उसके बाद बोलने का अवसर मिला है । देश का विपक्ष इस देश के अंदर केवल नकारात्मक, झूठ और छल-कपट की राजनीति करना चाहता है । यह इस देश का दुर्भाग्य है कि इस प्रकार का विपक्ष आज इस भूमिका में सदन के अंदर बोल रहा है और ये इस भूमिका को लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं ।

माननीय अध्यक्ष जी, जब औवेसी जी बोल रहे थे तो यह कह रहे थे कि 17 करोड़ मुसलमानों को इस बजट के अंदर कोई अवसर नहीं मिला है । मैं आज कहना चाहता हूँ कि भारत के अंदर माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने, हमारी वित्त मंत्री जी ने 10 वर्षों के अंदर सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर जो काम भारत के अंदर किया है, वह सिर्फ भारत के प्रधान मंत्री मोदी जी ने ही किया है । हर समाज, वर्ग के लिए यह बजट सर्वस्पर्शी, सर्व समावेशी और विकासोन्मुखी तथा 140 करोड़ देशवासियों की आशाओं, आकांक्षाओं और अमृतकाल के सभी संकल्पों को सिद्ध करने वाला रहा है ।

आम बजट 2024-25 में विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का आर्थिक दस्तावेज इस बजट के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में प्रस्तुत हुआ है । मैं इस सदन के अंदर कहना चाहता हूँ कि जब हम मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ रहे थे, तब मध्य प्रदेश के चुनाव में उस समय हमको मध्य प्रदेश की जनता ने कहा कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी हैं और मध्य प्रदेश के मन में मोदी के अभियान के साथ हमने विधान सभा में रिकॉर्ड बनाया और लोक सभा के अंदर तो देश के इतिहास में 29 की 29 सीटें जीतकर मोदी जी को मध्य प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया ।

इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज कहना चाहता हूँ कि इस बजट के अंदर, जो वर्ष 2024-25 का बजट ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्य, एक मिनट रुक जाइए । प्लीज माननीय सदस्य, बैठ जाइए । सुरेश जी, मणिक्कम जी, प्लीज बैठिए । आप सदन की मर्यादाओं का ध्यान रखिए ।

श्री विष्णु दत्त शर्मा **:** अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024-25 का बजट माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो प्रस्तुत किया है, उस बजट के अंदर मैं मध्य प्रदेश की ओर से माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ । माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस बजट के अंदर मध्य प्रदेश के लिए 97 हजार 907 करोड़ रुपये दिए हैं, जो कि पिछले बजट की तुलना में 11 हजार 205 करोड़ रुपये अधिक हैं । प्रधान मंत्री मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश हमेशा रहा है, इसलिए मैं मध्य प्रदेश की जनता की ओर से माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि बजट में रेल मंत्रालय ने 14 हजार 738 करोड़ रुपये मध्य प्रदेश को दिए हैं, जो कि कांग्रेस के समय में केवल 632 करोड़ रुपये थे । माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री जी ने आज मध्य प्रदेश का रेल बजट 14 हजार 738 करोड़ रुपये का दिया है ।

मध्य प्रदेश में रेलवे का 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है । यह एक एतिहासिक कदम माननीय प्रधान मंत्री जी नेतृत्व में हुआ है । विगत 10 वर्षों में 1062 फ्लाईओवर से लेकर कई प्रकार की रेल की सौगातें माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को मिली हैं । माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में शपथ ली थी और उन्होंने तब कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है । मैं आज इस सदन में उल्लेख करना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने 55 वर्षों तक इस देश पर राज किया और कांग्रेस के उस समय के प्रधान मंत्री, चूँकि मैं उनके नाम का उल्लेख इसलिए नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वे सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि वे कहते थे कि यदि हम गरीब के लिए 100 रुपये भेजते हैं तो 85 पैसे दलाल और बिचौलिए खा जाते हैं, केवल 15 पैसे गरीब तक पहुंचते हैं ।

14.55 hrs (Shri A**.** Raja *in the Chair*)

आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि वर्ष 2014 के बाद माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने गरीबी हटाने का नारा नहीं दिया, लेकिन आज इस देश में माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बजट में फिर से जो प्रावधान किए गए हैं, उनके आधार पर, गरीब कल्याण योजनाओं के आधार पर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उभर कर आए हैं । यह मोदी जी के कारण ही इस देश में संभव हुआ है ।

माननीय सभापति महोदय, ?प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना? वर्ष 2020 से लागू हुई । इससे 80 करोड़ गरीब परिवारों को नि:शुल्क अनाज मिला है । ?आयुष्मान भारत योजना? के माध्यम से 20 करोड़ लोगों को फ्री में इलाज कराने का अधिकार मिला है । ?प्रधानमंत्री आवास योजना? के तहत माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने चार करोड़ परिवारों को उनके सर पर छत देकर उनके जीवन में खुशी लाने का काम किया है । माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने ?प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना? के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक बहनों को चूल्हे से मुक्ति दिला कर गैस सिलेंडर्स उपलब्ध कराने का काम इस भारत में किया है ।

आज मैं कहना चाहता हूं कि ?प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना? के माध्यम से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गांव-गांव को सड़कों से जोड़ने का प्रयास किया । आज माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस देश में एक-एक गांव को सड़कों से जोड़ने का प्रावधान इस बजट किया है । अगर 25 हजार ग्रामीण बस्तियों में कोई बस्ती बची है, जिनकी रोड कनेक्टिविटी नहीं है, उन बस्तियों में ?सड़क संपर्क योजना? के तहत सड़कों के निर्माण का प्रावधान इस बजट में किया गया है । आज मैं इस बजट के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं ।

?प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना? के माध्यम से 78 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को आर्थिक संबल प्रदान किया गया है । लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है । आज मैं इस सदन में कहता हूं कि अगर कोई गरीब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदान किए जा रहे आवास से वंचित है, तो इस बजट के माध्यम से फिर तीन करोड़ परिवारों को आवास प्रदान कराने काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार करेगी ।

माननीय सभापति महोदय, इस देश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से लोगों को सुविधाएं प्रदान की जा रही है । जब हम छिंदवाड़ा का चुनाव लड़ रहे थे, तो लोग कहते थे कि पता नहीं छिंदवाड़ा किसका गढ़ है । उस समय मैंने कहा था कि छिंदवाड़ा किसी का गढ़ है, तो वह माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के गरीब कल्याण योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है और भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक बहुमत से छिंदवाड़ा में विजय श्री हासिल कर वहां उस गढ़ को तोड़ने का भी काम किया है ।

इस देश में माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने गुड गवर्नेंस दी है । मैंने कहा था कि कांग्रेस के माननीय प्रधान मंत्री कहते थे कि इस देश में गरीब तक केवल 15 पैसे पहुंचते हैं, तब माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने जन धन एकाउंट्स खोल कर 51 करोड़ लोगों के लिए इस देश में यह व्यवस्था सुनिश्चित कर दी है कि अगर गरीब के खाते में एक रुपए भेजा जाता है, तो उनके खाते में 99 पैसे नहीं बल्कि एक रुपए ही पहुंचेगा । यह माननीय प्रधान मंत्री जी ने सुनिश्चित किया है । जब उन्होंने जन धन एकाउंट्स खोला था, तब वे मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि जब वर्ष 2014 में वे दलाल और बिचौलिए चले गए, तो उसके बाद देश में गरीबों को सुकून मिला है । डायरैक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 34 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थी के खातों में पहुंचाए गए हैं । आज मैं इस सदन में बजट भाषण में बताना चाहता हूं कि 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत भारत को डीबीटी के माध्यम से हुई है । इस देश में मोदी जी हैं । मोदी जी ने इस बात को भी मुमकिन करने का प्रयास किया है । हमारे विपक्ष के लोग अभी लगातार हंगामा करते रहे, वर्ष 2014 से पहले इस देश की सरकार भ्रष्टाचार के नाम से जानी जाती थी ।

15.00 hrs

मैं इस सदन में एक बात का और उल्लेख करना चाहता हूं । अखिलेश जी भी यहां पर बैठे हुए हैं । मैं बुंदेलखंड क्षेत्र का सांसद हूं । हमारे आज के नेता, प्रतिपक्ष वर्ष 2008 में टीकमगढ़ जिले के एक टिपरिया गांव की बहन भंजन बाई के घर गए थे । अभी वह उदाहरण दे रहे थे कि मैं इनसे मिला, मैं उनसे मिला । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब वर्ष 2008 में आपकी सरकार थी, वर्ष 2014 तक आपकी सरकार चली तो टिपरिया गांव की उस बहन भंजन भाई का इतने सालों में क्या हुआ था? आपको याद नहीं होगा, लेकिन आज मैं गर्व से कहता हूं कि उस बहन के सिर पर छत देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है ।

मैं नेता प्रतिपक्ष जी से कहूंगा कि आप बुंदेलखंड की गरीबी और सूखे पर अलाप करके आए थे । वर्ष 2014 के बाद मोदी जी की सरकार बनी । मोदी जी की सरकार ने बुंदेलखंड के लिए इस बजट के अंदर प्रावधान करने का काम किया है, इसलिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं । अटल जी का वह सपना पूरा करने का काम माननीय प्रधान मंत्री जी ने किया है । माननीय प्रधान मंत्री जी मोदी जी ने केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए 44,605 करोड़ रुपये पिछले बजट में प्रावधान करके बुंदेलखंड को दिये । आज मैं कहना चाहता हूं कि वह बुंदेलखंड अब सूखा बुंदेलखंड नहीं है । वह हरा-भरा बुंदेलखंड होगा । वह बुंदेलखंड अब गरीब बुंदेलखंड नहीं, बल्कि समृद्धशाली बुंदेलखंड बनेगा । जो लोग बुंदेलखंड का मजाक उड़ा रहे थे, आज आप वहां जाएंगे तो आपको सरपट हाइवेज मिलेंगे । बुंदेलखंड के खजुराहो का टूरिज्म बढ़ा है । आज इस सदन में मैं कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने बुंदेलखंड के क्षेत्र में जिस प्रकार से विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम किया है, हम आज माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं ।

हम देखते हैं कि आज़ादी के 70 वर्षों में 7 ?एम्स? ही खुल पाए थे, लेकिन आज मोदी जी ने देश के अंदर 23 ? एम्स? खोलकर भारत को स्वास्थ्य की सुविधाओं में अवसर दिया है । 387 मेडिकल कॉलेजेज की जगह 706 मेडिकल कॉलेजेज, मेडिकल की सीट्स ? जो डॉक्टर बनाने के लिए केवल 51 हजार थीं, आज देश के अंदर 1 लाख 7 हजार हो गई हैं । वर्ष 2014 में केवल 17 एयरपोर्ट्स थे, वह वर्ष 2023 में बढ़कर 148 हो गए हैं । बजट में प्रावधान करके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने इस बजट के माध्यम से देश के विकास की राह को और प्रशस्त किया है, इसलिए हम कहते हैं कि मोदी हैं तो मुमकिन है ।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब गरीब मां का बेटा देश का प्रधान मंत्री बनता है तो वह गरीब के दर्द को समझता है । इसलिए केवल भाषण देना, केवल न्यूसेंस की पॉलिटिक्स करना, केवल झूठ और छलकपट की राजनीति करने से यह देश नहीं चलेगा । मैं आज कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने बुंदेलखंड की जनता के लिए चाहे वह वन्दे भारत एक्सप्रेस हो, हाइवेज हो और चाहे टूरिज्म के अंदर गति देने का काम किया हो, बुंदेलखंड के अंदर अब औद्योगिकीकरण से लेकर स्वास्थ्य की सुविधाओं के साथ नेचुरोपैथी, योग तथा अध्यात्म का केन्द्र बनाने का काम भी माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के माध्यम से हमारे इस बजट के अंदर प्रावधान करने का काम किया है ।

महोदय, कांग्रेस की सरकारों के द्वारा वर्षों से उपेक्षित किसान और कृषि ? दोनों के विकास के प्रति आज मोदी जी की सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है । इस बजट में कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान करके किसानों के लिए, सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च समर्थन मूल्य की 1.8 लाख करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देकर किसानों के उत्थान के लिए अपना प्रतिबद्ध होने का वचन माननीय प्रधान मंत्री जी ने दिया है ।

आज मैं कहना चाहता हूँ कि भारत विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है । देश में 65 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु के लोगों की है । 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं की संख्या 38 करोड़ है ।

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please conclude now.

? (*Interruptions*)

श्री विष्णु दत्त शर्मा **:** वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प के प्रति 18 वर्ष की आयु के फर्स्ट टाइम के वोटर्स, 1.85 करोड़ हैं । इन नौज़वानों ने विवेकानन्द के आदर्शों पर चलने वाली नरेन्द्र मोदी जी की सरकार को आज इस देश में फिर से तीसरी बार चुनकर भेजा है । इसलिए आज मैं कहना चाहता हूँ, इस बजट के अन्दर, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, पाँच वर्षों में 8 करोड़ से अधिक रोज़गार के अवसर सृजित हुए हैं । वर्ष 2017 से 2024 के बीच 6 करोड़ 20 लाख सब्सक्राइबर्स ईपीएफ से जुड़े हैं ।

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please conclude now.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, seven or eight members from your party have also given their names. You have already exhausted your time. Please conclude within a minute.

? (*Interruptions*)

श्री विष्णु दत्त शर्मा **:** मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनन्दन करता हूँ कि इस बजट के अन्दर युवाओं के लिए दो लाख करोड़ रुपए का प्रावधान माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है ।

महोदय, 5 वर्षों में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को रोज़गार मिलेगा । यह बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का बजट है । इसलिए आज मैं इस सदन में कहना चाहता हूँ कि स्वामी

विवेकानन्द जी ने कहा था- ?मुझे कुछ ऐसे नौज़वान चाहिए, जो मेरे मन के अनुरूप हैं, तो इस देश का परिदृश्य बदल जाएगा ।? लेकिन आज इस बजट में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को जो ताकत दी है, मैं कहना चाहता हूँ कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के युवाओं से कहा था? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Shri Awadhesh Prasad.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member Shri Awadhesh Prasad, please carry on. Your mike is on. Nothing else will go on record.

? (*Interruptions*)*?* *

श्री अवधेश प्रसाद **(**फैज़ाबाद**) :** माननीय सभापति जी, मैं आपके प्रति बहुत ही आभारी हूँ कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया है ।

मान्यवर, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम की धरती, डॉ. राममनोहर लोहिया, आचार्य नरेन्द्र देव और अशफ़ाकउल्ला की शहीदी धरती से आया हूँ । मान्यवर, मैंने वित्त मंत्री जी द्वारा रखे गए 70 पृष्ठों के बजट को देखा । मैंने कई बार देखा, दूरबीन लगाकर देखा, लेकिन इसमें अयोध्या का नाम नहीं है, इसमें उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है । मान्यवर, यह वह अयोध्या है, यह प्रभु श्रीराम की मर्यादा की अयोध्या है, केवल अयोध्या में ही नहीं, बल्कि प्रभु श्रीराम की मर्यादा सारे देश-दुनिया में फैली है ।

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या के नाम पर राजनीति की है, व्यापार किया है । मैं आज बहुत ही दुखी मन से बोल रहा हूँ, मैं इस आदरणीय सदन में निवेदन कर रहा हूँ कि अयोध्या के नाम को, अयोध्या के विकास को पूरी तरह से नकारा गया है । ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं दलित जाति का हूँ । हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने मुझे एक सामान्य सीट से टिकट दी और 22 जनवरी से लेकर जब तक चुनाव हुए, वहाँ देश के कोने-कोने से अवधेश प्रसाद को हराने के लिए लोग आए, समाजवादी पार्टी को हराने के लिए, अखिलेश यादव के उम्मीदवार को हराने के लिए आए । लेकिन प्रभु श्रीराम की कृपा मेरे ऊपर थी, इसलिए जनता ने उनको नकार दिया है । मान्यवर, इसलिए नकारा है, क्योंकि वहां के लोगों को, जो प्रभु श्रीराम की प्रजा थी, श्री राम को बहुत प्यारी थी, उन लोगों को सताया गया है, उनके घरों को ढहाया गया है ।

मान्यवर, चाहे वह रामपथ का मामला हो, चाहे एयरोड्रम का मामला हो, चाहे अन्य निर्माण का मामला हो । लोगों के दो-दो पीढ़ियों के मकान को बुल्डोजर लगाकर ढहाया गया है । बच्चे चिलचिलाती गर्मी में रोते थे, महिलाएं रोती थीं, बुजुर्ग रोते थे । आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बुल्डोजर चलने के कारण घर ढहने से नगर में तीन लोगों की मौतें हुई हैं ।

मान्यवर, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से नकारा गया है । जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या में मंदिर निर्माण का आदेश दिया, तब बड़े पैमाने पर जमीनें खरीदी गईं, जमीनों में घोटाला किया गया ।

मान्यवर, एक जमीन ऐसी है, जो दो करोड़ की थी और दो घंटे के बाद उसे 18 करोड़ में बेचा गया है । ये खरीदने वाले कोई दूसरे नहीं हैं, वे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं । किसानों को बर्बाद किया गया है, तबाह किया गया है । इसीलिए, जनता आज पूरी तरह से नाराज है ।

मान्यवर, अगर किसी ने काम किया है, तो हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने किया है । उन्होंने मेडिकल कॉलेजेज़ बनाए हैं, सीवर लाइन्स बनाई हैं और बिजली के तारों को अंडरग्राउंड किया है । इन्होंने तो केवल अयोध्या की जनता को छलने का काम किया है ।

मान्यवर, हमारे यहां ?गुप्तार घाट? है, जहां निषाद लोग रहते हैं और भगवान राम को प्यारे हैं, निषादों की बस्ती को धराशायी कर दिया है और वहां पर दुकानें बनाई हैं । दुकानें किसको दी हैं? बड़े-बड़े करोड़पतियों को दुकानें दी हैं और निषाद समाज को बिगाड़ा-उजाड़ा गया है । आज वहां की जनता बहुत परेशान है ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस माननीय सदन के समक्ष कहना चाहता हूं कि वहां की जनता इतनी नाराज है कि वर्ष 2027 में जब चुनाव होगा, तब भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा और जब वर्ष 2029 में फिर चुनाव आएगा, तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा ।

हमारे नेता ने कहा है कि हम अयोध्या को ऐसा स्थान बनाएंगे, ऐसा शहर बनाएंगे कि दुनिया भर से लोग उसको देखने के लिए आएंगे, एक उदाहरण बनेगा, इन्होंने तो केवल चौपट किया है ।

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस सदन द्वारा एक कमेटी बना दी जाए और कमेटी इस बात की जांच करे कि कितना घोटाला हुआ है? जमीन किसने खरीदी है और निर्माण चाहे रामपथ में हुआ हो, चाहे हवाई अड्डे में हुआ हो, चाहे रेलवे में और जमीनों में हुआ हो । उसकी जांच कराई जाए और जांच की रिपोर्ट माननीय सदन के सामने रखी जाए । ?दूध का दूध और पानी का पानी? हो जाए । किस तरह से अयोध्या को ठगा गया है, उसको नकारा गया है, यह देश के सामने आ जाएगा ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूं कि आपने वर्ष 2024-2025 के बजट पर हो रही इस महत्वपूर्ण चर्चा में बोलने का मुझे अवसर दिया ।

हम तो उम्मीद करते थे, हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि भाइयों और बहनों, दो करोड़ नौकरी होंगी, 100 दिन में महंगाई कम होगी और किसानों की आमदनी दोगुनी होगी । बजट के 70 पेजों में यह कहीं नहीं है । ? (व्यवधान)

मान्यवर, मुझे कहना है कि एक बहुत बड़े शायर हैं, जिन्होंने साफ लिखा है, प्रसिद्ध शायर हैं श्री जावेद अख़्तर, उनका एक शेर है ?

?जीना मुश्किल है कि आसान ज़रा देख तो लो,

लगते हैं लोग परेशान ज़रा देख तो लो,

ये नया शहर तो है ख़ूब बसाया तुमने,

क्यों पुराना हुआ वीरान ज़रा देख तो लो ।?

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

? (*Interruptions*)

श्री अवधेश प्रसाद **:** मान्यवर, सिर्फ दो मिनट और दीजिए । अयोध्या का मामला है । ये नकार दें, लेकिन आपसे तो हम उम्मीद करते हैं ।

मान्यवर, यह सरकार पूरी तरह से दलित विरोधी है । एक बहुत बड़े विद्वान थे, वे वर्धा यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र के वी.सी. थे । उन्होंने डा. भीमराव अम्बेडकर पर रिसर्च किया है और उन पर एक अच्छी किताब लिखी है । उन्हें सस्पेंड करके नौकरी से निकाला गया जबकि वे देश में एक बड़े काबिल व्यक्ति हैं । अगर उनका कोई अपराध है तो यही है कि वे बस शिड्यूल्ड कास्ट में पैदा हुए ।

मान्यवर, यह वित्त मंत्री जी का बजट भाषण है और यह हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है । बजट भाषण जैसा कवर राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का होना चाहिए था, लेकिन यह क्या हो रहा है? इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है? यह अनुसूचित जाति के लिए एक मजाक है । राष्ट्रपति जी हमारे देश की गौरव हैं, लेकिन वे शिड्यूल्ड कास्ट हैं, हमारी कौम में पैदा हुई हैं । यह देश में चलने वाला नहीं है ।? (व्यवधान)

मान्यवर, हम अयोध्या से जीत कर आए हैं । इनका पूरे देश से सफाया हो जाएगा और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने कहा है कि हम अयोध्या को ऐसा स्थान बनाएंगे कि दुनिया के लोग उसे देखने आएंगे । इन्होंने तो व्यापार किया है, इन्होंने ठगा है ।

हमारे प्रधान मंत्री जी शिड्यूल्ड कास्ट के एक व्यक्ति के यहां चाय पीने गए थे और उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया हो जाएगा । हरिजन बिरादरी के यहां वे चाय पीने गए थे और कहा था कि बहुत अच्छा हो जाएगा, विकास हो जाएगा, पर आज उसे दिखवा लें, वह परिवार वैसा-का-वैसा ही है । इन्होंने अयोध्या को ठगा है, व्यापार किया है । इसकी जांच कराई जाए ।

मान्यवर, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

SHRI P. V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Thank you, hon. Chairman for letting me speak on this Budget. First of all, I would like to congratulate our hon. Finance Minister for assuming the charge once again.

Sir, coming to the issues of our State, I would like to say that a Special Category status was promised to us during the split of our State. It was promised by both the BJP and the Congress and all the other parties which were there at the time of split of our State. So, we demand that a Special Category status should be given to us.

I would also like to submit that we do not believe in this package that has been given. The package is like a myth. While giving this package, they are just talking about one or two things, which are part of the Andhra Pradesh Reorganization Act. We are not going to accept this package.

I would also like to remind to my friends from the Telugu Desam Party that they have been demanding a Special Category status for the State since 2019. I wish that they stick to the same stand. Keeping aside politics, we, the YSR Party is ready to work with all other parties, including the TDP for Special Category status in the interest of the State. We demand the Special Category status for our State. It should be replaced with the said package.

The hon. Finance Minister was talking about the Polavaram Project. It is true that the Polavaram Project is a lifeline for our State. We would like to know from the hon. Finance Minister, though it is a national project, why was execution of the project given to the State Government? What was the reason behind it? The NDA Government was in power. Giving the execution work to the State Government is a sort of a blunder for this project. The whole project has been messed up. It was accepted at 2014 rates, which is not at all acceptable. It is 10 years now. Who is going to bear the cost of escalation?

Sir, we would also like to bring to the notice of the House the blunder which happened in the construction of the diaphragm wall of the dam. For any dam to be built, whether upstream or downstream, there needs to be a cofferdam built. The purpose of the cofferdam is to prevent flood during the construction so that the main dam does not get affected. But what happened in the Polavaram Project? The diaphragm wall, which is the foundation of the main dam, was built without the cofferdam being completed. Thereby the flood eroded the whole diaphragm wall. If the project is built on the same diaphragm wall, it is going to affect the security and safety of the project, and it is going to lead to a huge catastrophe. I would like to know, since the diaphragm wall is damaged, who is going to bear the cost of diaphragm wall which has to be built parallelly, and which has to be constructed again? It is going to cost thousands of crores of rupees. Is the State going to bear this or the Centre going to bear this? We do not accept this being put as a burden on the people of our State.

We also demand that land acquisition for Polavaram Project be executed simultaneously along with the construction of the project. Any escalation in costs due to delays because of these blunders should also be borne by the Central Government. That is our demand.

The hon. Finance Minister announced that Rs. 15,000 crore are being given for the construction of Amravati. If this is a loan, who is going to bear this? What is the advantage for the people of our State? Is it a part of the FRBM limits given to our

State or is it over and above that? As of now, what we understand is that it is the amount collected by way of taxes from our people, What is the advantage that we are going to get from this amount of Rs. 15,000 crore? We appreciate any help being done to the State, but we demand that it should be in the form of a grant and not a loan.

Sir, we also want to know the timeline for Kadapa-Bangalore railway line. Now, the TDP and the BJP are in power in the State. We would like to know when the Kadapa-Bangalore railway line will be finished.

We also oppose the privatisation of Visakhapatnam Steel Plant. If we sell Visakhapatnam Steel Plant at this juncture without a proper iron-ore mine, there is no way justice will be done. We demand that iron-ore mines should be allotted for Visakhapatnam Steel Plant and the Government owns it. If iron-ore mines are allotted to Visakhapatnam Steel Plant, it will be highly profitable and a big asset for our country. We strongly oppose the privatisation of Visakhapatnam Steel Plant.

We also demand that whatever other promises have been made in the AP Reorganisation Act, they should also be fulfilled. It has been ten years since the promises were made and the tenure of AP Reorganisation Act is also over. We want to know what is happening for Visakhapatnam Metro and Kadapa Steel Plant.

There were also promises made in the form of ?Super Six? during the election. Since NDA is in power in our State, we would like to know the timeline for the execution of these ?Super Six? promises. We hope that ?Super Six? promises will not become ?Sorry Six? promises for our State. We wish and hope that the promises would be kept. It was promised that immediately after coming to power, all the ?Super Six? promises would be taken care of, but we do not find it happening. Apart from one promise, nothing else has been kept.

Sir, I would also like to bring to the notice of the House that without proper law and order, investments will not come to the State. For example, I have been prevented from going into my constituency. They attacked me. They burnt my vehicles. They destroyed my vehicles. The attack took place in full glare of all the TV channels. Finally, a case of attempt to murder was booked against me. After an attack happened on me, a reverse case was filed against me. Such is the law and order situation in the State. If the law and order situation is so bad in our State, how will investments come into our State? I demand from the Government that law

and order should be restored in our State, and all the violence should be put an end to.

I would request the Government not to cut down on the capital expenditure of Rs. 11 lakh crore for various other reasons.

I also demand that MSMEs should be given top priority because MSMEs contribute 33 per cent to our GDP and 45 per cent to our exports. They have huge issues in raising capital. They also have huge issues in regulatory compliances. So, if these things are taken care of, MSMEs will grow further, which will be good for the economy of our country. It is one of the major steps we need to take for achieving a $ 5 trillion economy.

I hope that the hon. Finance Minister will address all our concerns. With these words, I conclude my speech.

Thank you.

SHRI K. SUBBARAYAN (TIRUPPUR): Hon Chairperson Sir, Vanakkam. I wish to say some of my views on behalf of the Communist Party of India on the Budget for the year 2024-25. Some assurances are given in this Budget. The ruling dispensation has already not fulfilled the assurances given by them earlier. How can we believe their new assurances? They have not behaved in the last 10 years as trustworthy ones to believe. Neither have they fulfilled their promises. These new assurances are like befooling us once again as they did earlier.

This Union Government is talking time and again about progress and development. Where is progress? And where is development? WHO and UNICEF say that 74.1 per cent Indians are malnourished. If 3/4th of our population is malnourished, then where this development or progress is taking place? Is this ruling party trying to befool us?

The Economic Survey of India says that inflation is under control. But what is the real situation? This year July, inflation has been increasing more than 9.4 per cent. Price rise is again on the rise. If this Government talks about progress and development, it is just an eyewash and nothing else.

Bihar and Andhra Pradesh have been provided special funds and financial assistance. We welcome this. We welcome the help being extended to Andhra

Pradesh and Bihar. Have Andhra Pradesh and Bihar only asked for financial help during the elections? This help is not extended to these States in order to help them in the right perspective. In order to meet your cheap political aspirations, I want to say that this is a political stunt staged by you. This is not a help extended by them honestly. That is why, I would like to say that this help will be in such a fashion.

Today we have unemployment issues in our country. They are giving false hopes of fulfilling many aspirations. The MSMEs provide the maximum employment.

The MSMEs provide 30 per cent of employment. Who have given pressure to these MSMEs? This BJP is pro-monopolies. They support fully the corporate companies and the multi-national companies. Micro Small and Medium Enterprises are being affected due to their wrong policies. If we want to support the MSMEs, then the GST levied on them should be reduced. Their loans should be reduced or waived off.

I want to mention about agriculture. What is the contribution of agriculture to our GDP before 10 years? What is the contribution of agriculture to our GDP today? We urge that a White Paper should be presented by this Government on this issue.

What is the development that has taken place in agriculture? Rural areas are emptied. They are the ones who shattered the rural economy. They have really shattered our rural economy. Therefore, unemployment problems continue to rise.

Similar is the case with 100-Day Employment Scheme. I wish to stress that they are silently destroying the 100-day employment guarantee scheme. I want to make a request to the hon. Finance Minister and the ruling party that 100 days of work should be increased to 200 man-days of work under the MGNREGA Scheme. Similarly, daily wages should be increased from 100 days to 200 man-days. Daily wage should be not less than Rs. 500 per day. As a result of this guarantee, at least 33 crore people will be benefitted. Rural unemployment will be reduced.

The UPA Government introduced MGNREGA- a good Act, for providing work to the rural citizens, which should be implemented. I want to know the action taken in this regard by the hon. Finance Minister.

I also mentioned about this during the discussion on the Vote of Thanks to the hon. President?s Address to the MPs of both the Houses of Parliament. The MP?s MPLAD Scheme has an allocation of Rs 5 crore per annum. Out of which, Rs.90 lakh will be

collected as GST. Is there a basis to this? This is tax collection fund for the MPs to spend for the people of their constituencies allocated under the MPLAD Scheme. But GST is levied on this. Is there any estimation? Kindly ponder over this. After deduction of GST, it would be Rs 4 crore per annum. Only an amount of Rs 65 lakh can be provided to each Assembly Constituency. How can you fulfil the needs?

The hon. Chief Minister of Tamil Nadu Shri M.K. Stalin is giving Rs 4 crore as Local Area Development Fund to each Assembly Constituency in Tamil Nadu. Moreover, this has been exempted from GST. If we calculate MPLAD, it just comes to allocation of just Rs 65 lakh to each Assembly Constituency in an MP Constituency. I urge upon the hon. Finance Minister to provide Rs. 4 crore to each Assembly Constituency in a Parliamentary Constituency.

I urge that a reply to this be made by the hon. Finance Minister. Otherwise, you scarp this Scheme. We do not want this. If you want to make it effective, you should enhance the MPLAD amount.

I want to talk about the electoral bonds. I will finish my speech after talking about this issue of electoral bonds. The Union Government does not have any moral responsibility to talk about corruption. This is not my statement. This is the statement made by the hon. Supreme Court of India. It said that the amount collected through electoral bonds is illegal. I want to request the hon. Finance Minister to confiscate all the money collected illegally through electoral bonds, be it any party. I urge that such money should be taken to the Government treasury. Therefore, I request you, please do not talk about corruption.

I want to quote what our saints have said in Rig Veda. We want a knowledge which will not create enemies. But unfortunately, here the ruling party is fully aimed to create enemies. It is their full-time profession. This is their profession by tradition. They want to destroy the harmony in the country. Patriotic Indians are rather ready to destroy such evil acts. The primary duty of patriotic Indians is to remove the BJP from power.

Thank you, Vanakkam.

श्रीमती शताब्दी राय बनर्जी **(बीरभूम) :** सर, बजट ऐसी चीज है, जिसका देश के सभी लोग इंतजार करते हैं । गरीब यह सोचकर इंतजार करते हैं कि थोड़ा तेल के दाम कम हो जाएं, आलू के दाम कम हो जाएं, मेडिसिन्स के दाम कम हो जाएं और वे बच्चे, मां-बाप को थोड़ी अच्छी जिंदगी दे सकें । मिडिल क्लास यह सोचता है कि पेंशन

में कुछ टैक्स बेनिफिट हो जाए, कुछ बैंक का इंट्रेस्ट बढ़ जाए, कहीं पेट्रोल का दाम कम जो जाए, जिससे बाइक लेकर आफिस जा सके । अपर क्लास, जिनके पास बहुत पैसा है, वे सोचते हैं कि कॉर्पोरेट का जो लोन है, वह कैसे माफ हो और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से कैसे बैंक से पैसे लें और बाहर भाग जाएं ।

इस बजट में न बच्चे की बात की गई, न फार्मर्स की बात की गई, न देश की बात की गई । इसमें सिर्फ दो स्टेट्स की बात हुई । हम लोग जैसे पीपीपी मॉडल बोलते हैं, वैसे यह बजट बीबीबी है, मतलब बीजेपी बजाओ बजट । दो स्टेट्स को बचाने की चक्कर में यह बजट पेश किया गया ।

The failure of Government has always been covered by using past tense, and the long-term result has been pronounced by using future tense. On the ground, only tension and suffering of the people at the bottom stand unchanged.

An important question stands, did the Government undertake the actual impact assessment of the last budget? Certainly, the Government did not do it because of the following facts. Fact A: As on March 2023, the Global Nutrition Report by the World Health Organization says that 34.7 per cent of children under the age of five years are still affected, which is higher than the average of 21.8 per cent in the Asia region. India has made no progress towards achieving the target of removing malnutrition. Still 17.3 per cent of children under the age of five years are affected by malnutrition which is highest in the world. And, fact B: As per the Global Hunger Index, 2022, Report, child mortality rate in India was 3.3 per cent.

On these two unfortunate facts, we saw the development of two further unfortunate realities. First, the word ?children? remained absolutely absent from the hour-long Budget Speech. Second, the Ministry of Women and Child Development has seen a marginal increase of 2.5 per cent in its budget allocation for the financial year 2024-2025. In 2024, we have been told that the budget allocation on education has increased to six per cent of GDP. The drop-out rate in class 10 stood at 20.6 per cent in 2023. The Budget speech not only had no mention on primary or higher education, but also the allocation on education has merely increased by 0.74 per cent from the year 2023-24, which is below three per cent of GDP.

In February, 2024, before election, the focus was on GYAN - Garib, Yuva, Annadata and Nari. Besides the NITI Aayog?s report, many other study reports say that 'out of pocket' health expenditure is one of the primary causes of household financial problems, leading to poverty in low and middle-income groups. In July, 2024, GYAN lost the focus. The budget for health received only 1.7 per cent rise from the previous year, which is less than the allocation made in the interim Budget.

डायरेक्ट बेनिफिट्स कुछ नहीं है, इन्फ्रास्ट्रक्चर, जॉब क्रिएशन कुछ नहीं है । फ्लड्स वेस्ट बंगाल में नहीं होता है? हर साल फ्लड होता है । हम लोगों के चीफ मिनिस्टर नई जिन्दगी देते हैं, नया घर देते हैं, इसमें वेस्ट बंगाल के लिए कुछ नहीं है । रेल के बारे में कुछ नहीं, रेल में सेफ्टी और सिक्योरिटी का हाल ऐसा हो गया है कि अगर टिकट लिया और रेल का टिकट कन्फर्म हुआ तो एलआईसी एजेंट घर आ जाता है कि आप जाओगे तो वापस नहीं आओगे, रेल का ऐसा हाल हो गया है ।

हर स्टेट में कुछ न कुछ टूरिज्म है, जिसे आप सपोर्ट दे सकते हैं, जिसे प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं किया । आप कश्मीर के बारे में बात किया, क्या किया? जब अनुच्छेद 370 हटा तो पुराने एमपजी को याद होगा कि सेंट्रल हॉल में हम लोगों को कश्मीरी फूड देना स्टार्ट किया था । उस समय लगा था कि कश्मीरी फूड दे रहे हैं तो उसके लिए फीलिंग है, 370 हटा, लेकिन प्यार है । उसे प्यार-फीलिंग नहीं कहते, उसको हिपोक्रेसी कहते हैं, जो गवर्नमेंट ने किया था ।

जो एमपीलैड हम लोगों को मिलता है, एक असेम्बली क्षेत्र के लिए 70 लाख रूपये, जो अडानी-अम्बानी के एक महीने के ब्रेकफास्ट का पैसा है, वह डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं, हम कैसे डेवलप करें? अगर आप एमपीलैड नहीं बढ़ाएंगे तब भी हम लोग वोट लेकर आ जाएंगे । जो बीबीबी - बीजेपी बचाओ बजट पेश किया है । नेक्सट टाइम कभी देश बचाओ बजट भी करेंगे, इसी इंतजार और उम्मीद से मैं अपनी बात समाप्त करती हूं ।

ADV. FRANCIS GEORGE (KOTTAYAM): Sir, we are almost reaching the fag end of this discussion on Budget 2024. The hon. Finance Minister in her speech said that the focus of the Budget is on four major classes, that is, the poor, the women, the youth and the *annadata*, the farmer. She also said that the Government announced higher MSP a month ago for all major crops delivering on the promise of 50 per cent margin over cost to the farmers. The farmers are on the path of agitation again. The second farmers? agitation is going on, and they are detained at the border of Punjab and Haryana at Shambhu and Khanauri to prevent them from entering the capital city of New Delhi.

Sir, our annadatas are out in the sun and rain braving the brutality of the police and the paramilitary forces since February this year. The death toll of farmers is mounting.

As we all know, in the first farmer's agitation, more than 700 farmers lost their lives and they are still being treated like aliens and invaders. The Leader of the Opposition rightfully pointed out all this. What disservice has this hapless lot, who form more than 60 per cent of our population, done to this country? How can we treat them like this?

Sir, I would like to cite one instance. When the war in Afghanistan was over, that country was short of food grains, there was famine, hunger, and world over, almost many countries contributed food grains to help them. As good neighbours, we also

sent food grains to Afghanistan. The Taliban leadership said, out of the food grains, the wheat they got from all over the world, the best quality wheat was supplied by India. Who produced this best quality wheat? Is it the Government or the political class like us? It was these people who produced the best quality wheat which brought glory to our country. They are the ones who are out languishing at Shambhu and Khanauri at the border.

Sir, the Finance Minister spoke about a lot of programmes for the farming community. What are the farmers demanding? The farmers are demanding Minimum Support Price as per the C2+50 per cent, recommended by the National Commission on Farmers, headed by late Professor M.S. Swaminathan. They demand pension for farmers and agricultural workers. They are demanding waiver of farm debts. Unfortunately, the Budget is totally silent on all these aspects. The INDIA bloc, the Leader of the Opposition said, if we come to power, we will fulfil this C2+ 50 per cent formula, as promised by the NDA during all the elections they have won. They have not done anything, and in this Budget also they are not prepared to do anything.

Sir, when we look at the facts, from 2019-20 onwards, there is a decline in allocation for agriculture. It was 5.44 per cent in 2019-20. But when it comes to 2024-25, the allocation is only 3.15 per cent. The way the government helps the farmers, I would like to cite one more instance. Even as the Session is on, I am told about the India-Malaysia collaboration on palm oil and agriculture. An agreement has been signed by the hon. Agricultural Minister, Shri Shivraj Singh Chauhan, and the Minister for Plantations and Commodities of Malaysia, Mr. Abdul Ghani to deepen bilateral agricultural cooperation and especially a national mission on edible oil, oil palm. What is this surreptitious move? The Parliament is not being informed about this bilateral agreement between Malaysia and India? When we go through it, is this the way the Government helps our oilseed farmers? When I made enquiries, I could find that there is a company called Wilmar International Limited. It is having 83,000 acres of palm plantation in Malaysia. Now, Mr. Adani, has purchased 50 per cent stake of this company. Now, this Wilmar International is Wilmar Adani Limited.

From 2024 onwards, now the import duty is exempted. What was the import duty for edible oil? It was 44 per cent till 2023. Then 12 per cent was reduced, it was reduced to 32 per cent. Now, from 2024 April onwards, there is no duty at all for import of edible oil.

There is only an agricultural cess of five per cent. Now it goes out of the Custom?s control. It will affect our small, medium and the coconut farmers in Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, and in all the Southern States. Also, in Bundelkhand area in UP and Madhya Pradesh where all other oilseeds are being grown, our small, medium and marginal farmers are going to be affected. The Government is not at all bothered.

The Kerala Government has made some demands before the Finance Minister, before the Union Government. Kerala is in a very serious financial crisis. Kerala seeks a special package of Rs.24,000 crore to tide over the financial crisis. The State is not even able to pay salaries and pensions properly due to the financial crisis it faces. This is not like a bonanza which has been given to Andhra Pradesh or Bihar. We will be paying this back. But to tide over the crisis, we have asked for a special package of Rs.24,000 crore. The Finance Minister is mum on this.

Regarding the GST revenue sharing, instead of the 50:50 formula, we have demanded 60:40 revenue sharing, that is, 60 per cent to the States and 40 per cent to the Centre. I mean it does not benefit Keala alone. It will benefit all the States.

We have demanded for giving special assistance to the Vizhinjam Port. The Vizhinjam Project is not only for Keala but this is the country?s flagship project also. I need not say that it will be of great benefit to the country. We have demanded only Rs.5,000 crore in this regard by raising the borrowing ceiling to 3.5 per cent from the three per cent limit of the GSDP.

The All India Institute of Medical Sciences is a long-promised project to Kerala. No final announcement has been made in this regard. We expected that the Finance Minister will announce it in the Budget. The Centre has declared a project called the National Industrial Corridor Development Programme of the Government of India under which the Kochi-Bengaluru Industrial Corridor was taken up. Kerala has put up one project, namely, Global City in Kochi as part of this particular project. Nothing has been done. Now, we are being told that this entire project is being withdrawn.

Then I come to the Medical Devices Park at Thonnakkal in Thiruvananthapuram District. This is a very vital area where we are importing all these devices. If we can start this particular Park, we can avoid the import.

Last but not least is rubber which is a strategic crop. We have sought MSP of Rs. 250 per kilogram for rubber. Now the ASEAN Multilateral Agreement is being

renegotiated, and it is going to be renewed. Rubber has been put as an industrial raw material. We demand that it has to be brought back to the agricultural list. Then only we can have all the benefits that other agricultural commodities get from the Agriculture Ministry.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

ADV. FRANCIS GEORGE: Sir, I am just concluding. The import duty on gold and silver has been reduced from 15 per cent to six per cent. That is a good move. We hope that it will curtail smuggling. But something more has to be done in this particular sector because the IT Act says that the gold traders have to collect a copy of the PAN card of the customers who make purchases worth Rs.2 lakh and more. Now, at the present rates, Rs.2 lakh means only 30 grams can be purchased. It will create a lot of practical problems. Also, the limit shall be raised to Rs.5 lakh. It is also estimated that 15 per cent of the total gold deposit, which comes to about 30,000 tonnes, is in India, and also about 800 to 1000 tonnes are being imported every year. If the Government starts a gold deposit bond scheme, thereby if 10 per cent of this accumulated stock can be brought in the market, there would not be any need for import which will boost our foreign exchange.

The Government should direct the banks to restart the Agriculture Gold Loan Scheme at four per cent interest rate, which was of great help to the small, ordinary, medium farmers and the general public. That has been now totally stopped. Only the Gramin Banks operate it now. I would request the Finance Minister to give immediate instructions to all the public sector banks and the scheduled commercial banks to restart this programme.

Coming to the Employees? Provident Fund Pension Scheme, it is so unfortunate that the total collection from the PF contribution is Rs.12 lakh crore. The accumulated Pension Fund is Rs.7,80,388 crore, but the average pension given is only Rs.784.

HON. CHAIRPERSON: Please wind up your speech.

ADV. FRANCIS GEORGE: I request the Finance Minister to immediately raise this to at least Rs. 9,000 or Rs.10,000. About Rs.7,80,308 crore is there. But these poor people are being given only Rs.784 as pension.

Why have the States to go for this kind of special packages? The 16th Finance Commission has started its work. The 14th Finance Commission raised the State

share of net proceeds from 32 per cent to 42 per cent. Then, what did the Centre do? The Centre raised the cesses and surcharges to circumvent this by raising this 10 per cent devolution to the States.

There is no official publication which provides annually the aggregated estimates of the net proceeds or net divisible pool, the total amount of cesses and surcharges collected by the Union Government and the total collection of taxes is being decided like this.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now. Otherwise, I will be compelled to take the name of the next speaker.

ADV. FRANCIS GEORGE: Sir, I am concluding. This is a very vital issue. According to Article 79, net proceed means any tax or duty the proceeds thereof reduced by the cost of collection. We have to understand this.

The Seventh Schedule of the Constitution gives greater powers to the Union Government to collect direct and indirect taxes than the States. But larger proportion of spending responsibilities lies with the States. According to the 15th Finance Commission, when the States incurred 61 per cent of the total revenue expenditure, they collected only 38 per cent of the total revenue receipts. This is the reason why the States have to seek special compensation or special packages.

Sir, since the 16th Finance Commission has started its work, I hope that more funds will be devolved to the States so that they can recover or they can compensate their financial crises which they are facing.

HON. CHAIRPERSON: Please summarise your speech.

ADV. FRANCIS GEORGE: Sir, there are a lot of issues.

HON. CHAIRPERSON: But how can I accommodate the time? You have to decide your points.

ADV. FRANCIS GEORGE: Sir, I am concluding. So, I hope the Finance Minister will reconsider all these things and help a State like Kerala in overcoming from its financial crisis.

On the unemployment issues, this morning, the concerned Minister was stressing on generation of employment in this country. But the rate of unemployment today is at a high and severe level. According to the Centre for Monitoring Indian

Economy, it was 9.2 per cent in June, 2024. Among the degree holders, it is 40 per cent. Only 20.9 per cent workers have regular income. This is the situation of our country.

So, I hope more and more funds will be allotted to the States so that they can survive their financial crisis which they are facing, especially the State of Kerala. I thank you for giving me the time.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री**;** तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री **(**श्रीमती अनुप्रिया पटेल**) :** धन्यवाद सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो माननीय वित्त मंत्री जी को निरंतर सातवीं बार देश का बजट प्रस्तुत करने के लिए बहुत बधाई देती हूं और विकसित भारत की राह को प्रशस्त करने वाला बजट प्रस्तुत करने के लिए उनका अभिनन्दन भी करती हूं । देश ने तीसरी बार लगातार 62 वर्षों के बाद हमारी सरकार को चुना है, इसलिए आम जनमानस की उम्मीदें भी 3 गुना हैं । माननीय वित्त मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहती हूं कि इस देश को तीसरे कार्यकाल में जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए तीन गुना तेज गति से काम करने वाला बजट उन्होंने देश को सौंपा है ।

महोदय, हालांकि मेरे विपक्ष के मित्रों ने कहा कि यह कुर्सी बचाओ बजट है, यह एनडीए का बजट है, यह भारत का बजट नहीं है । मैं विपक्ष के अपने मित्रों को कहना चाहती हूं कि यह एनडीए का बजट है और यह भारत का बजट है, क्योंकि भारत ने एनडीए को चुना है, आपको नहीं चुना है और भारत ने एनडीए को तीसरी बार लगातार चुना है ।

महोदय, एनडीए को इसलिए चुना है, because NDA is of the people, by the people, and for the people of Bharat. मैं जानती हूं कि आप इस बात से सदमे में हैं । आपने बहुत सारी अफवाहें फैलाईं, बहुत सारा भ्रम फैलाया, लेकिन फिर भी तीसरी बार देश ने मोदी जी के नेतृत्व पर ही मुहर लगाई है और एनडीए को ही चुना है । अब आप यह मान लीजिए कि एनडीए का बजट भारत का बजट है । आप जो बार-बार एनडीए सरकार के कोलैप्स होने के सपने देखते रहते हैं, ये आपके मुंगेरीलाल के हसीन सपने कभी पूरे नहीं होने जा रहे हैं । हमारी सरकार पूरे पांच साल चलेगी और तीन गुना तेज गति से अपने तीसरे कार्यकाल में अपने सारे कमिट्मेंट्स पूरा करेगी, जो वादे हमने देश से किए हैं ।

सभापति महोदय, मैंने अभी माननीय एलओपी का भाषण सुना । मुझे लगा बजट भाषण होगा । बजट भाषण में, बजट के अलावा सब कुछ था, केवल बजट नहीं था । बजट की हलवा सेरेमनी का चित्र भी था, उसका भी उल्लेख था । कास्ट सेंसस का भी उल्लेख था । सब कुछ था, बस बजट नहीं था । मैं एलओपी को और विपक्ष के मित्रों को सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं? (व्यवधान) मैं अभी बजट पर बात करूंगी । आप सुन तो लीजिए । ? (व्यवधान) आप बिल्कुल सुनिए । अभी आप धैर्य रखिए । मैं सब बातों का जवाब दूंगी ।

सभापति महोदय, देश में सबसे लंबे समय तक कांग्रेस और यूपीए की सरकार रही है । अगर अपने कार्यकाल में, अपने बजट की हलवा सेरेमनी के चित्र की कमियों की चिंता की होती या कास्ट सेंसस की चिंता की होती तो आज आप जो कह रहे हैं, इस देश के एससी, एसटी, ओबीसीज को आपकी चिंता जायज नजर आती । लेकिन,

आज जब आप सत्ता से बाहर होने पर यह चिंता व्यक्त करते हैं तो देश का एससी, एसटी और ओबीसी समझता है कि आपकी यह चिंता केवल सत्ता में वापस आने की व्याकुलता से अधिक और कुछ भी नहीं है ।

सभापति महोदय, अब मैं बजट पर आती हूं । हमारी सरकार ने देश के किसान, देश के युवा, देश की महिला, देश के गरीब, देश के मिडिल क्लास, इन सबको अपनी प्राथमिकता में रखा है । मैं बात अगर कृषि की करूं तो हमारी सरकार ने 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है । कुछ महत्वपूर्ण बातें, जलवायु परिवर्तन आज देश और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है । ऐसी परिस्थिति में हमें टिकाऊ कृषि की जरूरत है । इसलिए, हमारी सरकार ने 109 किस्म की नई किस्मों को लाने की बात की है, जो प्रतिकूल मौसम की परिघटनाओं का सामना कर सकती हैं और कृषि को टिकाऊ बना सकती हैं । इसके साथ ही नैचुरल फॉर्मिंग की बात है,

आज यह वर्तमान समय की और आने वाले भविष्य की जरूरत है कि हम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें । हम मिट्टी की सेहत का ख्याल करें और देशवासियों की सेहत का भी ख्याल करें । हमारी सरकार ने इस बजट में टिकाऊ कृषि के साथ-साथ देश की खाद्य सुरक्षा बढ़ाने पर भी ध्यान दिया है । मेरे विपक्ष के मित्र, जो यहां बैठे हुए हैं, इनमें से कौन असहमत होगा कि आज देश को नैचुरल फॉर्मिंग की जरूरत नहीं है या देश को ऐसी फसल की किस्मों की जरूरत नहीं है, जो मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों में टिकी रहे । क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं कि आज हमारी दलहन और तिलहन के लिए जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है, उसको हमें कम करना चाहिए और अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करना चाहिए । हमारी सरकार ने ये तमाम प्रयास इस बजट में किए हैं । इसलिए, यह किसानों की भलाई का बजट है ।

सभापति महोदय, जहां तक विषय एमएसपी का है तो अनेक नई फसलों को एमएसपी के दायरे में लाने का काम हमारी सरकार ने दस सालों में किया है ।

16. 00 hrs

आपने यूपीए सरकार के 10 सालों में एमएसपी पर जो खरीद की थी, वह महज 45 करोड़ मीट्रिक टन फसलों की थी, जबकि हमारी सरकार ने पिछले 10 सालों में 70 करोड़ मीट्रिक टन फसल की खरीद एमएसपी पर करने का काम किया है । इसलिए संसद के फ्लोर से देश के किसानों को गुमराह करने का काम बंद होना चाहिए । सभापति महोदय, हमारी सरकार की प्राथमिकता में देश के युवा हैं । बजट पेश होने से पहले इकोनॉमिक सर्वे आया, उसमें दो महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं । पहली यह है कि हमारे देश के कॉलेजेज़ से हर साल जो ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, उसमें 51 प्रतिशत से कुछ अधिक ऐसे हैं, जो एम्प्लॉयेबल नहीं हैं, नौकरी पाने योग्य नहीं हैं । इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि आज उद्योगों को जिस स्किल सेट की आवश्यकता है, वह हमारे युवाओं के पास नहीं है । इसके साथ ही तमाम ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ और इकोनॉमिक डिप्रेशन की परिस्थितियों के बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था जिस तेज गति से आगे बढ़ रही है, उसको देखते हुए एवं उससे तालमेल बिठाते हुए हमें रोजगार सृजन करने की आवश्यकता है । ये दो बातें इकोनॉमिक सर्वे में कही गई हैं ।

हमारी सरकार ने जो बजट पेश किया है, उसमें इन दोनों बातों का ध्यान रखा है । सरकार ने युवाओं की स्किलिंग और युवाओं के रोजगार के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है । ?एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेटिव स्कीम? के तहत तीन योजनाएं लाई गई हैं । मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझसे पहले बहुत सारे वक्ता उसकी चर्चा कर चुके हैं । यह एक कोशिश है कि प्राइवेट सेक्टर को रोजगार के नज़रिए से सरकार कैसे मदद करेगी । स्किलिंग के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार और इसके साथ ही साथ हमारा प्राइवेट सेक्टर

20 लाख युवाओं को स्किलिंग करने जा रहा है । इसके लिए हमारे 1,000 से ज्यादा आईटीआईज़ को अपग्रेड किया जाएगा, ताकि युवाओं को उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप हम स्किल सेट दे सकें ।

सभापति जी, आज इंडस्ट्रीज़ के पास स्किल्ड लेबर्स की शॉर्टेज़ है । आईटीआईज़ के माध्यम से हम जिन ट्रेड्स में स्किलिंग देते हैं, जैसे फिटर है, प्लंबर है, कारपेंटर है, इलेक्ट्रीशियन्स हैं, बहुत सारे सेक्टर्स और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में इनकी भी आवश्यकता पड़ती है । स्किलिंग के साथ-साथ हमारी सरकार ने एक महत्वपूर्ण इंटनर्शिप योजना का ऐलान किया है, जिसमें देश की टॉप 500 कंपनियों में 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को हम इंटर्नशिप की सुविधाएं देंगे । ऐसा इसलिए है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं । बहुत सारे सक्सेज़फुल बिजनेस लीडर्स अपनी कंपनीज़ में इंटर्न्स के रूप में शुरुआत करके आगे बढ़े हैं, क्योंकि उसके लिए जो जरूरी एक्सपोजर या एक्सपीरियंस है, उनको अपनी कंपनीज़ में काम करते हुए मिला है । ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, रियल स्टेट, इन्फ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, रिटेल, लॉजिस्टक इत्यादि, जिसमें आज लेबर डिमांड सप्लाई का मिसमैच है और एक स्किल गैप है, जिसको भरने की एक कवायद ये इंटर्नशिप योजना है । इसलिए हमारे विपक्ष के मित्रों को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि टॉप 500 कंपनीज़ में इंटर्नशिप का अवसर देश के युवाओं को मिले ।

सभापति महोदय, अब मैं ?पूर्वोदय योजना? का जिक्र करना चाहूंगी । देश का संतुलित विकास एक गंभीर चिंता का विषय है, यह आज से नहीं, बल्कि बहुत लंबे समय से है । हमारी सरकार ने देश के समग्र, संतुलित, सर्वस्पर्शी विकास पर सदैव बल दिया है । ?पूर्वोदय योजना? के तहत हमारे देश के पूर्वी हिस्से में जो पांच राज्य हैं ? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश । ये पिछड़े राज्य हैं, विकास की मुख्य धारा से वंचित हैं ।

हमारी सरकार ने इस योजना के माध्यम से इन राज्यों की चिंता की है, जो पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी नहीं की थी, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है । हां, ये जरूर है कि इसमें हमारी सराकर ने पांचों राज्यों की चिंता की है, लेकिन दो राज्य - बिहार और आंध्र प्रदेश को लेकर हमारे विपक्ष के साथी थोड़ा उत्तेजित भी हुए हैं । उन्होंने कहा कि इनकी थाली में तो बहुत कुछ आ गया है, बाकी राज्यों को तो कुछ नहीं मिला है, जबकि इस योजना के तहत पांचों राज्य लाभान्वित किए जा रहे हैं ।

सभापति महोदय, क्या आंध्र प्रदेश और बिहार देश का हिस्सा नहीं है? मैं यह सवाल विपक्ष के साथियों से पूछना चाहूंगी । मैं यह भी कहना चाहती हूं कि आंध्र प्रदेश का विभाजन तो यूपीए सरकार के दौरान हुआ था । एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जिस राज्य को जो मदद मिलनी चाहिए थी, वह आपको देनी चाहिए थी, लेकिन आपने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया । वह हम कर रहे हैं । आंध्र प्रदेश का जो ज्यादा विकसित हिस्सा था, वह तेलंगाना के साथ चला गया । आंध्र प्रदेश को अपनी नई राजधानी सेट अप करने के लिए केंद्र की मदद की जरूरत है और केंद्र कर रहा है । आप जो काम अधूरा छोड़ कर गए थे, हमने वह कर दिया है । बिहार के झारखंड से अलग होने के बाद तमाम रिपोर्ट्स बताती हैं कि वह कितना पिछड़ गया है । उसकी वित्तीय परिस्थितियां बेहतर नहीं है । हम उसको सुधारने के लिए अपने राज्य की मदद कर रहे हैं । आपकी नजरों में बिहार और आंध्र प्रदेश अलग हो सकता है, लेकिन हमारे लिए नहीं है । आप भारत जोड़ो की बात करते हो और देश को टुकड़ों-टुकड़ों में देखते हो । हम देश को टुकड़ों-टुकड़ों में नहीं देखते हैं । हम अपने पूर्वी क्षेत्र के पांचों राज्यों को इस योजना के तहत लाभान्वित करने जा रहे हैं ।

अब मैं प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना का उल्लेख करना चाहती हूं । यह ऐसी योजना है, जिसके तहत देश के 63 हजार गांवों में पांच करोड़ जनजातीय समुदाय लाभान्वित होने जा रहा है । जनजातीय समाज की आबादी हमारे पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड, इन सभी राज्यों में है । क्या इस योजना का लाभ इन राज्यों

की जनजातीय आबादी को नहीं मिलना चाहिए? मैं यह विपक्ष के मित्रों से पूछना चाहती हूं । हमारी सरकार का बजट पूरे देश के हित में है, चाहे युवा हो, जनजातीय हो, किसान हो, महिला हो या गरीब हो । इसमें महिलाओं के लिए तीन लाख करोड रुपए का प्रावधान किया गया है । देश की इकोनॉमी आज 5 वें नंबर पर है और हम इसे तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने के लिए संकल्पित हैं । यह तब तक नहीं हो सकता है, जब तक हमारे देश के श्रम बल में, हमारे देश की वर्क फोर्स में देश की आधी आबादी की प्रतिभागिता न हो । हमने तीन लाख करोड़ रुपये का प्रावधान महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए किया है । महिलाओं के लिए वर्किंग वूमेन हॉस्पिटल्स, क्रैच्स, प्रॉपर्टी खरीद के नाम पर स्टाम्प शुल्क को कम करना, ऐसे तमाम प्रयास किए गए हैं । हमारे दस वर्षों के कार्यकाल में भी किए गए हैं । वूमेन लेड डेवलपमेंट की स्कीम पर हमारी सरकार ने काम किया है । हमारी तमाम ऐसी योजनाएं हैं, जो महिलाओं को केन्द्रित करके ही बनाई गईं, उनमें चाहे शौचालय का निर्माण हो, चाहे उज्ज्वला गैस का कनेक्शन हो, चाहे जल जीवन मिशन हो । ऐसी बहुत सारी योजनाओं ने महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव किया है और हमारे सारे प्रयास उसी के कंटीनुएशन में हैं । हमारी सरकार ने इस बजट के माध्यम से तय किया है कि 25 हजार ऐसी नई ग्रामीण बसावटें हैं, जिनको प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत संपर्क मार्ग से जोड़ने काम करेंगे । गरीबों को उनका आशियाना मिले, इसकी चिंता लगातार तीसरे कार्यकाल में भी बनी हुई है । तीन करोड़ नए आवास, जिनमें से एक करोड़ शहरी क्षेत्र में और दो करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में हमारी सरकार ने बनाने का संकल्प लिया है ।

सभापति महोदय, जो कामगार हैं, उनके लिए भी पीपीपी मोड पर हम किराए के घर का प्रावधान कर रहे हैं, यानी गरीब की चिंता भी इस बजट में स्पष्ट रूप से माननीय वित्त मंत्री जी ने की है। इसके साथ ही 25 करोड़ गरीबों को हम गरीबी रेखा से बाहर निकालकर लाए हैं तो वह इसलिए संभव हुआ है, क्योंकि हमने गरीबी मिटाने के प्रयास पूरी ईमानदारी से किए हैं, जो आप नहीं कर पाए थे । आप गरीबी हटाओ का नारा देते रहे, लेकिन आपके आंकड़ों में गरीब कभी भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाया, किंतु महज दस वर्षों में हमने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर निकाला है । हमने उनको मल्टी डाइमेंशनल पावर्टी से बाहर निकालकर दिखा दिया है और पांच साल बाद बढ़े हुए आंकड़े लेकर इसी पार्लियामेंट में आपके सामने आएंगे । वर्ष 2030 तक सात करोड़ के लगभग, यह आंकड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, देशवासी जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में बस रहे हैं, ये बड़ी संख्या में बसेंगे और इनका जीडीपी कंट्रीब्यूशन 66 प्रतिशत है । विकसित भारत बनाना है तो हमारी शहरी आबादी का और भी कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बढ़ेगा । 80 प्रतिशत से भी अधिक हो सकता है । इसलिए जरूरी है कि हम अपने शहरों का उचित विकास करें, उनको ग्रोथ हब्स बनाएं और उनके लिए भी 30 लाख से अधिक आबादी के सौ ऐसे शहरों को, जो तमाम आधुनिक सुविधाएं हैं, चाहे जल आपूर्ति की हो, सीवेज ट्रीटमेंट की हो, सॉलिड वेस्ट मेनेजमेंट की हो, इसको बढ़ावा देने की बात माननीय वित्त मंत्री जी ने की है ।

इसके अलावा हेल्थ सेक्टर का बजट 12.9 प्रतिशत बढ़कर अब 90958 करोड़ रुपये का हो चुका है । सात हजार करोड़ रुपये की इसमें वृद्धि हुई है । कैंसर के मरीजों के लिए, चूंकि इनकी संख्या हर वर्ष ढाई प्रतिशत बढ़ रही है । पिछले वर्ष भी हमने 15 लाख के करीब कैंसर केसेस देखे और ओरल कैंसर, लंग कैंसर, ब्रैस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर काफी तेजी से देश में बढ़े हैं । इसके लिए हमने कैंसर के मरीजों के लिए भी बजट में सौगात दी है और तीन ऐसी दवाएं हैं, जिन पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर दाम कम किए हैं ताकि सस्ता और सुलभ इलाज देश की जनता को उपलब्ध हो सके ।

सर, बातें बहुत सी हैं, लेकिन समय कम है, इसलिए मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का, देश को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का और देश को वर्ष 2047 तक

विकसित भारत बनाने का एक रोडमैप प्रस्तुत किया है, जिसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूं । ? (व्यवधान) उत्तर प्रदेश को इस बजट की एक-एक योजना का लाभ मिलने जा रहा है । ? (व्यवधान) आप चिंता मत कीजिए । उत्तर प्रदेश की चिंता आपने कभी नहीं की है । इसीलिए आप सत्ता से बाहर हैं । ? (व्यवधान)

श्री वरुण चौधरी **(**अम्बाला**) :** धन्यवाद सभापति महोदय ।

महोदय, आपके माध्यम से पहली बार मुझे इस सदन में बोलने का मौका मिल रहा है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । मैं अपने नेताओं का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अम्बाला लोक सभा क्षेत्रवासियों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे यहां चुनकर भेजा है ।

महोदय, बजट में बहुत सी बातें हुईं । विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है । यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज तक उसका कोई रोड मैप जारी नहीं हुआ है । इस सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया । जिसमें जवाबदेही थी, बताना पड़ता था, जमीन पर कुछ काम करना पड़ता था । 25 वर्ष की योजना चलायी गयी है ताकि न कोई पूछने वाला रहे और न कोई बताने वाला रहे ।

सर, हरियाणा प्रदेश से केन्द्र सरकार में तीन-तीन मंत्री होने के बाद भी पूरे के पूरे बजट में हरियाणा का नाम तक नहीं है । यह बहुत दुख की बात है । हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बैठाने की बातें हुई थीं । यहां चर्चा भी हुई कि किस तरह से कितनी-कितनी महंगी टिकटें मिलती हैं । आम आदमी तो छोड़िए, ठीकठाक आदमी भी जहाज में नहीं चढ़ पा रहा है । हालत यह हो गयी है कि हरियाणा में हमारी चलती हुई पैसेंजर ट्रेन्स को भी बंद कर दिया गया है । आम आदमी आज पैसेंजर ट्रेन में भी नहीं चढ़ सकता है । हरियाणा प्रदेश में नया कारखाना तो क्या लगना था, चले-चलाए कारखाने भी बंद हो गए हैं । हमारा पिंजोर में एचएमटी का बहुत बड़ा कारखाना बंद कर दिया गया है । बहुत समय से मांग आ रही है कि यमुना नगर से चंडीगढ़ वाया नारायणगढ़ रेल चलनी चाहिए, उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । हरियाणा के गांवों और शहरों में पानी के निकासी की समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन उस पर भी कोई बात नहीं की गयी है । टैक्स तो लिया जाता है, लेकिन सुविधा कुछ नहीं मिलती है । सर, इस तथाकथित अमृतकाल में युवा देश छोड़कर जा रहे हैं । जिस देश का युवा ही देश में नहीं रहेगा, वह देश कैसे विकसित होगा । अपराध, महंगाई, बेरोजगारी और नशा बढ़ता जा रहा है ।

हमारे हरियाणा प्रदेश में आए दिन गोलियां चलती हैं, फिरौतियां मांगी जाती हैं । आज यह हाल है कि हरियाणावासी और उनके साथ पूरा देश यह कह रहा है कि अमृतकाल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है । आमजन के लिए यह अमृतकाल नहीं है । अभी ?स्किल इंडिया? की बात हो रही थी कि 20 लाख लोगों को अगले पांच सालों में प्रशिक्षण दिया जाएगा । इसी तरह की बात वर्ष 2015 में भी की गई थी, तब टारगेट 30 करोड़ का था कि सात सालों में 30 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा ।

सर, जनता जानना चाहती है, हरियाणावासी जानना चाहते हैं, देशवासी जानना चाहते हैं कि वह पिछले वाला जुमला था या यह इस बार वाला जुमला है? किसानों की आय दोगुनी करने की बात हुई थी और यहां एमएसपी की गारंटी भी नहीं दी जा रही । एमएसपी की गारंटी पर भी बात नहीं कर रहे हैं । दो करोड़ नौकरियां देने की बात थी । 10 लाख नौकरियां तो केन्द्र सरकार के कार्यालयों में खाली पड़ी हैं, उनको भरने की कोई बात नहीं है । एससी/एसटी वर्ग का बैकलॉग सालों साल से खाली है, उसको भरने की कोई बात नहीं है और जब हमारे साथियों द्वारा सवाल लगाकर पूछा गया तो उसका ठीक से जवाब तक नहीं दिया गया ।

सर, हर सिर पर छत आने की बात वर्ष 2022 तक पूरी होनी थी और अब कह रहे हैं कि अगले पांच सालों में तीन करोड़ घर बनाए जाएंगे । हर सिर पर छत तो वर्ष 2022 तक ही आ जानी थी तो यह इस बार वाला जुमला

है या पिछली बार वाला जुमला था? सेस और सरचार्ज एक्सपोन्शली बढ़ते जा रहे हैं, जिसका डेवलूशन नहीं होता है । 15 वें फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि 41 प्रतिशत डेवलूशन होना चाहिए । सेस और सरचार्ज के कारण केवल 32 प्रतिशत ही डेवलूशन हो रहा है, जिससे राज्य सरकारों का, खास तौर पर जो विपक्ष की राज्य सरकारें हैं, उनका गला घोंटा जा रहा है । मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है कि सेस और सरचार्ज को भी डिवॉल्व करना चाहिए ।

सर, इसी बजट के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफैयर्स द्वारा 62 हजार करोड़ रुपये की डिमांड की गई है और यह किस नाम से की गई है ? नई योजनाओं के नाम से । उन नई योजनाओं की कोई जानकारी ही नहीं है कि वे कौन सी नई योजनाएं हैं । क्या इस सदन को यह जानकारी नहीं देनी चाहिए कि 62 हजार करोड़ रुपये किन योजनाओं पर खर्च होंगे? इसकी कोई जानकारी नहीं है?

16.19 hrs (Shri P. C. Mohan, *in the Chair*)

सर, बात होती है कि हम तीसरे नम्बर की जीडीपी पर अपने देश को लेकर जाएंगे और साथ ही यह नहीं बताया जाता है कि आज हम जीडीपी पर कैपिटा में 144 वें स्थान पर हैं । हम हंगर इंडेक्स में 111 वें स्थान पर हैं । पूरे विश्व में हम चाइल्ड वेस्टिंग दर में सबसे नीचे हैं । 80 करोड़ से अधिक लोगों को अन्न दिया जाता है । जैसा कि हमारे नेता श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने भी मांग की थी कि ये वे लोग हैं, जो स्वाभिमानी हैं, देश के नागरिक हैं, वे भी काम मांगते हैं, जिससे उनको भी वेतन मिले । हरियाणा के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी तो हुड्डा साहब मुख्य मंत्री थे । उस समय हर वर्ग का ध्यान रखा गया था और आज यह हाल है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपनी बात रखना चाहता है तो उस पर डंडे चलाए जाते हैं । लोगों की बात नहीं सुनी जाती है । ये हाल है कि महीनों-महीनों तक हमारे कर्मचारी धरने पर रहते हैं, लेकिन उनकी कोई बात सुनने नहीं जाता है । अभी चर्चा हो रही थी कि हमारे किसान बॉर्डर पर बैठे हैं ।

सर, यह देश हमारा है । किसान देश के ही नागरिक हैं । वे अपने देश की राजधानी में नहीं आ सकते हैं, ये हालात हैं । आपको उनकी बात सुननी चाहिए, हल निकालना चाहिए, लेकिन यह तानाशाही है और हम तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं । एमएसपी की लीगल गारंटी के लिए बार-बार बात उठ रही है, लेकिन उस पर सरकार का कोई बयान नहीं है ।

सर, आखिर में मैं यही कहूंगा:

हम होंगे कामयाब एक दिन,

मिलेगी इन जुमलों से निजात एक दिन ।

बहुत-बहुत धन्यवाद, जयहिंद ।

श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी (श्रीनगर) : मिस्टर चेयरमैन, यहां पर यूनियन बजट के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर का भी बजट टेबल किया गया है । जम्मू-कश्मीर का बजट डिसकस नहीं किया जा रहा है, बल्कि टेबल किया गया है । अभी तक एक माननीय मैम्बर, जो जम्मू-कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, उनके अलावा जम्मू-कश्मीर के हवाले से किसी ने बात नहीं की है ।

चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से यह बात बताना चाहता हूं कि बजट का यहां पर होना, जम्मू-कश्मीर का बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना, पार्लियामेंट के जरिए बनाया जाना, यूनियन गवर्नमेंट के जरिए बनाया जाना, यह सॉवरन बिट्रेयल है, जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ धोखा है । यह डेमोक्रेसी के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है, जो जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ किया जा रहा है । लोग डेमोक्रेसी में इस तरह के फैसले खुद लेते हैं, अपने लिए लेते हैं, जिसे कहते हैं ? democracy by the people, for the people, of the people. मगर आप देखें कि जम्मू-कश्मीर का बजट जम्मू-कश्मीर के लोग नहीं बनाते हैं, जम्मू-कश्मीर की स्टेट यह नहीं बनाता है । आज 70 सालों के बाद जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा किया गया और उस रियासत को इस हद तक गिराया गया कि उससे उसका बजट, उसके फैसले करने का हक भी छीना गया । उन वायदों के प्रिंसिपल्स के बरक्स, जिन प्रिंसिपल्स के बुनियाद पर हमने इस यूनियन के साथ ऐक्सेशन किया था कि हम अपने फैसले खुद लेंगे, जम्मू-कश्मीर स्टेट अपना फैसला खुद लेगा, अपना रास्ता खुद बनाएगा और हमें वह अख्तियार, हमें वह पावर इस यूनियन के संविधान ने दी थी । आज आप देखिए, हमें अपने फैसले लेने का अख्तियार नहीं है, अपने लिए रास्ते बनाने का अख्तियार नहीं है । हम पर फैसले थोपे जाते हैं । बजट यहां पर बनाया जाता है । आज आप मुझे बताइए, हर एक रियासत का, हर एक स्टेट के बाशिंदे यहां पर बैठे हुए हैं । किस स्टेट में ऐसा होता है कि उस स्टेट का बजट वह स्टेट खुद न बनाए, बल्कि वह उस पर थोपा जाए । वे फैसले उन पर थोपे जाएं । हम से हमारा हक छीना गया । हर तरह के डेमोक्रेटिक राइट्स जो उस स्टेट के बनते थे, आपने वे वर्ष 2019 में छीने । आर्टिकल 370 एक कड़ी थी, जिसके जरिए हम इस मुल्क से जुड़े थे और उस आर्टिकल के जरिए हमें वे हुकूक दिए जाते थे । हमें अपने सब्जेक्ट्स पर लेजिस्लेट करने का हक दिया जाता था । हम से पूछे बगैर यहां पर आर्टिकल 370 हटाया गया । हम से पूछे बगैर हमारे खिलाफ फैसले लिए गए । हमसे पूछे बगैर हमारा स्टेट्स और हमारा डेमोक्रेटिक राइट छीना गया । नतीजा यह है कि आज आप कहते हैं कि जम्मू-कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, जिसे मैं आज भी कबूल नहीं करता हूं । एक ऐसी रियासत जिसके पास अपनी लेजिस्लेटिव पावर थी, कॉंस्टिच्यूशनल पावर थी, लेकिन आज उनके पास कुछ नहीं है । नतीजा यह निकला है कि बजट यहां पर बनाया जाता है और उस बजट में जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ मजाक किया जाता है । मैं इम्प्लॉयमेंट के बारे में कहना चाहता हूं । जम्मू-कश्मीर में वर्ष 2019 के बाद आज पहली बार 70 सालों में अनइम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है । हमसे हमारे इख्तियारात छीने गए । हम डिसिजंस नहीं लेते हैं । आपका वायसराय वहां पर डिसिजन लेता है, जिसे आप एलजी कहते हैं । नतीजा यह निकला कि वहां पर अनइम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है । अनइम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है कि अगर वहां लोग रोजगार के लिए अप्लाई करना भी चाहते हैं, तो आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं, जगह नहीं है, जिनके जरिए आप उनको इम्प्लॉयमेंट दे सकें । आप उनकी जरूरत को पूरा कर सकें । आप एम्प्लॉयमेंट के हवाले से बहुत सारे लेवल्स पर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जंगें लड़ रहे हैं । यहां पर नई रिजर्वेशन पॉलिसी लागू की गई । वह हमने नहीं बनाई, जम्मू कश्मीर के लोगों ने नहीं बनाई । वह यहां पर बनाई गई और वहां पर थोपी गई । 70 परसेंट रिवर्जेशन बढ़ाई गई, ओपन मेरिट को 30 परसेंट तक कम किया गया । ओपन मेरिट के लिए अब जगह सिर्फ 30 परसेंट बनती है । यह एक ऐसी लड़ाई है, जहां पर ये चाहते हैं कि वहां पर क्लास वार हो । सोसायटी के जो मुख़्तलिफ़ सेक्शंस हैं, वे आपस में लड़ें । हमारी जो बैकवर्ड क्लासेज हैं, जिनके लिए हम चाहते हैं और हमेशा से रिजर्वेशन थी, हम चाहते थे कि उनको सपोर्ट मिले । वे ऊपर आए । उनको ओपन मेरिट के साथ लड़ाया जा रहा है । चूंकि जो तनासुख़ है, पॉपुलेशन का जो रेश्यो है, वह उस हद तक नहीं है, जिस हद तक रिजर्वेशन बढ़ाई गई । रिजर्वेशन 70 परसेंट के हद तक बढ़ाई गई, ओपन मेरिट को घटाया गया, जिससे क्लास वार, सैक्शन वार होने का खतरा है । मेरी गुजारिश है, मुझे गुजारिश करते हुए शर्म आती है, क्योंकि मैं फिर से कहूंगा कि हमारे हाथ में इख्तियार ही नहीं है । इन्हें भी सोचना चाहिए । एक रियासत है, जहां पर हमें उस हद तक गिराया गया है कि

यहां पर आकर भीख मांगनी पड़ती है । हम अपने फैसले नहीं ले पाते हैं । इनसे गुजारिश है कि ओपन मेरिट को या सुप्रीम कोर्ट की जो कैप है, उस हद तक रखें या पॉपुलेशन का जो रेश्यो है, पॉपुलेशन के हिसाब से जो कैटेगरीज हैं, आप उस हिसाब से रिजर्वेशन करें ताकि ओपन मेरिट पर इस वक्त जो तलवार चल रही है, वह न हो । हमारे लोग वहां पर इसका खामियाजा उठा रहे हैं ।

इसी के साथ-साथ कोविड की वजह से वैकेंसीज फिल करने के लिए जो डिले हुआ था, अगर यहां पर सब को याद हो तो कोविड से पहले वर्ष 2019 में स्टेट पर ताला लगाया गया था । उस दौरान स्टेट ने काम नहीं किया । उसके बाद कोविड आया । उसके बाद वैकेंसीज फिल होनी थी, उसके लिए वक्त नहीं दिया गया । वैकेंसीज फिल नहीं की गईं । उसका नतीजा यह हुआ कि हमारे जो बच्चे हैं, लड़के-लड़कियां हैं, वे ओवर एज होने शुरू हो गए हैं । हमारी गुजारिश है कि जो 28 साल की कैप है, उसको बढ़ाया जाए । उनको एज रिलेक्सेशन दी जाए, एगजम्प्शन दी जाए । वर्ष 2019 में कोविड के दौरान आपने जो लॉकडाउन किया था, जिस दौरान स्टेट ने काम नहीं किया, वैकेंसीज फिल नहीं हुईं, उनको एज रिलेक्सेशन दी जाए । आज वे 32 साल, 33 साल के हो गए हैं इसलिए उनको वन टाइम एगजम्प्शन दी जाए, एज रिलेक्सेशन दी जाए, ताकि वे अप्लाई कर सके ।

हॉर्टिकल्चर हमारा बहुत बड़ा सेक्टर है, बैकबोन है । आप उस हॉर्टिकल्चर के साथ भी लड़ाई दो लैवल्स पर लड़ रहे हैं । चेयरमैन सर, मैं आपके जरिये इन्हें बताना चाहता हूं । एक, हमारे लिए पेस्टिसाइड्स, खाद् वगैरह यहां से जो भेजी जाती है, वह जान-बूझकर टॉक्सिक भेजी जाती है । उससे हमारे पेड़-पौधे खराब किए जाते हैं । दूसरे लैवल पर, हमारे कश्मीर से जो सेब आता था, अगर आपने सुना हो, तो उसे पिछले साल रोका गया । मुल्क से बाहर चाहे ईरान हो, चाहे यूएसए हो, वहां से सेब लाया जाता है, विदाउट टैक्स, विदाउट इम्पोर्ट ड्यूटी सेब लाया जाता है ।

बाहर के सेब से यहां की मार्केट, मंडियां भरी गई हैं, जिस पर इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई गई है । कश्मीर से आने वाले सेब को रोका जाता है । कश्मीर के हॉर्टिकल्चर को टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स से खराब किया जाता है । दो लैवल्स पर हमारे साथ जंग लड़ी जाती है । हमारी इकोनॉमी को कमजोर किया जाता है । हमारे हॉर्टिकल्चर को कमजोर किया जाता है । मेरी गुजारिश है, हम चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की अवाम चाहती है कि इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाए । बाहर से जो सेब आता है, उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाए । हमें जो टॉक्सिक पेस्टीसाइड्स भेजा जाता है, उस हवाले से काम किया जाए । यह पेस्टिसाइड्स हमारे बीच न भेजा जाए । हमारे साथ इस तरह की जंगें न लड़ी जाएं । ? (व्यवधान) मैं वह बात भी करूंगा । मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है । आपका हाथ घंटी पर है । हमारे साथ हर तरह की ज्यादती होती है । वक्त भी उस तरह की एक ज्यादती है । मैं जानता हूं ।

मैं एक बात न चाहते हुए यहां पर दोहराना चाहता हूं । मैं यहां पर इलैक्शन की भीख मांगने के लिए नहीं आया हूं । मैं यहां पर अपना स्टेटस और अपना कॉन्स्टीट्यूशनल राइट्स, जो 370 के जरिये हमें दिया गया था, मैं वह मांगने आया हूं । चेयरमैन साहब, मैं इस वक्त की स्पीच कनक्लूड करते-करते आपके जरिये पूरे मूल्क को याद दिलाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी थी कि सितम्बर तक वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कायम की जाए । सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक अगले महीने सितंबर का महीना शुरू होने वाला है मगर अभी तक ? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** आप प्लीज कनक्लूड कीजिए ।

श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी **:** सर, मैं बस एक मिनट में कनक्लूड कर रहा हूं । वहां के इलैक्शन के लिए अभी भी कोई प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है । आपसे गुजारिश है । डेमोक्रेसी के लिए फोर द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी

? उन्हें डायरेक्शन दें । कम से कम सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर अमल करें और वहां पर इलैक्शन करवाएं । यहां पर जैसे अखिलेश जी ने कहा कि इन्होंने सीट्स बढ़ाई हैं । ये मुल्क भर में रिज़र्वेशन और पिछड़े क्लासेज के बारे में बातें करते हैं, तो ये जवाब दें कि बजट में, अपने प्लान में और जम्मू-कश्मीर की एसेम्बली में इन्होंने उस हवाले से क्या किया है?

मैं आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया । अगर और वक्त मिलता, तो मैं ज्यादा कह पाता । आपसे गुज़ारिश है कि जो बातें मैंने कही हैं, उन पर गौर करें और हमारी तरफ से भी बात करें । इनका अटेंशन जम्मू-कश्मीर की तरफ लें और हमारे मसले हल कराएं ।

बहुत-बहुत शुक्रिया ।

SHRI BALASHOWRY VALLABHANENI (MACHILIPATNAM): Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the Budget presented by the hon. Finance Minister on 23rd July.

Let me take this opportunity to congratulate Shrimati Nirmala Sitharaman Garu for taking charge of the Finance Ministry again, and also for presenting the Budget a record seventh time. This is the third consecutive Government of NDA. Modi Ji has been elected as the Prime Minister for the consecutive third term. The people of this country have shown faith in Modi ji and have voted for his leadership and given a strong mandate to NDA. In the last 10 years, under his leadership, this country has witnessed bold economic reforms like `Make in India? Initiative, GST, labour reforms etc., to social reforms like Beti Bachao Beti Padhao, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, Ujjawala Yojana etc. I am only mentioning a few here, there are so many. Hon. PM Modi has left a long-lasting impact on our nation. Under his leadership in the last 10 years, we have achieved the remarkable growth. We are the fastest growing economy. We are the fifth largest economy and we will definitely be the third largest economy in the course of the next few years. His policies are not only helping us grow domestically, but also on the world Map. This present Budget reflects the future vision of Modi Ji. The initiatives and economic policies announced in this Budget will push India's growth and our vision to become the third largest economy in the world and also make India a Viksit Bharat.

Sir, this Budget specially focuses on youth and employment generation. The Government has introduced internship programme which will benefit one crore youths with an internship allowance of Rs. 5,000 per month. The Budget also focuses on skill training of youth and encouraging women employment.

Sir, I come from Andhra Pradesh. Its financial conditions is not hidden. The previous AP Government has done nothing for the progress of the State and made it more miserable for the present Government to even survive.

Sir, I am grateful that this Budget has assured the implementation of all the commitments made to Andhra Pradesh as given in the AP Re-organisation Act. I am grateful that the FM has assured a special financial assistance of Rs. 15,000 crore to Andhra Pradesh. It is a first step towards re-building our State. It is a long journey, and we would definitely work together in bringing Andhra Pradesh's lost glory back.

Speaking of AP Re-organization Act, this would majorly include, setting up of oil refinery, setting up of steel plant and setting up of port.

The Machilipatnam Port is already under development. It is financed by the PFC. I seek the hon. Minister?s consideration and support for the holistic development of the Port with due emphasis on maritime development, roads, rail infrastructure development under its Gati Shakti Programme. I am sure, a timely completion of this project would definitely help AP in its economic development.

Secondly, setting up of steel plant at Kadappa is also proposed. It is an unrealised dream and a long-term demand of the State. We need your due consideration and support in this regard as well.

Thirdly and very importantly, for setting up of oil refinery near Machilipatnam Port, a good area of land bank is also available in Machilipatnam Port.

I would request the Government to consider this project at Machilipatnam. There are two more important issues. The first one is regarding the permanent capital city of Andhra Pradesh, and the second one is regarding the Polavaram Irrigation Project. As everyone of us here is aware, Andhra Pradesh till date does not have a permanent capital city. The hon. Minister has given us the financial assistance for the development of the capital city, that is Amaravati. I am thankful to the Government.

Regarding the Polavaram Project, importantly, the Finance Minister has mentioned financing and early completion of the Polavaram Irrigation Project which is the lifeline for Andhra Pradesh and its farmers. As Madam has also rightly said in her Budget speech, this is not only for Andhra Pradesh, but it will facilitate our country?s food security as well. This shows the importance of the Polavaram Project. Apart

from what has been given to my State, I would also like to speak about the Budget in general.

Regarding capital infrastructure and PLIs, first and foremost, we all appreciate the fact that the Budget aims to boost infrastructure development in the country and the same will create employment. Our Government has given more importance to capital infrastructure and push for manufacturing through Production Linked Incentive Schemes. India?s capex has almost doubled in the last three years from Rs.5.9 lakh crore in the financial year 2022 to Rs.11.11 lakh crore in the financial year 2025. The PLI schemes have crossed over Rs.1.03 lakh crore of investments. There is Rs.8.61 lakh crore worth of production and sales till November 2023, and they have generated employment of 6.78 lakhs, which is a big step forward in our economic progress, encouraging private investments and new ideas. This approach has led to a significant growth in areas like mobile manufacturing, solar energy, battery storage and various other industries. This has further helped in attracting global manufacturers, and creating millions of jobs for people with various skills. Additionally, the PLI schemes have helped and strengthened our domestic production capabilities to achieve India?s vision of Atmanirbhar Bharat. Under the leadership of Modi ji, the Government is creating a sustainable and inclusive future.

With regard to financial health of our banks, the Indian financial system is stronger than ever with regard to capital adequacy, low levels of non-performing assets and healthy profitability. Many thanks to the significant reforms and vigilant governance. I have served on the Finance Committee for the last five years and I have witnessed the first-hand transformation. According to the RBI?s Financial Stability Report, the gross NPAs of commercial banks fell to a 12-year low of 2.8 per cent in March 2024. Our Government is giving priority to financial inclusion. This improvement has restored confidence in our banking system which is now in an excellent shape to support further growth. India has topped the global rankings in digital payments. Digital transactions have gone up.

Sir, 46 per cent of global digital transactions are done in India. India accounted for 46 per cent of the global real-time payments. It is worth to note that digital transactions in India have grown 90-fold in the last 12 years.

With regard to agriculture and rural development, the Government has taken various initiatives to develop the agriculture sector. I only request the Government to allocate sufficient funds for adopting the modern methods, and it should

support this sector by reducing the GST on the agricultural inputs. There is also a need for increasing the rural infrastructure, including digital connectivity, etc.

Hon. Chairperson, Sir, at present, farmers are getting credit limit of Rs. 3 lakh on Kisan Credit Card with seven per cent as interest rate, of which the Government is paying four per cent and the farmers are paying the balance rate of three per cent interest. With increased prices of input material, I would like to request you to consider doubling the limit of Kisan Credit Card to Rs. 6 lakh so that the farmers have sufficient leverage to spend on agriculture.

More importantly, I have been raising the issues faced by the tenant farmers on various occasions in this very House. The tenant farmers need utmost attention of the Government and they should be treated at par with the other farmers. The tenant farmers do not have any access to Government schemes, and particularly, they do not have any financial support from the Government. I, once again, request the Government that tenant farmers should also be included in the financial schemes, particularly the Kisan Credit Scheme, Kisan Samman Nidhi, etc., like the other farmers.

Hon. Chairperson, Sir, lastly, I come to Dr. Bhogaraju Pattabhi Sitaramayya Memorial Building. Dr. Bhogaraju Pattabhi Sitaramayya was the founder of Andhra Bank. Every Telugu-speaking person had a special connect with the Andhra Bank. For us, banking means Andhra Bank. As you know, after the amalgamation of banks, the Andhra Bank had merged with the Union Bank of India. Dr. Bhogaraju Pattabhi Sitaramayya was one of the freedom fighters and he started the first bank in Machilipatnam, which is my constituency.

I request you to consider a proposal for constructing a knowledge park and also a museum. This has been a long-pending demand. I request the hon. Minister of Finance and the MD of the Union Bank of India to consider the said demand.

With these words, I support this Budget. Thank you, Sir.

श्री बृजमोहन अग्रवाल **(**रायपुर**) :** माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मोदी जी के इस तीसरे कार्यकाल में 48,21,000 करोड़ रुपये का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसका स्वागत करता हूं, अभिनन्दन करता हूं । माननीय प्रधान मंत्री और सीतारमण जी को मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं ।

महोदय, मैं यह कह सकता हूं कि देश के इतिहास में शायद सदियों के बाद यह तब्दीली हुई है । हमारे यहां मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, कांग्रेस ने राज किया, पर मोदी जी का राज आने के बाद इस देश की जनता

को एक-एक पल सुनहरा लग रहा है । अगर इस देश में तब्दीली हुई है तो मोदी जी के आने के बाद हुई है । इस देश में विकास हुआ है ।

महोदय, मैं नेता, प्रतिपक्ष जी की बातों को सुन रहा था । नेता, प्रतिपक्ष जी जब खड़े हुए तो ?जोड़ो, जोड़ो, भारत जोड़ो? की बात हो रही थी । पर, इस देश को तोड़ने का काम किसने किया?? (व्यवधान) पाकिस्तान किसने बनाया?? (व्यवधान) जरा बताइए, किसने बनाया पाकिस्तान? ? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please speak on the Budget.

श्री बृजमोहन अग्रवाल **:** कोको द्वीप को बर्मा को किसने दिया?? (व्यवधान) क्या आपके पास इसका कोई जवाब है?? (व्यवधान) आप जरा यह बताइए कि चीन को हमारा हिस्सा किसने दिया?? (व्यवधान) लद्दाख के हमारे हिस्से को किसने पाकिस्तान को दिया?? (व्यवधान) जब डोकलाम में चीन आगे बढ़ रहा था, तब राहुल गांधी जी चीन के दूतावास में बैठे हुए थे, चीन के दूतावास में जाकर उनके साथ समझौता कर रहे थे ।? (व्यवधान)

राहुल गांधी जी का भाषण मैंने बहुत ध्यान से सुना ।? (व्यवधान) वे ?नीट? की बातें कर रहे थे, पर छत्तीसगढ़ की पी.एस.सी. परीक्षा में कांग्रेस की सरकार में इतना भ्रष्टाचार हुआ कि उसके चेयरमैन आज जेल में हैं ।? (व्यवधान) जिन राज्यों में आज कांग्रेस की सरकारें हैं, आप उनके बारे में बात क्यों नहीं करते हैं?? (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ । ? (व्यवधान) छत्तीसगढ़ प्रभु राम का वनगमन मार्ग है । छत्तीसगढ़ माँ कौशल्या की जन्मभूमि है । छत्तीसगढ़ प्रभु वल्लभाचार्य की जन्मभूमि है । छत्तीसगढ़ से महानदी निकलती है, चित्रोत्पला नदी निकलती है । ? (व्यवधान) प्रभु राम वनगमन मार्ग के कारण प्रभु राम वहां के भांजे हैं । रामायरण की एक चौपाई है ? ?जाको प्रभु दारुण देही, ताकि मति पहले हर लेही॥? मुझे लगता है कि राहुल जी और विपक्ष की मति को भगवान ने पहले ही हर लिया है । अरे! जिस पार्टी को 244 सीटें मिलती हैं, उसको 99 सीटें वाला बोलता है कि तुम फेल हो गए । मैं पूछता हूँ कि 244 नंबर ज्यादा हैं कि 99 नंबर ज्यादा हैं । ? (व्यवधान) आप लोगों को क्या हो गया है? ? (व्यवधान) अरे! बताइए न, आप क्यों इतने उत्साह में हैं? ? (व्यवधान) बताइए कि 244 नंबर ज्यादा होते हैं कि 99 नंबर ज्यादा होते हैं?

HON. CHAIRPERSON: Please address the chair.

श्री बृजमोहन अग्रवाल **:** माननीय सभापति जी, अभी वे बोल रहे थे कि इस बजट में एससी के लिए कुछ नहीं है, एसटी के लिए कुछ नहीं है, पिछड़े वर्ग के लिए कुछ नहीं है । ज़रा बताइए कि प्रधान मंत्री आवास किसको मिलेंगे? ज़रा बताएं कि हर घर, नल से जल योजना का फायदा किसको मिलेगा? ज़रा बताइए कि चार करोड़ नौजवानों को अगर रोज़गार मिलेगा तो उससे किसको फायदा मिलेगा? ? (व्यवधान) आपकी तरह एससी, एसटी एवं पिछड़े वर्ग का शोषण करने वाले मोदी जी नहीं हैं । ? (व्यवधान) मोदी जी ने इस देश को चार जातियों में बांटा है - एक युवा होगा, एक किसान होगा, एक गरीब होगा, एक महिला होगी । वे किसी भी जाति-धर्म के हों, सबका विकास होगा । ? (व्यवधान) आपने क्या किया? आप इस बजट का विरोध क्यों कर रहे हैं? ? (व्यवधान) क्योंकि आपको इस देश का विकास पसंद नहीं है, किसानों का विकास पसंद नहीं है, महिलाओं का विकास पसंद नहीं है, युवाओं का विकास पसंद नहीं है । आपको देश की सीमाओं का विकास पसंद नहीं है । ? (व्यवधान) सभापति महोदय, इनको अगर पसंद है तो सिर्फ एक परिवार, दो परिवार और पांच परिवारों का विकास पसंद है । ? (व्यवधान) राहुल जी, एससी, एसटी एवं पिछड़े वर्ग की बहुत बातें कर रहे थे । मैं उनसे

पूछना चाहता हूँ कि आप क्यों प्रतिपक्ष के नेता बन गए? आपने किसी एससी, एसटी या पिछड़े वर्ग को क्यों नहीं बनाया? क्या कांग्रेस में कोई एससी, एसटी, ओबीसी जीत कर नहीं आया? ? (व्यवधान) मैं पूछता हूँ क्यों नहीं बनाया? ? (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, यह बजट इस देश के 140 करोड़ की जनसंख्या वाली जनता के सपनों को पूरा करने वाला बजट है । यह बजट भारत की तरक्की का बजट है । यह बजट हिन्दुस्तान को सशक्त बनाने वाला बजट है । यह बजट हिन्दुस्तान को शक्तिशाली बनाने वाला बजट है । यह बजट भारत को स्वाभिमानी बनाने वाला बजट है । यह बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है । ? (व्यवधान) मुझे लगता है कि निर्मलमा सीतामरण जी ने बजट की जो किताब सभी को दी है, शायद उस किताब को आपने पढ़ा नहीं है । अगर पढ़ा है तो आपको दृष्टिदोष है । ? (व्यवधान) यहां की हमारी एनेक्सी में आँख के इलाज करने वाले डॉक्टर हैं । ? (व्यवधान) ज़रा आप जा कर वहां दिखा लीजिए और आँख के दोष को दूर कर लीजिए ।

माननीय सभापति जी, हमारे प्रतिपक्ष के साथी, राहुल जी बार-बार मंहगाई की बात कर रहे थे । मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ष 1999 में जब अटल बिहारी जी प्रधान मंत्री थे, उस समय इनफ्लेशन दर 4.67 पर्सेंट थी, वर्ष 2005 में यह 5.80 थी । जब कांग्रेस का राज वर्ष 2012-13-14 में था, तब इनफ्लेशन दर 11.12 प्रतिशत थी । आज इनफ्लेशन दर 4.83 पर्सेंट है । यानि आज मंहगाई दर सात पर्सेंट कम है । आप कभी इसको देखते क्यों नहीं है?

अभी ये बात कर रहे थे कि मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं । ज़रा आप बताएं कि इनकम टैक्स में जो कमी की गई है, 7 लाख 75 हज़ार रुपये तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा, उसमें सैक्शन 87(a) में 7 लाख 75 हज़ार रुपये तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा । क्या आपने कभी किया था? आपने दो लाख रुपये से ज्यादा कभी नहीं बढ़ाया । अभी लगभग आठ लाख रुपये तक डिडक्शन्स के बाद इनकम टैक्स नहीं लगेगा ।

सभापति महोदय, मैं लॉ का छात्र भी रहा हूं । मैंने भारत के संविधान को भी पढ़ा है । भारत के संविधान में क्या लिखा है- संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न राष्ट्र की संकल्पना की गई है ।? (व्यवधान)

सभापति जी, मैंने तो अभी शुरू ही किया है ।? (व्यवधान) आप चीन से चंदा लेंगे, उससे काम नहीं चलेगा ।? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please address the Chair.

श्री बृजमोहन अग्रवाल **:** आप चीन से चंदा लेने का काम करते हो, उसके अलावा कोई काम नहीं करते हैं ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दो लाख करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । क्या आपने कभी महिलाओं की सशक्तिकरण की बात की थी?? (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, राहुल गांधी जी छतीसगढ़ गए थे । उन्होंने वहां के कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया था । उस घोषणा पत्र में कहा कि हर महिला को 500 रुपये महीने का देंगे । उसका क्या हुआ? आपने उनको पैसा नहीं दिया । आज छतीसगढ़ में हमारी सरकार 1000 रुपये महिलाओं को महीने की दे रही है, 12000 रुपये साल का दे रही है ।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude your speech.

श्री बृजमोहन अग्रवाल **:** माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा । ये लोग भारत की कल्पना टुकड़ों-टुकड़ों में करते हैं । ये भारत की कल्पना पाँच पार्ट्स में करते हैं । अगर टोटल में कोई भारत की कल्पना करता है तो नरेन्द्र मोदी जी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी करती है । हम विकसित भारत बनाने के लिए यहां पर काम कर रहे हैं । क्या आपने 60 सालों में अनुच्छेद 370 हटायी, आपने अयोध्या में प्रभु राम भगवान का मंदिर बनाया, आपने कभी कश्मीर में पत्थरबाजी खत्म की? साउथ पोल में विश्व का कोई देश नहीं जा पाया । अगर चंद्रमा के साउथ पोल में कोई गया तो हमारा भारत गया । उस पर आपको भी गर्व होना चाहिए । हमारी अर्थव्यवस्था जो 11 वें नंबर पर थी, उसको पांचवे नंबर और तीसरे नंबर पर लाने वाला कोई है तो नरेन्द्र मोदी जी हैं । यह आपके बस की बात नहीं है । भारत पर कोई हमला करता है और उसके घर में घुस कर जवाब देने वाला अगर कोई है तो हमारे नरेन्द्र मोदी जी हैं । अगर सेमी कंडक्टर चिप्स का कोई निर्माण कर सकता है, तो हमारे नरेन्द्र मोदी जी के राज में हो सकता है । अगर भारत में 5 जी आ सकता है तो नरेन्द्र मोदी जी के राज में आ सकता है । भारत में अगर प्रतिदिन दो महाविद्यालय खुल सकता है तो मोदी जी के राज में खुल सकता है । भारत में प्रतिदिन 30 किलोमीटर सड़क बन सकता है तो मोदी जी के राज में हो सकता है । हमारी सरकार पांच राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड बनाने की योजना लाई है । उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक लोन देने की योजना लाई गई है । कारीगरों के लिए डोरमेट्री बनाने की योजना लाई गई है । वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दी गई है । पेंशनभोगियों के लिए 15 हजार करोड़ रुपये से बढ़ा कर 25 हजार करोड़ रुपये कर दी गई है । प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ आवास बनेंगे । अभी मैं सुन रहा था । क्या कभी आपने ऐसा किया? राजीव जी के राज में प्रधानमंत्री आवास के लिए 12 हजार रुपये मिलते थे । आज ढाई-ढाई लाख रुपये मिल रहे हैं । 1 करोड़ शहरी आवास बनाए जाएंगे । आपने चांद पर तिरंगा नहीं लहराया । मोदी जी ने चांद पर भी तिरंगा लहरा दिया । उन्होंने गरीबों-वंचितों को सम्मान दिया, किसानों का कल्याण किया, नारी शक्ति को ताकतवर बनाया । अभी तो मनुष्यों के आधार कार्ड बन रहे हैं, अब मोदी जी के राज में किसानों की जमीन का भी आधार कार्ड बनेगा । शहरी जमीनों के भी आधार कार्ड बनेंगे ।? (व्यवधान)

श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील **(**सांगली**) :** सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद ।

महोदय, मैं और मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग बहुत ध्यान से बजट भाषण को सुन रहे थे । हमें यह आशा थी कि सांगली को इस बजट से कुछ हासिल होगा, लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि सांगली तो दूर, लगभग डेढ़ घंटे के भाषण में एक बार भी मेरे राज्य महाराष्ट्र का नाम नहीं लिया गया । असम और बिहार में आने वाली बाढ़ की बात की गई । महाराष्ट्र में भी बाढ़ आती है, लेकिन महाराष्ट्र में बाढ़ और उससे होने वाली जान और माल की हानि की बात अर्थ मंत्री जी ने नहीं की । आंध्र प्रदेश के अमरावती की बात की गई, उनको हजारों करोड़ रुपये का फंड दिया गया । महाराष्ट्र में भी एक अमरावती है, लेकिन उसका जिक्र नहीं किया गया ।

सांगली, जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, वह भी चाहता है कि स्मार्ट सिटी में उसका समावेश हो । उसका नाम न स्मार्ट सिटी में समाविष्ट हुआ, न वहां हवाई अड्डे के लिए कोई निधि दी गई । बिहार की सिंचाई योजनाओं के लिए एआईबीपी और पीएमकेएसवाई से निधि देने की बात की गई । मेरे महाराष्ट्र में, मेरे सांगली क्षेत्र में विस्तारित

महसा, विस्तारित टेम्बू प्रकल्पों के लिए एआईबीपी से निधि देने के लिए अर्थ मंत्री जी को कोई जरूरत महसूस नहीं हुई ।

महोदय, भारत के टैक्स का 37 फीसदी हिस्सा महाराष्ट्र से आता है । भारत की जीडीपी का 14 फीसदी हिस्सा महाराष्ट्र देता है । सरकार का लक्ष्य है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनायेंगे । अगर महाराष्ट्र से 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी न बने, तो देश की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी मुमकिन नहीं है । महाराष्ट्र के विकास के बिना इस भारत राष्ट्र का विकास होना नामुमकिन है । मैं महाराष्ट्र के स्टेट एंथम, जो हमारा राज्य गान है, उससे एक लाइन आपको बताता हूं ।

सर, इतिहास गवाह है कि दिल्ली का तख्त सलामत रखने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र लेता था, लेता है और लेता रहेगा, चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक हो, साहित्यिक हो या राजनैतिक हो । यह जो सरकार बनी है, इसको सलामत रखने का काम भी महाराष्ट्र ने 17 सांसद देकर किया है । हमें भूल जाओ, हमारी तरफ मत देखो, लेकिन उन 17 सांसदों को देखकर महाराष्ट्र के लिए कुछ तो देना चाहिए था । कुछ सांसद मुस्करा रहे हैं । इनको देखकर फिल्म का एक गाना याद आता है, ?तुम इतना जो मुस्करा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो ।? मैं जानता हूं कि इन्हें डर है कि वापस निर्वाचन क्षेत्र में जाकर क्या कहेंगे, यह दु:ख उनको सता रहा है । मैं इनकी मजबूरियां समझता हूं । बैसाखियों पर बनी हुई सरकार से लोग और क्या अपेक्षा करेंगे? मुझे डर है कि यह बैसाखियों पर मजबूरन चलने वाली सरकार अपना देश न डुबा दे ।

सर, राज्यों की बात छोड़ते हैं, सामान्य लोगों की अपेक्षाओं पर क्या-क्या किया? मैं यह पूछना चाहता हूं । एमएसपी को लीगलाइज करने की बात थी, यह इन्होंने नहीं की । किसान कर्ज से मर रहे हैं, उनका कर्ज माफ करने की मांग की, वह नजरंदाज कर दी । महंगाई सीमित रखने के लिए तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं । ईपीएस में 7 हजार रुपये मासिक पेंशन देने की बात हुई, वह मांग इन्होंने नजरंदाज कर दी । भूमिहीन किसानों को पीएम सम्मान योजना में समाविष्ट करने की बात की, वह मांग भी इन्होंने ठुकरा दिया । फर्टिलाइजर्स और सीड्स पर लगने वाले जीएसटी को भी इन्होंने माफ नहीं किया । मनरेगा में 400 रुपये तक मिनिमम वेज बढ़ाने की मांग की थी, वह भी इन्होंने नहीं दी ।

इन्होंने जो नहीं दिया, तो नहीं दिया । जो दिया है, उस पर मैं एक मिनट बात करूंगा । They have again decided to continue with giving food subsidy to 80 crore people. It is a very ironic issue because the entire BJP?s plan or the election manifesto was going around telling people, ?Vote us back to power.? आपकी फूड सब्सिडी खत्म हो जाएगी । फूड सब्सिडी की बात करते हैं और खुद इन्होंने अपने बजट में फूड सब्सिडी पर देने वाला प्रोविजन कम कर दिया है ।

सर, ये किसानों के वेलफेयर की बात करते हैं । साढ़े 13 फीसदी फर्टिलाइजर की सब्सिडी के लिए होने वाला प्रोविजन इन्होंने कम किया है । ये इंटर्नशिप की बात करते हैं । 500 फर्म मिलकर 20 हजार लोग हायर करेंगे, मुझे यह मुमकिन नहीं लगता है । ये 3 करोड़ घर बनाने की बातें करते हैं । मैंने पूरा बजट छान मारा । पिछले बजट से इस बजट में सिर्फ 5 फीसदी ज्यादा प्रोविजन किया है । ये किसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? बजट में 70 हजार करोड़ रुपये पिछले वोट ऑन एकाउंट में और 60 हजार करोड़ रुपये इस वोट ऑन एकाउंट में इन्होंने न्यू स्कीम्स के लिए दिए हैं । कौन सी न्यू स्कीम्स हैं? इससे क्या होने वाला है?

17.00 hrs

Sir, is this a Budget only of announcements or a Budget only for actual provisions?

हमारे संत तुकाराम महाराज जी का एक अभंग सुनाता हूं:-

Saint Tukaram ji talked about this kind of people who only pay lip service to the people. They look good but lack substance.

इसका अर्थ यह है कि बातों की कढ़ी चावल से किसी का पेट नहीं भरता । परसों बजट से खुश एक सांसद बोले कि विशाल यह तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है । ये ट्रेलर और पिक्चर जैसी बातों से मैं पूरा डर जाता हूं । परसों बीबी ने एक पिक्चर का ट्रेलर देख लिया और मुझे पिक्चर दिखाने ले गई । दिक्कत यह है कि ट्रेलर देखकर पिक्चर तो चले गए, लेकिन आधे घंटे में बोर हो गया, बकवास पिक्चर थी, बाहर आ गए । मेरी दिक्कत सरकार से यही है कि ट्रेलर तो ये बहुत अच्छा बना लेते हैं, लेकिन इनसे पिक्चर नहीं बनती क्योंकि डायरेक्टर में ही प्रॉब्लम है । इस बार तो ट्रेलर भी बकवास हुआ ।

Sir, I will conclude by mentioning a simple point. I want to tell them why they have lost in the States like Maharashtra. They may go on and talk about how the Constitution was brought in and caste equation was brought in. But that is not the reason for them losing majority of the States of India.

There is an article by Indian Express, which says that in every State, where the GDP has dropped, the BJP has lost. And, if they continue with this kind of economic policy, I assure you that आने वाले महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में ये वापस हारेंगे । मेरा अनुरोध है कि इकोनॉमी पर ध्यान दो वरना आप ज्यादा दिन उस तरफ नहीं रहने वाले हैं । धन्यवाद ।

SHRI NAVEEN JINDAL (KURUKSHETRA): Hon. Chairman Sir, I am grateful to you for granting me this opportunity to speak on this Budget. First and foremost, I extend my heartiest congratulations to the hon. Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman ji for presenting the Budget for a record seventh time.

Sir, this budget is an important step in the spectacular journey of our country to be developed by 2047. The unprecedented development and progress witnessed by us during the last decade under the inspiring leadership of our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi is admirable. It is admirable because at a time when most of the countries, including the developed ones, were facing economic challenges and challenges on other fronts, India, in spite of its very large population and diversity, had set an example of a truly welfare State and a model economy.

Sir, we are already the fifth-largest economy in the world, and in the next few years we are going to go on to become the third-largest. This is a great achievement. It is something that we can all be very proud of.

Sir, when we see the budget from a social perspective, it is not just a ?Bahujan Hitay, Bahujan Sukhay?, but also a ?Sarvajan Hitay, Sarvajan Sukhay? Budget. It contains welfare measures and schemes for the marginalised and deprived, including women, poor, farmers, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and youths, who constitute more than 65 per cent of our population. But I find it sad that not a single word of appreciation has come from the hon. Members adorning the benches in front of us. If it is only for the sake of criticism, then in my view, they are at risk of losing their credibility.

Sir, due to paucity of time, I will limit myself only to two of the Budget priorities. The first is productivity and resilience in agriculture, and the second is employment and skilling. Hopefully, my hon. friends will be able to appreciate the Budget at least on these two critical points.

Sir, a mammoth sum of Rs. 1.95 lakh crore have been allocated in respect of agriculture and farmers? welfare and Rs. 2.65 lakh crore have been allocated for rural development. This is indeed a very laudable step and will certainly go a long way in improving the lot of our Annadatas, the hands that feed us.

Sir, through your kind self, I would like to draw the attention of this august House to a pioneering measure included in this Budget, that is, initiation of one crore farmers to natural farming by our hon. Prime Minister. There is a growing realisation that only natural farming is the most health-friendly and environmentally sustainable form of farming. It is much better compared to chemical farming. It is much more economical than organic farming.

Sir, our hon. Prime Minister has been a strong votary of natural farming, and has been spearheading this noble cause. We are thankful to him for making this a reality in this Budget. I am confident that this would be a game-changer not only for India but also for the entire world.

Sir, all the hon. Members of this August House are well aware that due to unabated use of chemical fertilizers, pesticides, insecticides, weedicides, etc. mother earth will be soon rendered barren. The food that most of us consume is toxic and full of harmful elements leading to cancer and various other serious elements. Therefore, it is high time we put the clock back by adopting a practice like natural farming to rejuvenate mother earth and restore organic carbon and other critical elements including helpful bacteria and earthworms back into the soil.

Sir, I too was not very familiar with natural farming till recently. But hearing about it from our hon. Prime Minister in his various speeches, I discussed it with eminent experts like Acharya Devvrat ji, hon. Governor of Gujarat and Padmasri Dr. Hari Om, who are leading this initiative. I am convinced about its overwhelming benefits. It is really the need of the hour. We need to act on a war footing with a sense of urgency. I would request the Government to set up easily accessible, specialized procurement centres for this natural produce as the farmers will get a much higher price for this produce, increasing the farmer's income. Also, this would help us in becoming *aatmanirbhar* in case of fertilizers, and we will not have to import any fertilizers from outside.

Sir, the second issue that I wish to speak about is skill development. It is an issue which is very close to my heart. In my view, skill development is the most important issue for young India. While we speak extensively about unemployment, we hardly speak about the shortage of skilled workforce for the Indian industry. I would like to thank the hon. Prime Minister for making education and skilling aspirational through the National Credit Framework. To facilitate this, the Government has announced upgradation of 1000 ITIs by upgrading infrastructure of skilling in future technologies and training of the trainers.

Sir, I would like to make some suggestions as I have seen a lot of ITIs all over the country. Most of the ITIs that we have work in one shift only. If they start working in two shifts, they will be able to train double the number of students. Moreover, they should also be producing goods for the market. If they are producing goods for the market, they will not have any shortage of raw materials to practice on. We also need to ensure high quality training and standards. We need to have tie ups with the best skilling institutes in the world so that their curriculum and courses are approved by them. Our courses should also be recognized internationally.

Sir, our students need to be trained in Artificial Intelligence (AI), robotics, instrumentation and automation, hydraulics, mechatronics, machine learning, internet of things, etc. They also need to be trained in good spoken English and other soft skills. Once they are well trained, they will be able to work for big companies in India. They will be able to start their own ventures, and if they wish to go abroad, they will be able to go abroad through legitimate channels, and not having to resort to donkey routes. We also need to have a scheme to operate ITIs under the Public Private Partnership mode and not for profit institutions, as this will solve the challenge of hiring top class trainers in new technology. Some ITIs

could also be working as repair shops, where people can take their tractors and cars, and the students will get real time experience while learning.

Sir, I am also deeply impressed by the vision of internships on a large scale in the top 500 companies to create skilled workforce in the country. Through you, Sir, I would assure this august House of making it a huge success in our company, Jindal Steel & Power.

सभापति जी, कौशल विकास पर बोलते हुए मैं बहुत भावनाओं से भरा हुआ हूं, क्योंकि मुझे मेरे प्रेरणास्रोत मेरे पिता स्व. ओपी जिंदल जी की याद आ रही है, जो 11 वीं लोक सभा के सदस्य थे । उन्होंने अपने हाथों से हल चलाने से लेकर अपने हाथों से स्टील उद्योग में काम किया । बाबू जी कारखानों में काम करने वालों के कौशल व सम्मान पर सदैव ध्यान देते थे । वह हाथ से काम करने वालों को भगवान विश्वकर्मा का स्वरूप मानते थे । इंजीनियर्स को भी वह उनसे सलाह लेने को कहते थे ।

महोदय, स्व. ओपी जिंदल जी ने देश को स्टील के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए व पिछड़े दलितों को पूरा सम्मान दिलाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया । उनके उच्च आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए मैं आपके माध्यम से इस गरिमामयी सदन में संकल्प लेता हूं कि विश्व के धर्म क्षेत्र और मेरे कर्म क्षेत्र, हरियाणा के कुरुक्षेत्र व कैथल जिले में तथा छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के अंदर हम भारत के सबसे अच्छे नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे अच्छे विकास कौशल केंद्र साबित करेंगे ।

महोदय, हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि हमारे हरियाणा के सभी आईटीआई और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी की अपेक्षाओं के अनुरूप उच्चकोटि का प्रदर्शन करें । माननीय प्रधान मंत्री जी ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की जिम्मेदारी जयंत चौधरी जी को दी है, जो खुद एक युवा हैं । हमें विश्वास है कि वे इसमें बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे । मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वह विश्व का धर्म क्षेत्र है । ऋग्वेद, सामवेद की रचना इसी धर्मक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में हुई । यहीं पर महाभारत के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया । हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में हरियाणा और गीता स्थली कुरुक्षेत्र के विकास के लिए बहुत-कुछ किया है, जिसके लिए हम हरियाणावासी उनके आभारी हैं ।

महोदय, मैं हरियाणा के मेरे कुछ साथियों द्वारा बजट की चर्चा के दौरान हरियाणा की अनदेखी की बात पर दो शब्द कहना चाहूंगा । अगर वे बजट को ध्यान से पढेंगे तो पाएंगे कि सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय बजट में हरियाणा के लिए भी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बहुत धन आवंटित किया गया है । उनकी जानकारी के लिए मैं संक्षेप में बता देता हूं कि वर्ष 2024-25 में 13 हजार 6 सौ करोड़ से भी अधिक की राशि हरियाणा को प्राप्त होगी । प्राकृतिक खेती की योजना, जिसके बारे में मैंने विस्तार से कहा, अभी हरियाणा में केवल 6 हजार एकड़ के अंदर ही हमारे किसान भाई इसका प्रयोग कर रहे हैं । अगर हम सब मिलकर काम करें, इसको 6 हजार से 6 लाख हम करवा सकते हैं और इससे हमारे किसानों का व्यय कम होगा और आमदनी दोगुनी हो सकती है ।

महोदय, कौशल विकास के लिए आवंटित 2 लाख करोड़ की धनराशि से हरियाणा के युवाओं को भी भरपूर लाभ मिलेगा । एमएसएमई से संबद्ध योजनाओं से हरियाणा की लगभग 1 लाख 16 हजार इकाइयां भी लाभान्वित होंगी । प्रधान मंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसके अंतर्गत ग्रामीणों को घरों में मुफ्त बिजली मिलेगी । वह भी जल्द शुरू होने वाली है । आपके माध्यम से मेरा हरियाणा के सभी माननीय सांसदों से आग्रह है कि इस

बजट के जनहितकारी प्रावधानों से अपने हलके के लोगों को अवश्य अवगत कराएं, ताकि वे इन कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकें ।

महोदय, मैं सदन में उपस्थित सभी साथियों से यह आग्रह करूंगा कि इस बजट का समर्थन करें, क्योंकि राष्ट्र निर्माण एक महायज्ञ है, इसलिए सभी से आहुति अपेक्षित है । आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं । धन्यवाद, जय हिंद ।

DR. THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): Hon. Chairperson Sir, Vanakkam. This Budget seems to have been prepared without keeping the comprehensive development of our country. The interests of the people belonging to the working class, particularly the marginalised sections of our society have not been taken into account in this Budget. This is just a Budget to appease and satisfy one or two allies in the Coalition Government of NDA and it mostly reflects their sentiments concerning to keep this Government in power for the next five years intact by doing such appeasement. This is a Budget of partiality. This Budget is prepared just by ignoring the State Governments where the parties of INDIA Alliance are in power.

The hon. Chief Minister of Tamil Nadu Thiru Thalapathy M.K. Stalin, as a protest to condemn this Budget, has openly announced that he will not participate and hence boycotted the meeting of the General Council of NITI Aayog meeting. Not only that I wish to bring to your notice that the hon. Chief Minister of Tamil Nadu has organised several agitations throughout Tamil Nadu condemning the Union Budget. However, the hon. Chief Minister of West Bengal Ms Mamata Banerjee attended the NITI Aayog meeting but she was ill-treated by way of switching off her microphone when she was continuing her speech. I strongly condemn this disrespectful act. I also pinpoint that such things should not occur. The States where the non-BJP parties are in power and the States where the parties of INDIA are in power have been ignored in this Budget. Some States including Tamil Nadu have not accepted the implementation of the National Educational Policy, NEP. There are issues in implementation of NEP as there are contradictions in the basic policies and these States do not accept those contradictions. Funds that are due under the Samagra Shiksha Abhiyan are not released to Tamil Nadu and this Government is engaged in blackmail politics. I strongly condemn this. The hon. Minister of School Education of Tamil Nadu Shri Anbil Mahesh Poyyamozhi along with hon. MPs and officials met the Union Minister of Education Shri Dharmendra Pradhan in person and placed this demand. The hon. Minister informed them that the funds would only be released if the Tamil Nadu Government gives a written signed assurance that the NEP would be implemented in Tamil Nadu. I strongly

condemn this blackmail tactics of the Government. I urge that Samagra Shiksha Scheme funds should be released immediately.

Hon. Chairman Sir, this Budget is a big disappointment for farmers. They wanted that a law should be legislated as regards the Minimum Support Price for their hard-earned produce. But this Government does not seem to pay attention to their demand. This Government has reduced funds meant for food subsidy and fertilizer subsidy. The farmers throughout the country are shocked due to this decision of the Government. The allocation for MNREGA was not increased. The same amount of funds is allocated to this 100 day employment scheme as it was done in the previous years. Adequate funds have not been allocated for education. Last year Rs 45,234 crore was allocated for education and only an amount of Rs 38,416 crore was spent by them. They have approximately Rs 7,000 crore of unspent account. This is a matter of concern. This year they have announced Rs 46,315 crore. Will they spend the whole allocated amount is another question mark? Hon Chairman Sir, the Department of Higher Education has seen a drastic cut in fund allocation by Rs 10,000 crore. I not only condemn this reduction but also, want this amount that is reduced should be allocated again. The IITs have seen a reduction of Rs. 60 crore in their fund allocation this year.

Hon. Chairman Sir, during last December this Government passed so many legislations after suspending many Opposition MPs. It includes three Acts relating to criminal procedure. Article 348 of the Constitution clearly states that all these Acts and their names and titles should be in English. But why the name of IPC was given as Bharatiya Nyaya Sanhita? The people of this country are questioning you why the law relating to Criminal Procedure Code was renamed as Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. Why is it so? And the Indian Evidence Act has been named as Bharatiya Sakshya Adhiniyam. People of India are questioning this use of Sanskrit names in these three Acts. Hon Ministers should reply. This is against the Constitution of India. This is against Article 348 of the Constitution. This should be given up. I urge that all these three revised laws should be repealed. On 26th of this month and today the 29th of July 2024, so many advocates from Tamil Nadu have held agitations in Delhi stressing their demand to withdraw these Acts. I also want to stress in this august House that all the three criminal procedure Acts should be withdrawn and the old Acts should be in their place. Hon. Chairperson Sir, there is a separate Ministry for Social Justice. Almost 80 per cent of our population is looked after by this Ministry. In Tamil Nadu we have a separate Ministry for the welfare of the Adidravida people. Similarly, there are separate Commissions for SCs and STs at

the national level. They are called as National Commission for Scheduled Castes and National Commission for Scheduled Tribes. I urge that a separate Ministry should be created for the Scheduled Castes and another separate Ministry for the Scheduled Tribes. There should be a separate Ministry for the differently-abled persons as well. I urge that there should also be a separate Ministry for Minorities.

Atrocities against the SCs and STs have risen throughout the country. Atrocities against women have also increased. Uttar Pradesh is affected very much because of honour killing and this is spreading towards the southern States. I urge upon the Union Government that a separate law should be enacted to check and prevent honour killing in India.

There is an important demand about post-matric scholarship. They came with a proposal in the year 2019 to scarp this scholarship from 2018 onwards. On behalf of Viduthalai Chiruthaigal Party, we opposed this decision. We met the then hon. Union Minister in this regard and stressed that Post-matric scholarships should be continued without any timeline. Then they said Rs. 35,000 crore would be allocated till the year 2025. If it is so, then every year Rs. 7,000 crore should have been allocated. But they have not done so. Even now it is unknown that on what criterion, they have allocated funds for this scheme. Since the students will be studying generation after generation, no timeline should be fixed for such a scholarship scheme. I am duty-bound to urge that these Post-matric scholarships should be continued for long with adequate allocation. Under SC Sub-plan and ST Sub-plan, funds should be allocated in proposition to their population. In India, the SCs constitute 15 per cent of the population. The total outlay of this Budget is Rs 48, 20, 000 crore. And only 2 lakh crore have been allocated in this Budget. As per proportionate allocation it should have been more than Rs 7 lakh crore for the SCs. Not only for SCs, even the STs and the Minorities should get allocation of funds in proportion to their total population. This is my pertinent demand to the Union Government.

As mentioned by our hon. Leader of the Opposition, the people belonging to the marginalised sections of our society particularly, the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, OBCs, Minorities, Differently-abled are all ignored by this Government in this Budget. I want to submit that such a Government will not last long for a full term of five years. I want to give you a warning in this regard. You should not only engage in appeasing your coalition partners but you should also

show concern towards the interests of the working class. With this I conclude. Thank you.

श्री विजय कुमार हाँसदाक **(**राजमहल**) :** सर, मैं अपनी पार्टी जेएमएम की तरफ से इस बिल को अपोज़ करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं इस सदन में तीसरी बार आया हूं और मुझे लगता है कि जितनी बार जीतते हैं, उतनी ही जिम्मेदारी बढ़ती है । यहां पर इस सरकार का 11 वां बजट पर पेश हुआ है, मुझे लगता है कि वह जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की तरफ से बिल्कुल नहीं दिख रही है । हां, एक चीज बिल्कुल समझ में आई है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक्स्ट्रा टू एबी वाला बहुत दिन से सुन रहे थे, इस बार आंध्र प्रदेश और बिहार को जो मिला है, हमको वह टू एबी इस बार समझ में आया है । आंध्र प्रदेश में बीजेपी लेड गवर्नमेंट द्वारा वहां पर नई सरकार बनने के बाद जितने लोगों को मारा गया, जितने लोगों ने आत्मदाह किया, सुसाइड किया, उसका भी आंकड़ा देखना चाहिए । हमारे मुख्य मंत्री को 5 महीने से ऊपर जेल में रखा गया । हम दोनों तरह के चरित्र का कंपेरिजन दिखाना चाहते हैं कि एक सरकार क्या करती है और हमारे सीएम 5 महीने अंदर रहने के बावजूद, वहां पर कुछ नहीं होता है, फिर भी वह ऑफिस रिज्यूम करके जनता के लिए काम करना स्टार्ट करते हैं ।

सर, टैक्स स्लैब में जो घटाया गया है, उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि चमत्कार हो गया है । हमारे यहां वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पेइंग टैक्स सिस्टम है । इनकम टैक्स के ऊपर टैक्स, जो चीजें खरीदते हैं, उस पर टैक्स लगाते हैं, कोई बचत करते हैं, उसमें टैक्स लगता है, कुछ बेचना चाहते हैं, उस पर टैक्स लगता है । इतना हाईएस्ट पेइंग टैक्स सिस्टम होने के बावजूद टैक्स स्लैब में जो कटौती की गई है, उसके बाद जो पीठ थपथपाई जा रही है, मैं इसको चमत्कार ही कहूंगा । हर बार जीडीपी की बात की जाती है । मुझे जीडीपी की ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन जितना सुनता हूं, मुझे उससे समझ में आता है कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है और हमारे यहां जो इकोनामिक सिस्टम रन करता है, प्रत्येक वर्ष या पांच साल में इकोनामिक ग्रोथ क्या होनी चाहिए, वह प्रेडिक्शन यहां के अर्थशास्त्री कर देंगे । उसके एक्सपर्ट सदन में बहुत लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे यहां की जीडीपी क्या है, हमारे यहां पब्लिक सेक्टर किस तरह से ग्रोथ कर रहा है, हम यहां से क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे यहां कितना जॉब क्रिएशन हो रहा है, इन सब चीजों पर अगर हम बोलेंगे और उसके बाद हम कहेंगे कि हमारे यहां कुछ बढ़िया हो रहा है, तब हमको समझ में आएगा । हमने इतने घंटे का बजट सुन लिया, लेकिन समझ में नहीं आया कि आखिर में क्या हो रहा है । तीसरी बार की सरकार बनने के बाद अगर अभी भी आप इसी तरह से घुमाते रहेंगे और देश को गर्त में ले जाते रहेंगे तो फिर जिम्मेदारी आपकी ही है ।

सर, झारखंड की तरफ से हम देश को सबसे ज्यादा माइनिंग देते हैं और हर एक चीज देते हैं । जितनी माइनिंग होती है, जितनी उसकी रॉयल्टी है और हमारा जितना बकाया पड़ा हुआ है, हम उसकी कई वर्षों से मांग कर रहे हैं । अगर हमें वही मिल जाए तो हम अपने झारखंड का विकास कर लें । जब पीएम आवास की बात की गई तो हमारे यहां पीएम आवास रोका गया । अगर आप पीएम आवास ही दे देते । वहां पीएम आवास बंद होने के बाद हम लोगों ने झारखंड में अपना अबुआ आवास योजना शुरू की । ऐसी कई योजनाओं में झारखंड को अनदेखा किया जा रहा है । मैं कहूंगा कि हमारे यहां की हेमंत सरकार से सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से वहां की कल्याणकारी योजनाएं हैं । वह पांच महीने जेल में रहने के बाद बाहर निकले और किस तरह से लगन के साथ लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आप वहां की हर एक योजना निकालकर देखिए और उनसे सीखने की जरूरत है ।

सर, यहां पर बांग्लादेश का बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा था । मैं राजमहल लोक सभा से बिलॉन्ग करता हूं । यहां पर राजमहल लोक सभा का नाम कई बार लिया गया है और झारखंड में बांग्लादेशी प्रभाव का नाम लिया गया है । आप वहां की इकोनॉमी और यहां की इकोनॉमी को भी थोड़ा समझाएं । बंगाल और बांग्लादेश हमारे बगल में

ही है । हमारे यहां से कई टन्स में पत्थर जाता है । वह अपनी शोर लाइन हमारे यहां के पत्थर से बना रहे हैं । पूरे विश्व की क्लॉथ इंडस्ट्री वहां पर जाकर बस गई है । वहां की जीडीपी क्या है और हमारे यहां की जीडीपी क्या है, उसको समझ लीजिए । वहां से लोग हमारे यहां क्यों आएंगे? आज जो इकोनॉमी बांग्लादेश की है, उसकी वजह से उल्टे हमारे यहां से लोग नौकरी लेने के लिए जाएंगे । आपने देश की जो स्थिति यहां पर बना रखी है और कोई जॉब क्रिएशन भी नहीं है । कोविड के बाद से अभी तक जॉब क्रिएशन के साथ एक तुलनात्मक बात होनी चाहिए कि कितनी जॉब्स का नुकसान हुआ और प्रत्येक वर्ष आपने कितनी नई जॉब्स क्रिएट कीं? पुरानी न बताएं, बल्कि ये बताएं कितनी नई जॉब्स क्रिएट कीं, उस पर बात होनी चाहिए । सिर्फ आंकड़ों का खेला खेलकर यहां पर पूरे देश को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है । जहां तक बांग्लादेश की बात की जा रही है तो हमारे यहां गोड्डा में जो पावर प्लांट है, वहां से पूरे बांग्लादेश के लिए बिजली जा रही है, लेकिन हमारे यहां झारखंड के लिए कुछ नहीं मिल रहा है । बांग्लादेश की स्थिति हम से बहुत बढ़िया है ।

मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से झारखण्ड में लगातार माइनिंग हो रही है । रेलवे को हम जितना दे रहे हैं, उसकी बनिस्पत जितना हम लोगों को मिल रहा है, उसका रिजल्ट आपको झारखण्ड स्टेट के रिज़ल्ट से समझ में आ रहा होगा कि जितना वहां के आदिवासियों और गैर आदिवासियों ने झारखण्ड में बीजेपी और बीजेपी के एलाइंस को नकारा है । यह बात उनको समझ में आनी चाहिए । वे लगातार जो गलती कर रहे हैं, उसको उन्हें सुधारना चाहिए । दूसरा, मैं यह कहना चाहूंगा कि पूरे बजट को देखने के बाद मैं यह कह सकता हूं कि यह बजट न युवाओं के लिए है, न यह किसानों के लिए है और न महिलाओं के लिए है । मैं यह कहना चाहता हूं कि आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि विश्व गुरू और भगवान बनने से अच्छा है कि आपको देश ने जो बनाया है, वह बनकर के सही ढंग से इस देश के लोगों के लिए काम कीजिए । आपको जो जिम्मेदारी दी गयी है, उसको ठीक ढंग से पूरा कर लीजिए क्योंकि तीसरी बार आपको जनता ने यहां बैठाया है तो आपकी कुछ जिम्मेदारी है । आप भगवान का नाम लेते हैं, जितने धार्मिक स्थल हैं या धार्मिक इम्पोर्टेंस की एमपी सीट्स हैं, उन सबको आपने लूज़ किया है । आपको ऊपर वाला जो संदेश दे रहा है, अगर वह भी आप समझ नहीं पाए तो हम इंसान जो यहां बैठे हैं, वह क्या आपको समझा पाएंगे । धन्यवाद ।

श्री राजू बिष्ट **(**दार्जिलिंग**) :** धन्यवाद सभापति महोदय । आपने मुझे वर्ष 2024-25 के बजट पर बोलने का समय दिया । मैं दार्जिलिंग की जनता का भी आभारी हूं जिन्होंने मुझे दूसरी बार उनकी आवाज इस सदन में बनने का मौका दिया । मैं आदरणीय प्रधान मंत्री मोदी जी को और वित्त मंत्री सीतारमण जी को कि बजट में हर पहलू को ध्यान में रखकर के बजट तैयार किया गया है । बजट में युवाओं की बात की गयी है । यूथ स्किलिंग, इम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें अर्बन डेवलमेंट भी है और रूरल डेवलपमेंट भी है, इनोवेशन, मैन्युफेक्चरिंग और विमिन लेड डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है । भारत युवाओं का देश है और आज का युवा कल का भारत है । युवाओं के रोजगार और स्किलिंग के लिए भारत सरकार दो लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी । पांच साल में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का इसमें लक्ष्य रखा गया है । भारत की 500 फॉर्च्यून कम्पनियों में उनको एक साल की ट्रेनिंग भी मिलेगी और स्टाइपंड के नाते पांच हजार रुपये प्रति माह भी मिलेगा । जिन युवाओं को पहली बार नौकरी मिलेगी, उनको भारत सरकार 15 हजार रुपये डायरेक्ट भारत सरकार देने का काम भी करेगी । इतना ही नहीं हायर एजुकेशन के लिए दस लाख रुपये तक का लोन भी मिलेगा और जिसका तीन परसेंट ब्याज, जो लगभग 40 परसेंट हो जाता है, वह भारत सरकार भरेगी । इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है जिसके लिए 11 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का आवंटन किया गया है और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत तीन करोड़

नये घर बनेंगे । प्रधान मंत्री आवास योजना अर्बन के अंतर्गत एक करोड़ घर बनेंगे, जिसके लिए 10 लाख करोड़ रुपये का खर्च भारत सरकार करेगी । पीएमजनमन योजना के तहत 24104 करोड़ रुपये जनजातीय विकास के लिए रखे गए हैं । मैं प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि पहली बार चाय बागान के बारे में इस बजट में कहा गया है । नॉर्थ बंगाल और असम के चाय बागान में काम करने वाले श्रमिक, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं, उनके बच्चों की एजुकेशन और देखरेख के लिए एक हजार करोड़ रुपये का आवंटन बजट में हुआ है । मैं नॉर्थ बंगाल और असम की जनता की ओर से प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा ।

महोदय, मैं अब बंगाल की बात करना चाहता हूं । आजादी के समय बंगाल बेस्ट बंगाल था । उसको टीएमसी ने आज सबसे वर्स्ट बंगाल बना दिया है । ? (व्यवधान) आप चिल्लाते रहो, मैं आंकड़े बताता हूं । ? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please address the Chair and talk only on the Budget.

श्री राजू बिष्ट **:** महोदय, मैं बजट पर ही बोल रहा हूं ।

जो काम ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, आज टीएमसी भी पंश्चिम बंगाल के साथ वही व्यवहार कर रही है । वहां पर अनेक योजनाएं, जिनमें चाहे मनरेगा हो, स्वच्छ भारत हो, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना हो, आवास योजना हो, आरआईडीएफ का फंड हो, मुफ्त राशन हो या चाहे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड हो, हर जगह घोटाला है । यहां तक इन्होंने शिक्षा को भी नहीं छोड़ा है । ? (व्यवधान) अभी ओलंपिक चल रहा है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर आज करप्शन के ऊपर ओलंपिक में कॉम्पिटिशन होता तो टीएमसी को गोल्ड मेडल मिलता । हम ईज ऑफ डुइंग की बात करते हैं, लेकिन ईज ऑफ डुइंग करप्शन में टीएमसी नम्बर वन है । ? (व्यवधान)

पश्चिम बंगाल को सात लाख करोड़ रुपये का कर्जा टीएमसी की देन है । पश्चिम बंगाल में 35 सालों तक सीपीएम शासन में थी । उस समय 1 लाख 90 हजार करोड़ रुपये का कर्जा था आज वह बढ़कर 7 लाख करोड़ रुपये का हो गया है । मैंने टीएमसी से एक रुपया नहीं लिया, लेकिन मेरे ऊपर 70 हजार रुपये का कर्जा इन्होंने डाला है । पश्चिम बंगाल की मंथली पर-कैपिटा कंजम्पशन नॉर्थ ईस्ट के आठों स्टेट्स से भी कम है । इन्हें शर्म आनी चाहिए ।

आजादी के समय पश्चिम बंगाल की मैन्युफैक्चरिंग 30 परसेंट कंट्रीब्यूट करती थी, जो आज 3 परसेंट से भी कम रह गई है । यह भी इन्हीं की देन है । यह कहते हैं कि केन्द्र सरकार इनको पैसे नहीं देती है । मैं इनको डेटा के साथ कहना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री आवास योजना, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना और मनरेगा, हालांकि मैं आपके सामने मनरेगा का आँकड़ा रखना चाहता हूँ । यह बड़ा मैजिक नम्बर है ।

आधार लिंक होने से पहले मनरेगा के 3.88 करोड़ कार्ड थे और जैसे ही आधार लिंक हो गया तो ये सिर्फ 2.5 करोड़ रह गए । ? (व्यवधान) यानी 1 करोड़ 35 लाख फर्जी कार्ड बांग्लादेशी नागरिकों के बने थे । इतना ही नहीं चौबीस परगना जिले में मनरेगा के 38 लाख कार्ड थे और आधार लिंक होते ही 15 लाख विलुप्त हो गए । इसी तरह मुर्शिदाबाद में 33 लाख मनरेगा के कार्ड थे, जिनमें से 13 लाख आधार लिंक करते ही गायब हो गए । यह हकीकत है ।

चाहे चिटफंड घोटाला हो, टीचर घोटाला हो, पीडीएस घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, मनरेगा, आवास योजना, हर घर जल, गाय की तस्करी, सभी घोटालों में टीएमसी लिप्त है । यहां तक कि टीएमसी के शासन में मुख्य मंत्री की पेंटिंग का भी घोटाला हो गया । मैं इनके एक नेता को सुन रहा था । उन्होंने नॉर्थ बंगाल की बात की । मैं उसे भी आपके समक्ष रखना चाहूंगा । नॉर्थ बंगाल में आठ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनकी आबादी करीब-करीब तीन करोड़ है

। हम रिसोर्स में भी रिच हैं और पश्चिम बंगाल को सबसे बड़ा रेवेन्यू भी नॉर्थ बंगाल देता है । हमारे पास चाय है, ट्रेड है, हाइड्रो है, टूरिज्म है और फॉरेस्ट भी है । इतना कुछ होते हुए भी और हमारा कंट्रीब्यूशन होते हुए भी पश्चिम बंगाल का सालाना बजट 3.88 लाख करोड़ रुपये का है, लेकिन नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट बोर्ड को 860 करोड़ रुपये मिलते हैं । शायद दीदी को पता भी नहीं होगा, यह पूरे बजट का 0.002 परसेंट है ।

हमारे चाय बागान बंद हो रहे हैं । हमारे सिनकोना बागान बंद हो चुके हैं । इन्होंने सिर्फ नॉर्थ बंगाल को ठगा है और हमें लूटा है । ? (व्यवधान) नॉर्थ बंगाल के लोग स्वाभिमानी हैं । हम अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं । इतना ही नहीं इन्होंने कहा कि बजट में पश्चिम बंगाल को कुछ नहीं मिला है । मैं आपके सामने कुछ आँकड़े लेकर आया हूँ । बजट में 93 हजार करोड़ रुपये सिर्फ पश्चिम बंगाल को मिल रहा है, जो कि महाराष्ट्र से ज्यादा है । डेढ़ लाख करोड़ रुपये इंटरेस्ट फ्री, आपको 50 सालों तक ब्याज नहीं देना है, यह पश्चिम बंगाल के लिए भी है ।

?पूर्वोदय योजना?, जिसके अंतर्गत अमृतसर से लेकर कोलकाता तक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा, जिसमें पश्चिम बंगाल के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे । एक करोड़ अर्बन हाउसिंग बनेंगे, जिसमें कोलकाता, दुर्गापुर, आसनसोल, सिलीगुड़ी जैसे शहरों को इसका लाभ मिलेगा । दो करोड़ आवास बनेंगे और इतना ही नहीं रेलवे की तरफ से 14 हजार करोड़ रुपये आवंटन हुए हैं और ऑलरेडी 60 हजार करोड़ रुपये के रेलवे के काम पश्चिम बंगाल में चल रहे हैं । 100 नए अमृत स्टेशन बनेंगे, जिसमें सिलीगुड़र और जलपाईगुड़ी भी है ।

अब मैं तीस्ता फ्लड की बात करता हूँ । इनके एक नेता ने कहा था कि तीस्ता फ्लड के दौरान सिक्किम को पैसे मिले, लेकिन पश्चिम बंगाल को कुछ नहीं मिला ।

सर, हकीकत यह है कि अक्टूबर, 2023 में जैसे ही फ्लड आया तो सिक्किम ने इसको डिजास्टर घोषित किया और एसडीआरएफ एवं एनडीआरएफ का 10 प्रतिशत पैसा वहां की जनता को मिला, लेकिन पश्चिम बंगाल ने डिजास्टर घोषित नहीं किया, तो हमारी जनता को कुछ नहीं मिला । मैं इस बजट के लिए वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि इसमें 11,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसमें से बंगाल को 1200 करोड़ रुपए मिलेंगे ।

मैं आपके माध्यम से बंगाल सरकार से निवेदन करता हूं कि तीस्ता फ्लड पीड़ितों को यह पैसा मिले । सर, मैं अपने कुछ क्षेत्रों की दो-तीन बातें आपके समक्ष रखूंगा । दार्जिलिंग हिल्स, तराई और दुआर्स लंबे समय से एक स्थायी राजनीतिक समाधान की मांग करती आई हैं । इसके कारण अतीत में कई आंदोलन हुए हैं । वर्ष 1986-88 के आंदोलन के माध्यम से दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल बना । वर्ष 2007 से वर्ष 2011 के आंदोलन के कारण गोरखालैंड टेरिटेरियल एडमिनिस्ट्रेशन बना । जो सेमी-ऑटोनोमस बॉडी थी, उसको पश्चिम बंगाल ने चलने नहीं दिया । हमारे क्षेत्र में आए दिन बहुत तेजी से डेमोग्राफी चेंज हो रही है । हमारा इलाका बहुत सेंसिटिव है, जिसमें बांगलादेश, नेपाल, भूटान और बगल में चाइना भी है । वोट बैंक के कारण बांगलादेशी और रोहिंग्या आए दिन चाय बागान में अपना घर बना रहे हैं ।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि आज हमारे मुल निवासी गोरखा, आदिवासी, कोच, मेचे, राभा, टोटो, राजबंशी, बंगाली भाषी और हिन्दी भाषी समुदाय खतरे में हैं । इसीलिए इस क्षेत्र का स्थायी समाधान भारत के संविधान के अंतर्गत हो, जिसमें टीएमसी का कोई हस्तक्षेप न हो । गोरखा समुदाय में 11 जनजातियां जो आजादी के समय, वर्ष 1951 के सेंसस तक ऑलरेडी हिल ट्राइब के रूप में जानी जाती थीं, जिनमें, भुजेल, गुरूंग, मंगर, नेवार, जोगी, खस, राई, सुनुवार, थामी, याखा यानी देवान और धीमाल थीं । ये वर्ष

1931, 9141 और वर्ष 1951 के सेंसस में भी जनजाति थे । मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इनको जनजाति का दर्जा जल्द से जल्द मिले ।? (व्यवधान)

सर, इसका एक बड़ा कारण है कि भारत-नेपाल एक मित्र देश है ।? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please conclude the speech. You have spoken for more than 10 minutes.

श्री राजू बिष्ट **:** वर्ष 1950 की इंडो-नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी की धारा सात के अंतर्गत जो भी भारतीय गोरखा हैं, वे नेपाली कहे जाते हैं । वे नेपाल के सिटिजन कहे जाते हैं । इससे हमें बहुत पीड़ा है । आए दिन हमारे जवान भारत मां की सेवा करते हुए शहीद होते हैं ।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें जनजाति का दर्जा मिले । तीस्ता बाढ़ पीड़ितों को उनका अधिकार मिले ।? (व्यवधान)

श्री उज्ज्वल रमण सिंह **(**इलाहाबाद**) :** सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मैं इलाहाबाद की धरती, जहां से पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे लोग प्रधान मंत्री बने । जिसने हरिवंश राय बच्चन, फिराक गोरखपुरी, अकबर इलाहाबादी, धर्मवीर भारती और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे विश्व विख्यात कवि और शायर देश को दिए हैं । आज इस सरकार द्वारा कुर्सी बचाओ बजट पेश किया गया है, मैं इस पर चार पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं :

डबल इंजन वाले डर गए,

चुनावी वायदे से मुकर गए

कुर्सी की लोभ में मर गए

और गिरने की हर हद से गुजर गए ।

सरकार का यह हाल है । भारत के इतिहास में इतना दिशाहीन बजट कभी नहीं आया । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ कुर्सी बचाना है । इस बजट में देश हित में कोई ऐसा काम नहीं किया गया है । इसमें कोई ऐसा काम नहीं बताया गया है, इसमें ऐसी कोई एक दिशा नहीं बताई गई है, जिससे देश आगे बढ़ सके । यह अपनी नीतियों और कार्यक्रमों का नहीं बल्कि केवल जो सरकार के सहयोगी हैं, उनके कहने पर उनको बचाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने का बजट है । यह बजट केवल अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने का बजट है । इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र में पैसे कम किए गए हैं । यह दुखदायी और पीड़ादायक है । आप शिक्षा को जीडीपी का मात्र ढ़ाई प्रतिशत दे रहे हैं, लेकिन चाइना इसमें पांच प्रतिशत दे रहा हैं । चाइना में 56,600 करोड़ रुपए शिक्षा पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन भारत में शिक्षा पर 1440 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं । फर्क एक प्रतिशत का है, लेकिन एक प्रतिशत का फर्क 40 हजार करोड़ रुपए का फर्क लाता है । आप शिक्षा को खत्म करके देश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं । मैं एक लाइन इसके बारे में कहना चाहूंगा ।

इल्म बढ़ाता है उसको घटा सकता नहीं

ये वह दौलत है, जो कोई चुरा सकता नहीं है ।

अगर आप अपने नौजवानों को, अपने देशवासियों को अच्छी शिक्षा देते, अगर आप शिक्षा का बजट 6 परसेंट जीडीपी पर ले जाते तो कहीं न कहीं यह देश आगे बढ़ता । लेकिन इस सरकार ने इसको कम करने का काम किया है । इसका फोकस शिक्षा नहीं है । इसका फोकस स्वास्थ्य नहीं है । स्वास्थ्य का यह हाल है कि अगर आप प्रयागराज में बीमार हो जाए तो उसको कोई अस्पताल नहीं मिलता है । आप पूरे देश में एम्स बनाने की बात करते हैं, लेकिन आप प्रयागराज को एम्स देने की बात नहीं करते हैं । प्रयागराज के साथ, पूरे उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया गया । उत्तर प्रदेश को विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए था । चाहे बुंदेलखंड का क्षेत्र हो, चाहे पूर्वांचल का इलाका हो, वह पूरे देश में सबसे पिछड़ा हुआ है । अगर आप लोगों ने वहां विशेष पैकेज दिया होता, तो आज आपकी यह दशा नहीं होती, पूरा बुंदेलखंड हारने का काम किया और पूरा पूर्वांचल हारने का काम किया । इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं । ? (व्यवधान) साथियो, सुनने का भी माद्दा रखिये ।

हम चीन से मुकाबला करने की बात करते हैं । एजुकेशन पर खर्च लगातार कम होता जा रहा है । ऐसी दशा में मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा कि सरकार आम आदमी का दर्द नहीं समझती है । आम आदमी की शिक्षा और विकास पर ध्यान नहीं देती है । अपनी कुर्सी बचाने की यह चाहे जितनी कोशिश कर लें, जनता की जब आह निकलती है, तो बड़ी-बड़ी हुकूमतों को हिला देती है । आपको समझना चाहिए कि जनता की आज आह निकल रही है । आज मध्यम वर्ग कराहा रहा है । जिस तरीके से आप इंडेक्सेशन खत्म कर रहे हैं, आपने उसे लगाकर खत्म किया । आप पिछले रास्ते से इनहेरिटेंस टैक्स लाने का जो प्रयास कर रहे हैं, मध्यम वर्ग इस चीज को समझता है । आज मध्यम वर्ग परेशान किससे है? वह इनफ्लेशन से परेशान है, नौकरी न मिलने से परेशान है । उसके बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, वह उससे परेशान है । आज किसान किस चीज से पेरशान है? आप एमएसपी की जो लीगल गारंटी नहीं दे रहे हैं, इससे किसान परेशान हैं । लेकिन यह सरकार इस बात का दर्द समझने को तैयार नहीं है ।

मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा । मैं प्रयागराज की धरती से आता हूं, वहां पर नैनी इंडस्ट्रियल एरिया है । जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा था कि इंडस्ट्रियल एरिया को रिवाइव करने का काम करेंगे । वर्ष 2014 से 2024 आ गया, एक भी इंडस्ट्री को पुनर्जीवित करने का काम इस सरकार ने नहीं किया । मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर आप दोहरा रुख अपनाएंगे, सौतेला व्यवहार अपनाएंगे तो कहीं न कहीं जनता आपको दंडित करने का काम करेगी । कोल जाति को जनजाति का दर्जा देने की बात मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी की सरकार ने कही थी । उसका प्रस्ताव भेजा था । लेकिन आपकी सरकार ने कोल को जनजाति का दर्जा देने की बात नहीं की । मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी की सरकारों ने 17 जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की विधान सभा में पास करके भेजा था । लेकिन इस सरकार ने 17 जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया । मैं बस अंत में एक बात कहकर, नज़ीर अकबराबादी का एक शेर कहकर कुर्सी बचाओ सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं और मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं । नज़ीर अकबराबादी का शेर है, जो मैं आपके बीच रख रहा हूं?

?क्या मसनद तकिया मुल्क मकाँ क्या चौकी कुर्सी तख़्त छतर

सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा ।?

इसलिए साथियों, मैं इस सरकार को कहना चाहूंगा, जो किसान विरोधी बजट है, नौजवान विरोधी बजट है, महिला विरोधी बजट है, जो शोषित और वंचित वर्ग के खिलाफ बजट है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं

। हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं, देश में जनगणना की बात करते हैं । ? (व्यवधान) महोदय, इसके साथ आपका आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री नरेश गणपत म्हस्के **(ठाणे) :** महोदय, आज बजट पर हो रही चर्चा में मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । सर्वप्रथम मैं महाराष्ट्र के गौरव छत्रपति शिवाजी महाराज, भारत रत्न डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर जी, महात्मा फुले जी, हिन्दू हृदय सम्राट, शिव सेना प्रमुख माननीय बाला साहेब ठाकरे जी को नमन करता हूं ।

मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे गुरुवर धर्मवीर आनंद दीघे साहब को, मैं हमारे पंत प्रधान नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, हमारे पार्टी के नेता, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को, जिन्होंने मुझे इस सदन का सदस्य बनने का सौभाग्य दिया । मैं अपने क्षेत्र ठाणे की जनता को कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे नगर सेवक, महापौर और अब सांसद बना दिया ।

माननीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने देश का जो अर्थ-संकल्प पेश किया है, वह देश को विकास की तरफ लेकर जाने वाला है, इसलिए मैं उनका अभिनन्दन करता हूँ ।

After the presentation of this Budget 2024-25, the opposition leaders have been discussing about it inside and outside this house. A few members from Maharashtra have also joined them. They say, this budget is meant to protect and secure this Government and it is only to please particular states only. But I want to tell them that this budget is also for the states ruled by opposition parties. When this Government declare various schemes, it does not mean that only BJP ruled States will only benefit, around 4.1 crore youths from other states would also be benefitted during next 5 years. This budget will be useful for all the youths of our country.

इस योजना से महाराष्ट्र के गांव का बच्चा भी माइक्रोसॉफ्ट और गूगल में इंटर्नशिप करेगा और बंगाल का बच्चा भी उसमें शामिल होगा । जो एक्सप्रेसवे बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, 11 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्या उससे सिर्फ हम लोग लाभान्वित होंगे? इससे समाज का हर व्यक्ति लाभान्वित होगा, जिसने इस सरकार पर भरोसा किया है । The INDIA Alliance leaders are constantly criticizing this budget.

लेकिन इनकी सोच अंग्रेजों वाली ही है । वे कहते थे- ?डिवाइड एंड रूल ।? ये लोग उसे डिवाइड एंड रूल एंड फूल के रूप में आगे लेकर जा रहे हैं । मतलब यह है कि जनता को पहले धर्म के नाम पर बांटो, जाति के नाम पर और अब बजट के नाम पर ।

When they were taking the oath, everybody was uttering the Slogans, ?Jai Samvidhan, Jai Samvidhan'. But, if we refer to historical incidents, we will come know how they had suppressed constitution. The then Prime Minister of India, Shri

Rajiv Gandhi did not implement the Mandal Commission Report. They dismissed around 99 State Governments using Article 356. They toppled the Sharad Pawar Govt in 1980 and imposed President's Rule. On the other hand, only NDA saved and secured constitution. We supported to implement Mandal comission Report in 1989. In the year 2001, we amended Article 16 and changed the Supreme Court verdict. We strengthened the SC, ST Act in 2018 and changed the Supreme Court decision once again.

आपकी बारी आयी, तो आपने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सिर्फ एक समाज के लिए, उनको खुश करने के लिए चेंज किया और हमारी मुस्लिम बहनों के साथ नाइंसाफी की । इसलिए संविधान की रक्षा करने की बात वे न करें, जो संविधान का चीरहरण करने की बात करते थे ।

They are sloganeering for Constitution without reading it. Same way they are criticizing the budget even without going through it. Few people from Maharashtra are criticizing it without any reason. They know very little about it and they had accepted it earlier. You are saying that nothing has been allocated to Maharashtra. But on the contrary, around Rs 78,000 crore will be given to Maharashtra through Central Tax Collection. Rs 600 crore package has been declared for Vidarbha and Marathwada. It would help in stopping farmers' suicides in these regions. For Rural roads Rs 400 crore, for Dedicated Economic Corridor Rs 466 crore, for MUTP Rs 3,908 crore, for Mumbai Metro Rs 1087 crore, Rs 683 crore for Nagpur Metro, Rs 814 crore for Pune Metro, for Nag River Rejuvenation Rs 500 crore, for Mula-Mutha River conservation 790 crore and other schemes worth crores of rupees have also been declared in this budget.

Around Rs 15,940 crore has also been allocated for Railways in this year?s budget. Railway projects worth Rs 1 lac crore are being implemented in Maharashtra. These projects would benefit the people residing in all the Lok Sabha constituencies in Maharashtra. But still they are asking what has been given to Maharashtra.

Our hon. Prime Minister had given priority to Maharashtra earlier too. Rs 10.5 lac crore have been given to Maharashtra for the various projects like road construction, railway projects, railway station upgradation, Vadhavan Port Project, Mumbai- Ahmedabad Bullet Train, Airport development, Air connectivity, Samruddhi Mahamarg, Mumbai Coastal Road, Atal setu; Mumbai, Pune, Nagpur Irrigation projects etc. These projects were materialized and implemented just because of his kind help. Our hon. Home Minister has also helped to solve the problem of taxes worth Rs 6,000 crore imposed on Sugar Mill.

They are determined not to acknowledge these great works done by our Govt. They are not ready to accept reality.

सभापति महोदय, कांग्रेस को दस वर्षों के बाद विपक्ष के नेता का आधिकारिक पद मिला है । इसके लिए आपको बधाई है और उम्मीद है कि आप अगले कई वर्षों तक उस पद की गरिमा बढ़ाएंगे, क्योंकि आपका आर.ए.सी. टिकट है, जो कभी कन्फर्म नहीं होने वाला है । विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी हैं । ? (व्यवधान) सुबह मैंने देखा, मैं एक नया खासदार हूं, राहुल का अर्थ होता है ? भगवान बुद्ध का पुत्र । लेकिन, यहां तो अलग ही लग रहा था । वे अपने नेतृत्व में पूरे देश में भ्रम फैलाने की बातें कर रहे हैं ।

पहले आलू डालकर सोना निकालने की बात की, फिर अभय मुद्रा की बात की । नेताजी, सदन की गरिमा को समझिए । यह किसी पार्टी का कार्यालय नहीं है, यह संसद है । यह तो बचपना है, विपक्ष के कुछ लोग बचपना कर रहे हैं । मैं तो नया आदमी हूं, पहली बार खासदार बना हूं । यह सब देखते हुए मुझे अपना महानगर पालिका का सभागृह याद आया । मेरे यहां कभी भी विपक्ष के नेता लोगों ने इस तरह का बचपना नहीं किया ।

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please conclude the speech.

? (*Interruptions*)

श्री नरेश गणपत म्हस्के **:** सर, बस दो मिनट का समय और दीजिए ।

This is "Rahu Kaal? under the leadership of Shri Rahul Gandhi. They cannot pacify this ?Raahu? from his Kundli, because these congressmen consider only one family as their nation.

?तुम्हारे पांव के नीचे कोई ज़मीन नहीं,

कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं ।?

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, it is 6 o?clock right now and I have a long list of speakers to speak on this important issue. If the House agrees, I extend the time of the House till 8 o?clock.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

HON. CHAIRPERSON: Okay.

Mhaske ji, you please conclude your speech now.

SHRI NARESH GANPAT MHASKE: You have completely failed in the Lok Sabha litmus test. Shri Narendra Modi once said that he did not know about the polities of lies.

HON. CHAIRPERSON: Now, Adv. Chandra Shekhar.

18.00 hrs

एडवोकेट चन्द्र शेखर **(**नगीना**) :** सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बजट पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया ।

महोदय, मैं अपनी बात को शुरू करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी सन्तों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं । इसके साथ-साथ मैं भारत की महान जनता को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बार लोकतंत्र की रक्षा की ।

सभापति महोदय, पिछले दस सालों में सरकार की नीतियों के कारण गरीब और गरीब हुआ है और अमीर और अमीर हुआ है, यानी गरीबों और अमीरों के बीच फासला बढ़ गया है । सारे देश की सम्पत्ति को चन्द अमीरों के हाथों में दे दिया गया है । यह हमारे संविधान की मंशा और समतावादी समाज के लक्ष्य के खिलाफ है । अत: हमारी नीतियां गरीबों के पक्ष में भी होनी चाहिए ।

महोदय, जातिगत जनगणना, जो आज एस.सी., एस.टी., ओबीसी यानी कि बहुजन समाज के लिए जीवन-मरण का प्रश्न है, इसके बारे में बजट में कोई बात नहीं कही गयी है । इसके बाद जनसंख्या के अनुपात में बहुजन समाज को सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, तभी बाबा साहेब अम्बेडकर का समतामूलक समाज का जो सपना है, वह पूरा होगा ।

महोदय, यह कैसा विकसित भारत है, जिसमें आज भी सफाई कर्मचारी को पक्की नौकरी नहीं मिल रही है और उसको गटर में उतरने को मजबूर किया जा रहा है । उनके लिए अलग-से कोई बजट नहीं है । अगर सरकार चाहे तो बजट बन सकता है । एस.सी., एस.टी. का जो सब-प्लान मिलता था, जो पैसे मिलते थे, उसे बजट से हटा दिया गया है । इसके साथ-साथ देश के स्तर पर आशा, आंगनवाड़ी, भोजन माता, ग्राम सेवक, पी.आर.डी. जवान, होमग्रार्ड्स के मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुई है । ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है कि उनके जीवन में खुशहाली आए । इनका मानदेय बढ़ना चाहिए ।

18.02 hrs (Dr**.** Kakoli Ghosh Dastidar *in the Chair*)

विधवा, वृद्ध, विकलांग पेंशन को 500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 5,000 रुपये किया जाना चाहिए क्योंकि महंगाई बढ़ रही है । देश में प्रधान मंत्री जन कल्याण योजना के तहत एस.सी., एस.टी., ओबीसी और मुस्लिम को कितने घर दिए गए, इसका कोई आंकड़ा सरकार के पास नहीं है । इसी तरह, एस.सी., एस.टी., ओबीसी के कितने परिवारों के लिए शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध करायी गयी? आज भी सिद्धार्थनगर और ऐसे तमाम जिलों में शौचालय की व्यवस्था नहीं है । इस पर ध्यान देना चाहिए ।

देश भर में एस.सी., एस.टी., ओबीसी के जो रिक्त पद पड़े हुए हैं, उन बैकलॉग पदों को भरना चाहिए । सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा ।

महोदया, यह कैसी विश्व की पाँचवी अर्थव्यवस्था है, जिसमें आज भी एस.सी., एस.टी. पर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है । अगर आप एन.सी.आर.बी. के डेटा को देखेंगे तो आपको खून के आँसू रोने पड़ेंगे । युवा बेरोजगार है । वह सड़कों पर है । 80 करोड़ लोगों को पाँच किलोग्राम राशन से जीवन-यापन करना पड़ रहा है । एस.सी., एस.टी. को जो बजट मिलता है, मेरे दायीं तरफ जो साथी बैठे

हैं, उन्हें यह सुनकर बुरा लगेगा कि कर्नाटक में इन्होंने 14,732 करोड़ रुपये दूसरी योजना में लगा दिए और मध्य प्रदेश में आपने 95,000 करोड़ रुपये दूसरे कामों में लगा दिए । भाई, हमें जो मिलता है, वह तो हमसे मत छीनो!

महोदया, इस बजट में एम.एस.पी. की लीगल गारंटी की कोई बात नहीं हुई है । किसानों को जो 6,000 रुपये मिलते हैं, उसे बढ़ाकर 12,000 रुपये करना चाहिए । प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का सारा प्रीमियम सरकार दे, उसका बोझ किसानों पर न हो ।

महोदया, प्रोमोशन में रिज़र्वेशन को लागू नहीं किया गया । पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया गया । इस पर चर्चा नहीं हुई । देश में मनरेगा समेत न्यूनतम मजदूरी की दर 700 रुपये होनी चाहिए । ?समान काम, समान वेतन? की पॉलिसी लागू होनी चाहिए । रसोई की चिंता करते हुए 500 रुपये प्रति सिलिंडर से ज्यादा दाम नहीं होने चाहिए, जिससे महिलाओं को राहत मिल सके । बिजली के दामों में भी कमी होनी चाहिए । बेरोजगार युवाओं को 5,000 रुपये भत्ता मिलना चाहिए, जिससे वे अपनी पढ़ाई का खर्च उठा सकें ।

महोदया, मैं अपने क्षेत्र के विषय में कहना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नगीना में एक एम्स बनना चाहिए, एक आई.आई.टी. बनना चाहिए, एक आई.आई.एम. बनना चाहिए । नगीना लोक सभा संसदीय क्षेत्र में उद्योग-धंधे लगने चाहिए । नगीना की कताई मिल को पुन: शुरू कराना चाहिए । सरकार की आर.आर.टी.एस. योजना को मेरठ से आगे बढ़ाकर मुज़फ्फरनगर, सहारनपुर से नजीबाबाद होते हुए नगीना तक ले जाना चाहिए । नजीबाबाद से मुम्बई के लिए एक ट्रेन चलनी चाहिए । नगीना, स्योहारा और किरतपुर में रेल ओवरब्रिज बनने चाहिए ।

सभापति महोदया, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को 13,000 करोड़ रुपये दिए गए और जनजातीय कार्य मंत्रालय को 13,000 करोड़ रुपये दिए गए । इन्हें कुल 26,000 करोड़ रुपये दिए गए, जो कुल बजट 48.20 लाख करोड़ रुपये का लगभग 0.54 प्रतिशत है जबकि एस.सी., एस.टी. की संख्या 25 प्रतिशत से ज्यादा है । अगर बहुजन समाज की जनसंख्या को भी मिलाएंगे तो यह 85 प्रतिशत से ज्यादा है और हमारे विकास के लिए सरकार बजट का मात्र एक प्रतिशत पैसे खर्च कर रही है, जबकि हमें 25 प्रतिशत पैसे मिलने चाहिए ।

यह ऊंट के मुंह में ज़ीरे के समान है । जो कहावत हमने बहुत पहले से सुनी है । पिछले लंबे समय से हमारे साथ धोखा हो रहा है । लेकिन अब यह नहीं चलेगा । चंद लोगों के तराज़ू से देश के संसाधन नहीं बटेंगे । यह इस देश का बहुजन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा । संसाधनों का बंटवारा संख्या के आधार पर होगा । मान्यवर कांशीराम साहब ने नारा लगाया था कि ?न तो अब वोट हमारा राज तुम्हारा चलेगा? और आज हम कह रहे हैं कि ?न ही वोट हमारा, नोट तुम्हारा भी नहीं चलेगा ।?

आपके माध्यम से सरकार से मेरी एक मांग है । सरकार इस योजना का श्रेय भी खुद ही ले ले कि बहुजन समाज के अत्यंत गरीब परिवार को एक लाख रुपये सालाना दे । इसके लिए दस लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे । लेकिन इस एक लाख करोड़ रुपये की योजना से एक झटके से परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर आएंगे और उनके बच्चों का कुपोषण खत्म होगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, महिलाओं को सम्मानजनक जीवन मिलेगा और इससे वास्तव में ?सबका साथ, सबका विकास? का नारा सार्थक होगा । अगर प्रश्न यह है कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा तो उसका जवाब यह है कि जब अमीरों का 16 लाख करोड़ रुपये माफ हो सकता है, कॉर्पोरेट टैक्स को घटा कर लाखों-करोड़ों रुपये का चूना सरकारी खजाने को लगाया जा सकता है, पैट्रोल-डीज़ल की एक्साइज़ ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है तो सरकार गरीबों को पैसा क्यों नहीं दे सकती है?

महोदया, समय आ गया है कि अब एससी एवं एसटी के लिए निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए । मेरी आपसे यह भी माँग है, क्योंकि अब समय की माँग है और देश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है तो मैं यह कहूंगा कि इस सरकार का, जो ?सबका साथ-सबका विकास? का नारा लगभग असत्य महसूस होता है, क्योंकि अल्पसंख्यकों में से मुसलमानों, जैनों, सिखों और बुद्धिस्टों के लिए कुछ दिख नहीं रहा है । उनके कल्याण के लिए कोई योजना नहीं है । मदरसों को जो बजट मिलता था, वह कम कर दिया गया है । लोग आर्थिक तंगी से मर रहे हैं । इंटर्नशिप की बात हुई है, लेकिन परमामेंट रोज़गार नहीं है । कल दिल्ली में बच्चों के साथ क्या हुआ है? उनकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी किसकी है? वे आए तो आईएएस, आईपीएस बनने, लेकिन वे यहां से लाशें बन कर गए हैं । कोई ध्यान नहीं दे रहा है, किसी की नज़र नहीं है ।

महोदया, मैं आपसे यह भी आग्रह करूंगा कि हम ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए लोग देश से बड़ा प्रेम करते हैं और हम यह महसूस करते हैं कि सरकारें हमें सुनेंगी, सरकारें हमारे बारे में सोचेंगी । लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद भी ऐसा महसूस होता है और जिसको ?अमृतकाल? कहा जा रहा है, आज भी एससी, एसटी एवं ओबीसी के लोगों पर अत्याचार हो रहा है । दो दिन पहले ही एक व्यक्ति को गोली से उड़ा दिया गया और राजस्थान में एक व्यक्ति की गर्दन काट दी गई है । ये घटनाएं देख कर घर से निकलते हुए भी डर लगता है कि घर वापस लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे । सरकार से मेरा आग्रह है कि अगर आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारी हत्याएं हो रही हैं तो हमारी माँ को भी दर्द हुआ होगा, जब उसने हमें पैदा किया होगा ।

हमारी बहनों को भी हमारे खोने का दर्द होता होगा । आपकी कैसी कानून व्यवस्था है? आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप महिलाओं के रेप नहीं रोक पा रहे हैं, हत्याएं नहीं रोक पा रहे हैं, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, किसानों, मज़दूरों की जान नहीं बचा पा रहे हैं । किसान सुसाइड कर रहा है, नौजवान सुसाइड कर रहा है और बड़ी-बड़ी बातें होती हैं । इधर भी अच्छे लोग हैं, उधर भी अच्छे लोग हैं, लेकिन अच्छाई तब होगी, जब ज़मीन पर भी कुछ काम दिखाई देगा । महोदया, ज़मीन पर कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है । जब किसी योजना की बात आती है तो सरकार हमसे मुंह मोड़ लेती । आप देखिए कि एजुकेशन का बजट कम कर दिया । हैल्थ का बजट कम कर दिया । जब मैं अपने क्षेत्र में गया, तो आप विश्वास कीजिए, अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं हैं, स्कूलों में मास्टर नहीं हैं और कोई भर्ती ऐसी नहीं है, जिसका पेपर न लीक होता हो । देश किस तरफ जा रहा है और इसमें नौजवानों का भविष्य क्या है, इसके बारे में भी हमें चिंता करनी चाहिए ।

महोदया, अंत में अपनी बात को समाप्त करते हुए मेरा आपसे और आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि यहां बाहर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई थी, जो कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है । आप विश्वास कीजिए कि उसको ले कर इतना गुस्सा है । मैं हाथ जोड़ता नहीं हूँ, लेकिन मैं हाथ जोड़ कर आपसे आग्रह कर रहा हूँ, सरकार से एवं प्रधान मंत्री जी से आग्रह है कि अम्बेडकरवादियों के सम्मान का ध्यान रखते हुए, उनके दिल की पीड़ा को समझते हुए, उनके दर्द का ध्यान रखते हुए उस मूर्ति को पुन: स्थापित करवा दीजिए । अगर इसमें कोई राजनीतिक कारण है तो वह अलग बात है । मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस वज़ह से लोगों में बहुत गुस्सा है । जिस दिन अम्बेडकरवादी गुस्सा हो जाएगा, वह फिर इस सरकार को, जो 2024 में आ गई है, उसको आने वाले चुनावों में ऐसा सबक सिखाएगी कि दोबारा यह पलट के नहीं देख पाओगे ।

मैं आपका धन्यवाद करता हूँ । मुझे विश्वास है कि सरकार मेरी बातों पर गौर करेगी और गरीबों के बारे में सोचेगी तथा गरीबों को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान होंगे ।

धन्यवाद ।

श्री राजकुमार रोत **(**बांसवाड़ा**) :** सभापति महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । पक्ष और विपक्ष दोनों ने बजट को ले कर काफी चर्चा की है । जब देश का बजट आता है, तब देश का युवा एक आस लगा कर बैठता है कि इस बार कुछ अच्छा होगा । देश का गरीब, आदिवासी, एससी यह आस लगा कर बैठता है कि कुछ अच्छा होगा । हमारे राजस्थान की बात करें तो ये लोग राजस्थान में डंका बजा रहे थे कि डबल इंजन की सरकार है, सब कुछ हो जाएगा ।

जब हमने केंद्र और राज्य का बजट देखा तो उसमें कुछ भी नहीं पाया । पूरे देश के एससी, आदिवासी और युवाओं को लग रहा है कि डबल इंजन की सरकार की दावा करने वाली सरकार का इस बार का जो बजट है, वह कहीं न कहीं सिर्फ बिहार व आंध्र प्रदेश तथा सरकार बचाने का बजट साबित हुआ है । इस बार जुमलेबाज का बजट आया है और इसे देश की जनता देख रही है । मैं बांसवाड़ा लोक सभा क्षेत्र से आता हूं । मैं बांसवाड़ा-डूंगरपुर की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे चुन कर यहां भेजा है । हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जिसकी कोई पहचान नहीं हैं, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे व्यक्ति को जीता कर क्या करोगे । लेकिन, बांसवाड़ा-डूंगरपुर की जनता ने ठान लिया था कि यह लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है, इसे राजतंत्र तय करने का किसी को ठेका नहीं है । यह लोकतंत्र है । वहां की जनता ने ठान लिया था कि इस बार राज कुमार रोत लोक सभा में जाएगा ।

महोदया, मैं पूरे सदन के माध्यम से अपनी जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा । मोदी जी ने वहां के बड़े-बुजुर्गों को कहा था कि घर-घर जाकर राम-राम बोल देना और चुनाव जीताना । वहां के बड़े-बुजुर्गों ने ठान लिया और कह दिया था । उन्होंने मेरे और आपके माध्यम से उन तक संदेश पहुंचाया है । उन्होंने मुझे कहा था कि मोदी जी से कह देना कि पिछले दस सालों में देश के आदिवासियों को उजाड़ने का काम हुआ है । देश के अंदर धर्म की राजनीति हुई है । देश में जनता के खातों में 15 लाख रुपये देने और 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देने की बात करके उन्होंने दस साल राज किया । इस बार हम उनको सबक सिखाएंगे । उन्होंने मेरे माध्यम से मैसेज पहुंचाया है कि यह गुरू गोविंद की धरती है, मावजी महाराज की धरती है, संत सूरमाल महाराज की धरती है । मानगढ़ धाम में 1500 आदिवासी शहीद हुए थे । वहां पर मोदी जी दो बार आए, लेकिन मानगढ़ के आदिवासी समुदाय के लिए एक शब्द भी नहीं बोल कर गए । उनके लिए वह कुछ नहीं करके गए । उन्होंने मैसेज पहुंचाया है कि आदिवासी समुदाय जाग गया है । अब वह वैसा आदिवासी समुदाय नहीं रहा, जो बहकावे में आ जाएगा और वोट दे देगा ।

माननीय सभापति महोदया, अभी जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है, बजट के अंदर मैंने देखा कि धातुओं के खनन को लेकर उद्योगपतियों को टैक्स में छूट दी गई है । यह खनन कहां हो रहा है, यह हमारी धरती पर हो रहा है, हमारे देश में हो रहा है, पहाड़ों में हो रहा है, जंगलों में हो रहा है । वहां पर जीव-जंतु रहते हैं । वहां हमारे आदिवासी समुदाय भी रहते हैं, लेकिन उन आदिवासियों के लिए क्या प्रावधान किया गया है? अगर आदिवासी इलाके के अंदर देखा जाए तो वहां आदिवासी समुदाय बैठा हुआ है, लेकिन उनको आज तक जमीन का पट्टा नहीं मिला हुआ है । वह आजादी के पहले से बैठा हुआ है और अपनी जमीन की बात करता है ।

सभापति महोदया, यहां पर सत्ता को लेकर होड़ मची रहती है । सत्ता पाने के लिए बहुत कुछ बोला जाता है । मैं कहना चाह रहा हूं कि हमें सत्ता नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपना अस्तित्व बचाना है । हमें अपना स्वाभिमान बचाना है । हमें अपना जल, जंगल और जमीन बचाना है । देश के अंदर देखा गया कि जब आदिवासी समुदाय जल, जंगल और जमीन की बात करता है तो उसको नक्सलवाद का ठप्पा दे दिया जाता है । उसको नक्सलवाद के नाम पर मारा जाता है । हम छतीसगढ़ के बस्तर इलाके में देखते हैं । वहां पर 11 साल की एक बच्ची को

मारा जाता है और कहा जाता है कि वह नक्सलाइट थी । तीन-चार साल के बच्चों को मारा जाता है, गर्भवती महिलाओं को मारा जाता है । आदिवासी समुदाय जब भी अपने हक-अधिकार की बात करता है तो उस पर नक्सलाइट का ठप्पा लगाया जाता है ।

सभापति महोदया, आदिवासी और एससी समुदाय को फ्री की योजना दी जाती है । हम कहते हैं कि फ्री की योजना मत दीजिए, बल्कि हमें अपना हक दे दो । हमें जल, जंगल और जमीन का मालिकाना हक दीजिए । संविधान के अंदर शेड्यूल फाइव और सिक्स के अंदर जो रिजर्वेशन पॉलिसी लागू की गई है, उसको धरातल पर लागू किया जाए ।

सभापति महोदया, मैंने देखा है कि भाजपा अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग चीजों के बारे में कहती है । कई जगह वह कहती है कि बीफ खाओ, कई जगह कहती है कि मत खाओ । हमारे आदिवासी समुदाय के लिए एक धर्म कोड की लंबे समय से माँग चल रही है । हमारे आदिवासी समुदाय को अलग से धर्म कोड दिया जाए । आजादी से पहले वर्ष 1871 से वर्ष 1951 तक अलग जनगणना हुई है । आज आदिवासी समुदाय का कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपना रहा है, कोई हिन्दू धर्म अपना रहा है । आदिवासी समुदाय अलग-अलग जगह बँटा हुआ है । आज आदिवासियों की पहचान खत्म हो रही है । हमारा समुदाय लंबे समय से कह रहा है कि आदिवासियों के लिए जनगणना में अलग से कॉलम और धर्म कोड होने चाहिए । झारखंड के अंदर 11 नवंबर, 2020 को झारखंड विधान सभा में अलग से आदिवासी धर्म के कॉलम को लेकर एक प्रस्ताव पास हुआ । उस समय विपक्ष में भाजपा थी और उसने समर्थन दिया । उसने कहा कि आदिवासी समुदाय धर्म की व्यवस्था में चाहे हिन्दू हो, ईसाई हो, वह उसमें नहीं आता है । आदिवासियों की अलग परंपरा और रीति-रिवाज है, इसलिए उनका धर्म कोड जारी किया जाए । आज राजस्थान में अलग तरीके से माहौल बनाया जाता है । हम कहते हैं कि हमें किसी धर्म में नहीं रहना है । हम आदिवासी हैं और आदिवासी रहने दिया जाए ।

माननीय सभापति महोदया, कोई वनवासी कहते हैं तो कोई कुछ और कहते हैं । जो व्यवस्था बनी है, उस व्यवस्था के अंदर हम कई बार कहते हैं कि हमें कुछ मत दो । एजुकेशन को लेकर नई शिक्षा नीति बनी है । ? (व्यवधान) अभी घंटी बजने वाली है, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा । नई शिक्षा नीति के तहत यह प्रावधान किया गया है कि 6 साल का बच्चा होगा, इसके बाद उसे पहली क्लास में एडमिशन दिया जाएगा । मैं कहना चाह रहा हूं कि यह निजीकरण को बढ़ावा देने का तरीका है, ताकि सरकारी संस्थाएं खत्म हों, निजीकरण हो । मैं अंत में एक ही चीज कहना चाहूंगा ? (व्यवधान)

मैडम, मेरे लोक सभा क्षेत्र के अंदर गुजरात और राजस्थान प्रदेश का बार्डर है, जहां पर माही और कंडणा है । मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर आदिवासी समुदाय और उस क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इरीगेशन के तहत माही और कंडणा से प्रोजेक्ट तैयार करके उस इलाके के अंदर रखा जाए । आप सबका धन्यवाद ।

श्री प्रदान बरुआ (लखीमपुर) : महोदया, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद । मैं सर्वप्रथम प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं । असम के आहोम किंगडम का माउंट बोरियल साइट को वर्ल्ड हैरीटेज साइट में मोदी जी के विशेष प्रयास से स्थान मिला । मैं इसके लिए मोदी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं । वर्ष 2024-25 का बजट आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत बनाने के लिए मजबूत फाउंडेशन देने वाला बजट है । मोदी जी ने 10 सालों में सोशियो-इकोनामिक डेवलपमेंट में बहुत काम किया, आयुष्मान भारत लाए, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लाए, प्रधान मंत्री आवास योजना लाए, नेशनल लाइवलीहुड मिशन लाए, उजाला योजना लाए, पीएम विश्वकर्मा योजना लाए, पीएम किसान केसीसी लोन, हर घर जल, पीएम स्वनिधि योजना लाए । मोदी जी ने सोशियो-इकोनामिक डेवलपमेंट के अलावा सोशल सिक्योरिटी में भी 10

सालों में काफी अच्छा काम किया । जन-धन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना जैसी योजनाएं लाए, जिसकी वजह से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए ।

इन्फ्रास्ट्रक्चर में देश भर में काफी सुधार हुआ है । मेरे क्षेत्र में पहले मीटर गेज लाइन थी, वह भी अबंडन्ड थी । आज उसका ब्रॉड गेज में कन्वर्जन हो चुका है । वहां ट्रेन्स चलने लगी हैं । आज राजधानी ट्रेन भी उस क्षेत्र में चल रही है । मेरे तीन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में मेडिकल कॉलेज बना, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट बना, इंजीनियरिंग कॉलेज बना, बोगीबील ब्रिज बना, भूपेन हजारिका का ब्रिज बना । मैंने देखा कि जो ब्रिजेज़ हैं, उनके काम में 15-20 साल लग गए । उस समय रेलवे का बजट 2,120 करोड़ रुपये था और आज की डेट में रेलवे का बजट 10,376 करोड़ रुपये है । ब्रिज बनाने के साथ-साथ मोदी जी ने 5 हजार करोड़ रुपये का बजट तुरन्त प्रदान किया था । इसके अलावा एग्रीकल्चर में भी काफी सुधार हुआ । इसका हमारे क्षेत्र में भी फायदा मिला । स्वाइल हेल्थ कार्ड से शुरू किया और अभी डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर तक मोदी जी एग्रीकल्चर सैक्टर को लेकर गए । पीएम किसान योजना और साथ-साथ केसीसी लिंकेज भी हर फार्मर्स को दे रहे हैं ।

मोदी जी ने फरवरी, 2024 तक ?विकसित भारत संकल्प यात्रा? अभियान चलाया । इस अभियान की वजह से लोगों को और आगे ले जाने का काम हुआ । उस टाइम मोदी जी ने जब अभियान किया था, मेरे दो डिस्ट्रिक्ट्स में सिर्फ 12 हजार और 17 हजार लोगों को पीएम किसान योजना का लाभ मिला था ।

आज की डेट में 70-80 हजार लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि मिला है । इसके अलावा, आईटीआई अपग्रेडेशन के लिए एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । मेरीज कन्सर्नड मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि असम में ज्यादा से ज्यादा फंड दिया जाए । नार्थ ईस्ट के युवा को इंटर्नशिप और दूसरा मौका मिले, इसके लिए वहां बड़ी-बड़ी कंपनीज नहीं हैं, एक-दो पीएसयूज ही हैं । ज्यादा से ज्यादा आईआईटी के अपग्रेडेशन के लिए फंड दिया जाए, यह मेरी विनती है ।

इसके साथ-साथ एनसीवीटी का जो नार्म्स है, अभी लेवल 6 तक सीखाया जाता है । मोदी जी के आने के बाद देश में जो भी इन्फ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, वह इंटरनेशनल लैवल का है । आईटीआई लैवल को 6-7 तक लाना पड़ेगा । इसके लिए इक्विपेंट्स, मशीनरी, टूल्स, लैब्स, फैक्लटीज भी उसके साथ जुड़े, यह मेरी माननीय मंत्री जी से विशेष रिक्वेस्ट है । इसके अलावा, 100 इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक नार्थ ईस्ट के लिए एलॉट किये हैं । मेरी एक विनती है कि इंटीरियर से इंटीरियर लोकेशन चूज की जाए, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस भी शुरू की जाए । हमारा जो परपज है, आज डिजिटल बिजनेस हो रहा है, डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसका मौका नार्थ ईस्ट के काफी इलाकों में नहीं मिल रहा है । अगर प्रॉपरली सिलेक्शन इंटीरियर इलाके में हो जाए तो यह मौका उन इलाकों में भी जरूर मिलेगा । यह मेरा कन्सनर्ड मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है ।

इस बार बजट में फ्लड और इरोजन के बारे में भी उल्लेख किया गया । मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं । असम में बीजेपी की सरकार चल रही है । एटीएस में 5 हजार 800 करोड़ रुपये सेंट्रल अस्सिटेंस मिल रहा है, उसमें से 5000 हजार करोड़ रुपये लास्ट तीन सालों से मिल रहे हैं । मुझे उम्मीद है, इस बार नार्थ ईस्ट में फ्लड और इरोजन के मिटिगेशन के लिए सेंट्रल अस्सिटेंस मिलेगा । इससे अच्छा काम असम और नेबरिंग स्टेट में होगा । इसके अलावा, बजट में टी-गार्डन के लिए एक हजार करोड़ रुपये दिये, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं । टी-बोर्ड के 721 करोड़ रुपये दिये हैं, इसलिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं । 63 हजार ट्राइबल विलेज को आगे ले जाने का काम इस बजट में रखा गया । इसके लिए मैं

माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं । अंत मे, मैं इस बजट का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री आदित्य यादव **(**बदायूं**) :** सभापति महोदया, सर्वप्रथम मैं सदन और मेरे निर्वाचन क्षेत्र बदायूं की जनता को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे आज संसद में अपनी बात रखने का मौका दिया है, बजट की चर्चा में अपनी बात कहने का मौका दिया । जब वित्त मंत्री जी अपना बजट पेश कर रही थीं, उस समय बहुत बड़ी-बड़ी बातें किसानों को लेकर कही गईं, नौजवानों के लिए कहीं गईं, महिलाओं के लिए कही गईं । लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है । 60 प्रतिशत से ज्यादा आबादी आज किसानी में है, लेकिन जब सरकार किसानों की बात करती है तो किसानों को भी याद आता है कि जब प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2014 में किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी । आज हम कहां खड़े हैं । हमने इन दस सालों में देखा कि किस तरीके से किसान आंदोलन के जरिए एमएसपी की मांग थी । स्वामीनाथन कमेटी की बात करते हैं तो सामने से पक्ष के लोग हल्ला करते हैं कि हमने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया है । लेकिन सच्चाई यह है कि स्वामीनाथन की जो मूल आत्मा थी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, आज भी यह सरकार उसे लागू नहीं कर पाई है । सरकार इस बात को याद रखे, जब सर्दी, गर्मी, बारिश और धूप किसान झेल रहा था, सर्दी में बैठ कर अपनी मांगों को लेकर लड़ रहा था, उस समय सरकार ने अपना मुंह फेरकर किसानों का अपमान किया ।

हमें याद रखना होगा, जब 700 से ज्यादा किसानों ने अपना बलिदान दिया, उस समय मौजूदा सरकार ने उनके बलिदान को पहचानने से भी इंकार कर दिया था । हमें याद रखना होगा कि आज भी देश के किसी न किसी कोने में कई परिवार हैं, जिन्होंने अपने मुखिया को खोया है । उनके बच्चों के बारे में सोचिए । किसान अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, शिक्षा दिलाने के लिए खेत में मजदूरी करता है, लेकिन आज उस परिवार का भविष्य क्या है?

मैं बदायूं लोक सभा क्षेत्र से आता हूं, वहा सिंचाई को लेकर बहुत बड़ी समस्या है । बदायूं के पास दो नदियां बहती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन नदियों से सिंचाई करने के लिए कोई कनैक्टिविटी नहीं है । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आने वाले समय में किसानों के खेतों की सिंचाई के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? इस समय मेरे लोकसभा क्षेत्र में सारे किसान ट्यूबवैल पर निर्भर हैं । इस समय बिजली की यह स्थिति है कि हम गांवों में 10-15 दिन तक बिजली की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं । सरकार की तरफ से सर्वे किया गया था और अधिकारियों ने बताया कि 56 सब-स्टेशन्स हैं, लेकिन कम से कम 35 सब-स्टेशन्स और होने चाहिए । उनकी रिपोर्ट पर सरकार ने निर्णय लिया और अब 33 सब-स्टेशन्स को घटाकर मात्र आठ सब-स्टेशन्स किए जाने की बात आ रही है । किसान इस समय पीड़ित है और हमारे क्षेत्र में त्राहिमाम मचा हुआ है, इसलिए बिजली की समस्या को शीघ्र ही देखा जाए और इन समस्याओं को समझा जाए ।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, कई प्रदेशों में किसानों के लिए अगर कोई गंभीर समस्या बनती जा रही है तो वह आवारा पशुओं की है । किसान और उसके परिवार को दिन में सड़ती धूप में खेत में मेहनत करनी पड़ती है और रात में जागकर फसल की रखवाली आवारा पशुओं से करनी पड़ती है । जब आवारा पशु रात में खेत चर जाते हैं तो किसान का नुकसान होता है और वहीं आवारा पशु जब सड़क पर जाते हैं तो किसी न किसी नौजवान या महिला की जान ले लेते हैं । जब किसानों की बात की जाती है और किसान सम्मान निधि की ओर देखकर सरकार अपनी पीठ थपथपाती है । आंकड़े कहते हैं कि रूरल सैक्टर में खरीद की क्षमता घटती जा रही है, निश्चित तौर पर हमें समझना होगा कि किसान सम्मान निधि किसी काम की नहीं है ।

मैं यूथ का नेतृत्व करता हूं, देश में 35 प्रतिशत नौजवान हैं, जिनकी मूलभूत सुविधाएं एजुकेशन और जॉब अपॉरच्युनिटीज़ हैं । आज सरकार कहीं भी जॉब देने में असमर्थ होती चली जा रही है । हमारे देश के 80 प्रतिशत से ज्यादा नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं । आने वाले समय में नौजवानों के रोजगार के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए । मुझ जैसे कई नौजवान हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में छात्र राजनीति में आगे बढ़कर इन सदनों में लोगों का नेतृत्व करते हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में छात्र राजनीति को खत्म करके कहीं न कहीं नौजवानों को आगे आने से रोका जा रहा है ।

मैं छात्रों के लिए केवल इतना कहना चाहता हूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाओं में, जहां होस्टल की फीस बहुत कम रखी जाती थी ताकि किसानों के बच्चे पढ़-लिख सकें, अगर 400 प्रतिशत फीस बढ़ाई जाती है तो किसानों के लिए बहुत मुश्किल की बात होगी । धन्यवाद ।

डॉ. इन्द्रा हांग सुब्बा (सिक्किम) : माननीय सभापति महोदया जी, आपने मुझे बजट डिसकशन में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । मैं सर्वप्रथम सिक्किम और सिक्किम की जनता की ओर से माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई और शुभकामना देते हुए इस बजट का समर्थन करता हूं ।

यह बजट, विशेषकर युवाओं को सक्षम और सशक्त बनाने वाला बजट है । हमारे देश को विकसित बनाने के संकल्प के साथ यह बजट पेश किया गया है । हमें बहुत खुशी है कि इस सत्र में, इस बजट में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए और ज्यादा इम्प्लॉयबल बनाने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है । यह बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन जो भी हो, देर से हुआ, फिर भी आज हमारे युवाओं को सक्षम बनाने के लिए स्किलिंग और स्किल डेवलपमेंट को इस बजट में बहुत इम्पॉर्टेंस दिया गया है । हम जैसे युवा लोग, जिसमें 50 प्रतिशत से ज्यादा आबादी इस देश में युवाओं की है । सारे राज्यों में अनइम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं । इसको आगे ले जाकर बजट में समावेश करना बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग बजट हमें लगता है । हम इसका समर्थन भी करते हैं और इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए सारी पार्टियां, अक्रॉस द पार्टी लाइन हमें एक साथ होकर युवाओं को सक्षम बनाना जरूरी है ।

महोदया, बजट में कहा गया है कि एक करोड़ युवाओं को 5 सौ टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप दिया जाएगा, जिसका प्रावधान बजट में किया गया है, लेकिन अक्सर यह हुआ है कि जब इंटर्नशिप दी जाती है, तब किसी बड़ी कंपनी में स्किलिंग के लिए लिया जाता है, तो बड़े शहरों में जो होता है और बड़े शहरों के नजदीक के गांवों को ही यह मौका मिलता है । जैसे सिक्किम दिल्ली से लगभग हजार किमी दूर है, जहां के लोगों को इंटर्नशिप का मौका ज्यादा नहीं मिलता । हम वित्त मंत्री जी से यह भी निवेदन करते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करते वक्त सारी राज्य सरकारों को और राज्य सरकारों की जितनी भी मशीनरीज हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन्स हैं, उनको भी साथ लेकर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि दूर गांव में बैठे एक युवा को भी मौका मिले कि एक बड़ी कंपनी में वह इंटर्नशिप करे और उसके बाद उस कंपनी में उसको भी नौकरी करने का मौका मिले ।

महोदया, स्किलिंग की जहां तक बात है, तो आज हम जब ग्रेजुएट हो चुके हैं, जब लोगों ने बीए, बीएससी, एमए सब कर लिया है, उसके बाद हम उनकी स्किलिंग करने की बात सोच रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर विकसित भारत बनाना है, तो हमें सोचना चाहिए कि ये स्किलिंग स्कूल लेवल और स्कूल करिकुलम से ही शुरू होनी चाहिए ताकि जब वह अपनी डिग्री खत्म करे, तब तक उसे एक एक्स्ट्रा स्किल भी मिले और कहीं भी काम करने को एक्स्ट्रा सक्षम बना सके । यहां बजट में बहुत ही विजनरी चीज को लाया गया है- नैचुरल फार्मिंग ।

महोदया, आपको पता ही है कि सिक्किम में नैचुरल फार्मिंग बहुत पहले से ही प्रैक्टिस करके आए हैं । इसको इम्प्लीमेंट करते वक्त हमारा अनुभव भी रहा है और इसकी रिसर्च पेपर्स ने भी पुष्टि की है कि जब नैचुरल फार्मिंग में हम शिफ्ट करते हैं, तो उस टाइम प्रोडक्शन 37 प्रतिशत से लेकर 50-60 प्रतिशत तक कम हो जाता है । इस समय जब हम नैचुरल फार्मिंग में शिफ्ट करने की सोच रहे हैं, तो किसानों को बहुत ज्यादा इंसेंटिवाइज करना जरूरी होता है, उनको इंसेंटिव देना जरूरी होता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को हम इन्करेज कर सकें कि वे नैचुरल फार्मिंग की तरफ जाएं और इसकी प्रैक्टिस करें । सिक्किम में नैचुरल फार्मिंग को जबरदस्ती इम्प्लीमेंट किया गया । उस टाइम जिस तरह से नैचुरल फार्मिंग में प्रोडक्शन कम हो गया, जिस कारण बहुत सारे किसानों ने फार्मिंग ही छोड़ दी । हमारी सरकार आने के बाद हम उनको इन्करेज कर रहे हैं कि नैचुरल फार्मिंग के प्रोडक्शन को बढ़ाएं और बाहर एक्सपोर्ट करने की भी सुविधाओं का इसमें प्रावधान होना चाहिए । मैं कैमिकल व फर्टिलाइजर की स्टैंडिंग कमेटी में चार साल रहा हूं । चार सालों में कभी भी बायो फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ । जितना भी इंसेंटिव फर्टिलाइजर्स में दिया जाता है, वहां पर इसका डिस्कशन होता है, लेकिन बायो मैन्योर को प्रोक्योर करने का डिस्कशन कभी नहीं हुआ । इसको भी आगे ले जाना चाहिए ताकि जो भी फार्मर नैचुरल फार्मिंग करना चाहता है, उनको भी इसकी सुविधा मिलनी चाहिए । मैं वित्त मंत्री जी को सिक्किम की ओर से बहुत धन्यवाद देता हूं । ? (व्यवधान)

मैडम, दो मिनट, दो ही पॉइंट्स हैं, उनको खत्म करने के बाद मैं कनक्लूड कर दूंगा । तीस्ता फ्लड जो सिक्किम में 2023 में हुआ, उसके लिए हमें असिस्टेंस दिया जाएगा, यह बजट में बताया गया है । हम बहुत खुश हैं । सिक्किम सरकार प्रधान मंत्री जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती है, लेकिन फ्लड का खतरा यहां तक ही नहीं है, सिक्किम में और एंटायर हिमालय में इतना ज्यादा ग्लेशियर लेक्स हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जिस तरह से ग्लेशियर डिप्लीट हो रहा है, जिससे ग्लेशियर लेक्स का आकार बढ़ता जा रहा है और वह डैंजरस होता जा रहा है । सिक्किम में 300 से ज्यादा ग्लेशियर लेक्स हैं, जिसमें 16 से ज्यादा अभी डैंजरस हो चुकी हैं । इसके मिटिगेशन के लिए हम सिक्किम की ओर से इतनी ही रिक्वेस्ट भारत सरकार से करते हैं कि सिक्किम में एक रीजनल सेंटर फॉर ग्लेशियलोजी बनाया जाए, जहां मिटिगेशन के लिए काम किया जाए । इसके साथ प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए मैं कनक्लूड करता हूं ।

श्री इटेला राजेंदर **(**मल्काजगिरि**) :** धन्यवाद सभापति महोदया, वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया था, उसका सम्पूर्ण रूप से मैं सपोर्ट कर रहा हूं । आज मैंने एलओपी की बात सुनी थी । एग्रीकल्चर के बारे में बहुत बातचीत हुई थी । अनइम्प्लॉयमेंट, यूथ के लिए भी बातें कही गई थी और एक बात बहुत स्ट्रेस के साथ सोशल जस्टिस के बारे में बताया था । मैं पूछना चाहता हूं कि 77 वर्ष की आजादी में इस देश के अंदर 50 साल से अबव का जिसने शासन किया था, वह कांग्रेस पार्टी ने किया था । कांग्रेस पार्टी ने जिस टाइम शासन किया था, उस समय देश के अंदर हजारों किसानों ने सुसाइड किया था । वर्ष 2014 तक खेती के काम के लिए उस सरकार ने कुछ भी नहीं किया था । स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद उस टाइम की सरकार ने कुछ भी इफेक्टिव मेजर्स नहीं लिए थे । मोदी सरकार आने के बाद वर्ष 2014-15 में एमएसपी 1360 रुपये था, आज 10 साल बाद एमएसपी 2320 रुपये हो गया है । आज किसानों के बारे में स्वामीनाथन कमेटी को पूरी तरह इम्प्लीमेंट करने वाली सरकार मोदी सरकार है ।

मैडम, दूसरी बात, नैचुरल फार्मिंग के बारे में अभी हमारे मित्र ने जो बात की है, वह फैक्ट है । 30-40 परसेंट प्रोडक्टिविटी कम होती होगी । वर्ष 2014 से एक हेक्टेयर में 2050 किलोग्राम भी नहीं था, अभी प्रोडक्टिविटी

बढ़कर 2552 किलोग्राम आ रहा है । इसमें नैचुरल फार्मिंग और सीरील्स प्रोडक्शन के लिए भारत सरकार और मोदी जी जो सोच रहे हैं, वह कैंसर, रीनल फेल्योर्स अलग-अलग डिजीज जो बढ़ती जा रही हैं, इस देश को डिजीज से बचाने हेतु जरूर सोचना चाहिए । मोदी सरकार आज हमारे लोगों की हेल्थ के बारे में सोच रही है और उस पर अमल होने के लिए हमारी सरकार जो स्टेप्स ले रही है, उसका स्वागत करना हमारा कर्तव्य है ।

मैडम, इस देश में सोशल जस्टिस के बारे में बात की जा रही है । हमारे तेलंगाना में आज तक कांग्रेस पार्टी ने शासन किया था, एक भी दलित मुख्य मंत्री नहीं हुआ, एक भी गिरिजन मुख्य मंत्री नहीं हुआ था और एक भी ओबीसी मुख्य मंत्री नहीं हुआ था । मैं पूछना चाहता हूं कि एलओपी को कि वर्ष 2014 में जब कांग्रेस पार्टी अपोजीशन के रूप में बैठी थी, इनको एलिजिबिलिटी नहीं मिली थी । तब अपोजीशन लीडर कौन था, ये तो नहीं हैं? वर्ष 2019 में भी इनको एलिजिबिलिटी नहीं मिली थी । उस समय भी इनके पास फ्लोर लीडर नहीं था । अभी एलिजिबलिटी मिलने के बाद इनको फ्लोर लीडर मिला है । भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में एक ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाया है । जब हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस समय हमने अब्दुल कलाम को प्रेसिडेंट बनाया था । वर्ष 2014 में गवर्नमेंट आने के बाद मोदी जी ने एक दलित बेटा को राष्ट्रपति बनाया था । ये इसकी कभी कल्पना नहीं कर सकते है । ये जो एससीज, एसटीज और ओबीसीज के बारे में बात करते हैं, अभी एक एसटी राष्ट्रपति, एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है । ये सोच भी नहीं सकते हैं और कल्पना भी नहीं कर सकते हैं । ये दलित जाति के लिए बात कर रहे हैं, मैंने अभी नहीं देखा है, लेकिन लास्ट कैबिनेट में आउट ऑफ 76 मिनिस्टर्स में से एससीज के 12 लोग मंत्री थे, 8 लोग एसटी के मंत्री और ओबीसीज के 27 मंत्री थे । जो एससीज के बारे में, एसटीज के बारे में और ओबीसीज के बारे में कल्पना करने वाली और उस पर अमल करने वाली जो पार्टी है, वह भारतीय जनता पार्टी है । हम क्वैश्चन नहीं कर सकते हैं ।

महोदया, मुझे कल भाषण देने के लिए मौका दिया गया था । मैं फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हूं । मैंने सभी भाषण को सुना है । क्या भाषण दिया गया, वह मैं नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि ये लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं । लेकिन, आज कहा गया कि यह काम का बजट नहीं है, प्रजा का बजट नहीं है, इस बजट में ऑपोजिशन राज्यों को गलत वितरण किया गया है, ये सारी बातें गलत हैं ।

महोदया, इस बजट में जैसा हमारे साथी ने कहा कि बहुत साल के बाद अनएम्पलॉयड युवा के बारे में सोचकर पैसा एलोकेट करके, इस इश्यू को टैकल करने का जो निर्णय लिया गया है, वह बहुत स्वागतयोग्य है । आज यह इश्यू केवल भारत में ही नहीं है बल्कि सारी दुनिया में, आज अमरिका भी अनएम्पलॉयमेंट का प्रॉब्लम फेस कर रहा है । आज दुनिया के अंदर इंफ्लेशन ज्यादा हो रहा है । आज दुनिया के अंदर इकोनॉमिकल रिसेशन हो रहा है । इसके बावजूद मोदी जी की सरकार ने एक ही बात सोची कि जो युवाशक्ति दुनिया के अंदर भारत में ज्यादा है, उसको प्रोडक्टिविटी में रखना है । इस युवा शक्ति को देश को आगे बढ़ाने के लिए मौका देने का जो निर्णय लिया था, वह निर्णय केवल स्वागत करने के लिए नहीं है, अगर उस निर्णय पर अमल करें तो यह देश, जो अभी दुनिया की फिफ्थ इकोनॉमी देश है, आने वाले दिनों में डेफिनेटली थर्ड इकोनॉमी बनेगा ।

महोदया, मैं दो-तीन विषय रखना चाहता हूं । इन्होंने एसीज के बारे में बात की थी, ठीक है, लेकिन जो एससीज, एसटीज, ओबीसीज महिलाएं शौच के लिए बाहर लोटा लेकर जाती थीं, उनके लिए 12 करोड़ मकान के अंदर टॉयलेट बनाकर उन लोगों का जिसने रेस्पेक्ट बढ़ाया, वह मोदी जी ने बढ़ाया । यह काम कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया था ।

महोदया, ये कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ । ? (व्यवधान) मैं पढ़ता हूं, आप मुझे दस मिनट टाइम दे दीजिए । The number of rural tap water, जो पहले 3.2 करोड़ था, आज 13.8 करोड़ है । वर्ष 2014 तक the export of goods and services 28 लाख 56 हजार 781 था । आज ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, आज यह 64 लाख 56 हजार 15 है । आप देखिए कि यूपीए गवर्नमेंट में क्या था और एनडीए गवर्नमेंट क्या है । वर्ष 2014-15 तक प्रोडक्शन 252 मिलियन टन्स था । पहले 130.2 मिलियन टन था, लेकिन अभी 328.9 मिलिटन टन है । पहले अनाज की उपज प्रति हेक्टेयर 2,028 किलो थी, लेकिन आज प्रति हेक्टेयर 2,525 किलो है । इससे पहले मैंने बताया था कि वर्ष 2014 में एमएसपी 1,360 रुपये थी, लेकिन आज 2,320 रुपये है । पहले फॉरेन एक्सचेंज 18,28,375 करोड़ रुपये था, लेकिन आज 53,91,255 करोड़ रुपये है । पहले हाउसहहोल्ड के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए 2,86,97,592 रुपये थे ।?(व्यवधान)

श्री मोहम्मद हनीफ़ा **(**लद्दाख**) :** सभापति महोदया, आपने मुझे बजट 2024-25 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं ।

मैडम, इस बजट में लद्दाख के लिए तकरीबन 6,000 करोड़ रुपये का एलोकेशन किया गया है । पिछले बजट में भी तकरीबन इतना ही एलोकेशन किया गया था, लेकिन उसको रिवाइज्ड करके 4,500 करोड़ रुपये किया गया था । उसका कारण यह बताया गया कि वहां पर खर्च कम किया गया है ।

मैडम, लद्दाख का जियोग्रॉफिकल हालत और मौसमी हालत ऐसी है कि वहां पर वर्किंग सीजन बहुत देर से शुरू होता है । वहां पर बारिश के बाद तकरीबन वर्किंग सीजन शुरू होता है । बजट में जो रिव्यू किया जाता है, वहां पर सितंबर माह में किया जाता है । उसको खर्च करने के लिए बारिश और सितंबर माह के बीच बहुत कम वक्त होता है । सितंबर माह तक बिलिंग प्रोसीजर तैयार नहीं होता है । रिव्यू के वक्त एक्सपेंडिचर सामने नहीं आ पाता है ।

ये जो मुद्दा है, उसको मैंने माननीय वित्त मंत्री साहिबा के सामने भी रखा था । सितंबर माह में जो रिव्यू किया जाता है, अगर लद्दाख में नवंबर-दिसबंर माह में रिव्यू किया जाए, तो दिसंबर माह तक बिलिंग प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है और पूरी तरह से एक्सपेंडिचर सामने आ जाता है । एक्सपेंडिचर के आधार पर 6,000 करोड़ रुपये अनाउंस हुए हैं, उसको रिवाइज्ड करके उस रकम को कम किया जाता है । अगर दिसंबर माह में रिव्यू किया जाए, तो उस वक्त लद्दाख का एक्सपेंडिचर पूरी तरह से सामने आ जाता है । वहां के लिए जो बजट अनाउंस होता है, ताकि वहां मुक़म्मल तौर पर उसको खर्च किया जाएगा ।

मैडम, लद्दाख में ऑटोनोमस हिल डेवलेपमेंट काउंसिल है, जो एक वाहिद संस्था है, एक सेटअप है, वहां पर ग्रास रूट लेवल से आवाम के चुने हुए नुमाइंदे उस काउंसिल में जाते हैं और वहां पर ग्रास रूट लेवल पर प्लान तैयार किया जाता है । मगर 6,000 करोड़ रुपये का जो बजट अनाउंस किया जाता है, उसका महज 10 प्रतिशत उस काउंसिल के अख़्तियार में दिया जाता है । मेरी मांग है कि बजट का कम से कम 40 से 50 प्रतिशत ऑटोनोमस हिल डेवलेपमेंट काउंसिल के अख़्तियार में दिया जाए ।

जब यहां पर पिछली बार जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल लाया गया था, उस वक्त माननीय गृह मंत्री साहब ने यहां पर वादा किया था कि ऑटोनोमस हिल डेवलेपमेंट काउंसिल की जो पावर है, उसको एम्पॉवर किया जाएगा, उसको घटाया नहीं जाएगा, लेकिन ऑटोनोमस हिल डेवलेपमेंट काउंसिल के पास जो कैपेक्स बजट जाता है, जब

वर्ष 2019 में यूटी बना था, उससे पहले ये नॉन लैप्सेबल हुआ करता था, लेकिन अब वह लैप्सेबल है । इस बजट से हिल काउंसिल को तकरीबन 40 से 50 प्रतिशत दिया जाए और उसको नॉन लैप्सेबल बनाया जाए ।

ऑनरेबल मैडम, आज यहां पर एम्प्लॉयमेंट पर काफी बातें हुई हैं । यहां पर कहा गया है कि यह जो बजट है, यह एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक बजट है, लेकिन आज लद्दाख में सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ी परेशानी है तो वह बेरोजगारी है । वर्ष 2019 में लद्दाख को यूटी बनाया गया । ? (व्यवधान) मैडम, प्लीज, लद्दाख के कुछ इश्यूज़ यहां पर रखना बहुत जरूरी है । लद्दाख में आज बेरोजगारी का मसला सबसे बड़ा चैलेंज है । लद्दाख में पिछले पांच साल से खासकर गैजेटेड पोस्ट की कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है । वहां पर अभी तक पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं बना है । यह पहले जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ था । यह यूटी बना और उससे अलग हुआ, लेकिन अभी तक यहां पर पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं बना है । रिक्रूटमेंट रूल्स बन रहे हैं । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** अब अपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्री मोहम्मद हनीफ़ा **:** मैडम, उस दिन भी मुझे टाइम नहीं दिया गया था । कुछ इश्यूज़ हैं, जिनको यहां पर रखना जरूरी है ।

माननीय सभापति **:** आप ले कर दीजिए ।

श्री मोहम्मद हनीफ़ा **:** मैडम, लद्दाख का जो नौजवान तबका है, पढ़ा-लिखा यूथ है, वह आज परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है । बहुत सारे जवान, बहुत सारे पढ़े-लिखे यूथ ओवर एज हो गए हैं । लद्दाख में रिक्रूटमेंट सिस्टम को जल्द से जल्द शुरू किया जाए । वहां पर पीएसी का गठन किया जाए । अगर लद्दाख को अलग से पीएसी देने में मुश्किल है तो जम्मू कश्मीर पीएसी के साथ रखा जाए और जल्द से जल्द रिक्रूटमेंट शुरू की जाए । वहां पर 80 परसेंट रिज़र्वेशन की बात गवर्नमेंट की पिछली हाई पावर कमेटी मीटिंग में हुई थी । वहां पर 80 परसेंट रिज़र्वेशन मिलना चाहिए । वहां पर एलआरसी मेंडेटरी होना चाहिए । ये लद्दाख की परेशानियां हैं । मैडम, इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज हैं ।

[جناب محمد حنیفہ (لدّاخ): میڈم چیرمین صاحبہ، آپ نے مجھے بجٹ 25-2024 پر بولنے کا موقع دیا، اس کے لئے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔

میڈم، اس بجٹ میں لداخ کے لئے تقریباً 6000 کروڑ روپئے کا ایلوکیشن کیا گیا ہے۔ پچھلے بجٹ میں بھی تقریباً اتنا ھی ایلوکیشن کیا گیا تھا، لیکن اس کو ریوائز کرکے 4500 کروڑ کیا گیا تھا، اس کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ وہاں پر خرچہ کم کیا گیا ہے۔

میڈم، لداخ کا جیوگرافیکل حالت اور موسمی حالت ایسی ہے کہ وہاں پر ورکِنگ سیزن بہت دیر سے شروع ہوتا ہے، وہاں پر بارش کے بعد تقریباً ورکِنگ سیزن شروع ہوتا ہے۔ بجٹ میں جو ریویو کیا جاتا ہے، وہاں پر ستمبر ماہ میں کیا جاتا ہے۔ اس کو خرچ کرنے کے لئے بارش اور ستمبر ماہ کے بیچ بہت کم وقت ہوتا ہے۔ ستمبر ماہ تک بلنگ پروسیزر تیار نہیں ہوتا ہے۔ ریویو کے وقت ایکسپینڈیچر سامنے نہیں آ پاتا ہے۔

یہ جو مدعہ ہے، اس کو میں نے محترمہ وزیرِ مالیات صاحبہ کے سامنے بھی رکھا تھا۔ ستمبر ماہ میں جو ریویو کیا جاتا ہے، اگر لدّاخ میں نومبر۔ دسمبر ماہ میں ریویو کیا جائے، تو دسمبر ماہ تک بلنگ پروسیزر کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور پوری طرح سے ایکسپینڈیچر سامنے آ جاتا ہے۔ ایکسپینڈیچر کی بنیاد پر 6000 کروڑ روپئے اناؤنس ہوئے ہیں، اس کو ریوائز کرکے اس رقم کو کم کیا جاتا ہے۔ اگر

دسمبر ماہ میں ریویو کیا جائے، تو اس وقت لدّاخ کا ایکسپینڈیچر پوری طرح سے سامنے آ جاتا ہے۔ وہاں کے لئے جو بجٹ اناؤنس ہوتا ہے، تاکہ وہاں مکمل طور پر اس کو خرچ کیا جائے گا۔

میڈم، لدّاخ میں آٹونومس ہل ڈیولپمینٹ کاؤنسل ہے، جو ایک واحد اِدارہ ہے، ایک سیٹ اپ ہے، وہاں پر گراس روٹ لیول سے عوام کے چُنے ہوئے نمائندے اس کاؤنسل میں جاتے ہیں اور وہاں پر گراس روٹ لیول پر پلان تیار کیا جاتا ہے۔ مگر 6000 کروڑ روپئے کا جو بجٹ اناؤنس کیا جاتا ہے، اس کا محض 10 فیصد اس کاؤنسل کے اختیار میں دیا جاتا ہے۔ میری مانگ ہے کہ بجٹ کا کم سے کم 40 سے 50 فیصد آٹونومس ہِل ڈیولپمینٹ کاؤنسل ک اختیار میں دیا جائے۔

جب یہاں پر پچھلی بار جموں کشمیر پُنر گٹھن بِل لا یا گیا تھا، اس وقت محترم وزیرِ داخلہ صاحب نے یہاں پر وعدہ کیا تھا کہ آٹونومس ہِل ڈیولپمینٹ کاؤنسل کی جو پاور ہے، اس کو ایمپاور کیا جائے گا، اس کو گھٹایا نہیں جائے گا، لیکن آٹونومس ہلِ ڈیولپمینٹ کاؤنسل کے پاس جو کیپیکس بجٹ جاتا ہے، جب سال 2019 میں یو۔ٹی۔ بنا تھا، اس سے پہلے یہ نونل لیپسیبل ہوا کرتا تھا، لیکن اب وہاں لیپسیبل ہے۔ اس بجٹ سے ہِل کاؤنسل کو تاریباً 40 سے 50 فیصد دیا جائے اور اس کو نون لیپسیبل بنایا جائے۔

آنریبل میڈم، آج یہاں پر ایمپلائمنٹ پر کافی باتیں ہوئی ہیں۔ یہاں پر کہا گیا ہے کہ یہ جو بجٹ ہے، یہ ایمپلائمنٹ سینٹرک بجٹ ہے، لیکن آج لدّاخ میں سب سے بڑا چیلینج ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑی پریشانی ہے تو وہ بے روزگاری ہے۔ سال 2019 میں لدّاخ کو یو۔ٹی۔ بنایا گیا۔ (مداخلت) میڈم، پلیز لدّاخ کے کچھ ایشیوزیہاں پر رکھنا بہت ضروری ہے۔ لدّاخ میں آج بے روزگاری کا مسئلہ سب سے بڑا چیلینج ہے۔ لدّاخ میں پچھلے پانچ سال سے خاص کر گزیٹیڈ پوسٹ کی کوئی بھی ریکروٹمینٹ نہیں ہوئی ہے۔ وہاں پر ابھی تک پبلک سروس کمیشن نہیں بنا ہے۔ یہ پہلے جموں کشمیر پبلک سروس کمیشن کے ساتھ تھا۔ یہ یو۔ٹی۔ بنا اور اس سے الگ ہوا۔ لیکن ابھی تک یہاں پر پبلک سروس کمیشن نہیں بنا ہے۔ ریکورٹمینٹ رولز بن رہے ہیں۔ (مداخلت)

میڈم، اس دن بھی مجھے ٹائم نہیں دیا گیا تھا۔ کچھ ایشیوز ہیں، جن کو یہاں پر رکھنا ضروری ہے۔

میڈم، لدّاخ کا جو نوجوان طبقہ ہے، پڑھا لکھا یوتھ ہے، وہ آج پریشان ہے، بہت سارے جوان، بہت سارے پڑھے لکھے یوتھ اوور ایج ہو گئے ہیں۔ لدّاخ میں جو ریکروٹمینٹ سسٹم کو جلد سے جلد شروع کیا جائے، وہاں پر پی۔اے۔سی۔ کا گٹھن کیا جائے۔ اگر لدّاخ کو الگ سے پی۔اے۔سی۔ دینے میں مشکل ہے تو جموں کشمیر پی۔اے۔سی۔ کے ساتھ رکھا جائے اور جلد سے جلد ریکروٹمینٹ شروع کیا جائے۔ وہاں پر 80 فیصد ریزرویشن کی بات گورنمنٹ کی پچھلی ہائی پاور کمیٹی میٹنگ میں ہوئی تھی۔ وہاں پر 80 فیصد ریزرویشن ملنا چاہئیے۔ وہاں پر ای۔آر۔سی۔ مینڈیٹری ہونا چاہئیے۔ یہ لدّاخ کی پریشانیاں ہیں۔ میڈم، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایشیوز ہیں۔]

श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल **(दमन और दीव) :** सभापति महोदया, आपने वर्ष 2024-25 के वित्त बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं । भारत सरकार द्वारा लाया गया बजट बहुत अच्छा है और हर तबके के लोगों का ख्याल रखकर बनाया गया है, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन हमारे प्रदेश के लिए इसमें विशेष कुछ नहीं है । हम केन्द्र से संचालित हैं तो हमारा विशेष ध्यान रखना चाहिए था ।

महोदया, इस बजट में लाई गई योजनाएं जब तक धरातल पर इंप्लीमेंट नहीं होती हैं, तब तक इसका फायदा नहीं है । हमारे प्रदेश में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है । हमारे प्रदेश के प्रशासक जी के अड़ियल रवैए और गलत नितियों के चलते, सरकार की योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जिसका खामियाजा हमारी जनता भुगत रही है । मैं अपने प्रदेश के कुछ मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । सरकार रोजगार देने की बात करती है, लेकिन हमारे यहां लोगों के रोजगार छीने जा रहे है । कितनी सारी सैंक्शन्ड पोस्ट्स खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन भरी नहीं जाती है । युवाओं को सालों साल कॉन्ट्रैक्ट पर काम करवाकर जॉब से निकाल दिया जाता है । जिन्होंने कोरोना काल की महामारी में अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने परिवारों की जान की भी परवाह नहीं की, उनको सालों साल काम करवाकर नौकरी से निकाल दिया गया । सरकार टूरिज्म को बढ़ावा देने की बातें करती है, लेकिन हमारे प्रदेश दमन एवं दीव में बस स्टैंड तक नहीं है । हमारा पहला प्रदेश है, जहां बस स्टैंड तक नहीं है । क्या ऐसे पर्यटकों का सुधार होगा? क्या ऐसे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा?

महोदया, सरकार एफडीआई द्वारा विदेशी इन्वेस्टमेंट बढाना चाहती है, लेकिन हमारा प्रशासन हमारे ओसीआई पासपोर्ट धारक भाईयों के काम-धंधे बंद करवाने के नियम बनाता है । सरकार गरीबों को आवास देने की बात करती है और हमारा प्रशासन गरीबों के घर-मकान तोड़ने काम करता है । यहां तक कि प्रधान मंत्री आवास योजना में बनाए गए घर-मकान भी तोड़ दिए गए हैं । हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात करती है, रोड, रास्तों को सुधारने की बातें करती है, लेकिन हमारे प्रशासन ने सारे प्रदेश के रोड को खोदने से नहीं बचाया, बल्कि सारे रास्तों को खोदकर रख दिया है । यहां तक कि प्रदेश में एकमात्र कॉस्टल हाइवे है, वह भी खेती करने का खेत जैसा बन गया है । सरकार बिजली के बढ़ते बिलों से लोगों को राहत देने के उपाय ढूंढ रही है और हमारा प्रदेश हमें पूरे भारत से सबसे सस्ती बिजली देने के बावजूद भी सरकारी विधुत विभाग सालाना 100 से 200 करोड़ का फायदा करता रहा था, लेकिन विभाग को निजी कंपनी टोरेंट को देकर सस्ती बिजली को दो से तीन गुना भाव बढ़ाकर भी विभाग को 500 करोड का सालाना नुकसान दिखाया जा रहा है । सरकार वित्तीय घाटा कम करने का प्रयास कर रही है, लेकिन हमारा प्रशासन विकास कार्य पर मूल लागत से 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के ऊपर काम देने के बावजूद भी समय सीमा पर काम पूर्ण नही करवा रहा है और विकास कार्य की मूल कीमत को दो से तीन गुना बढ़ाकर विकास राशि का सत्यानाश कर वित्तीय घाटा बढ़ाने में अहम योगदान दे रहा है ।

सरकार हेल्थ सुविधा सुधारने की बात करती है । हमारे प्रदेश में गरीबों को सरकारी अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज नहीं मिलता है । पैसे खर्च करने के बावजूद भी हमें छोटे-छोटे इलाज करवाने के लिए गुजरात और महाराष्ट्र जाना पड़ता है । सरकार शिक्षा में सुधार की बात करती है, लेकिन हमारे प्रदेश में आजादी के इतने साल बीत जाने के बावजूद एसएससी और एचएससी का बोर्ड तक नहीं बन पाया है । हमें पढ़ायी के लिए आज भी गुजरात और महाराष्ट्र पर निर्भर रहना पड़ता है । आज जीरो ऑवर में भी मैंने इस बात को उठाया है ।

मैडम, सरकार रोजगार बढ़ाने की बात करती है । हमारे यहां रोजगार कैसे बढ़ेगा? फैक्ट्रियां हमारे यहां से पलायन कर रही हैं । बिल्डर्स की बिल्डिंग्स तोडी जा रही है । होटल वालों के होटल्स तोड़े जा रहे हैं । बार और रेस्टोरेंट वालों के लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं । छोटे से छोटे कामधंधे को बर्बाद किया जा रहा है । प्रशासन की ऐसी नीतियों से हर कोई परेशान है । प्रदेश का रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? कैसे रोजगार बढ़ेगा? हमारी सरकार मछुआरों के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर आयी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहां पिछले आठ सालों से मछुआरों की हालत बहुत ही दयनीय है । गुजरात और महाराष्ट्र में मछुआरों को अनेक योजनाओं में लाभ देती है, वैसा लाभ हमारे प्रदेश के मछुआरों को नहीं मिल पा रहा है । हमें बोट की खरीदी, नेट की खरीदी, वायरलेस की खरीदी, फ्रीज की खरीदी और इंजन की खरीदी पर और मछली पकड़ने के लिए जिस सामान की जरूरत पड़ती है, उस पर जो सब्सिडी मिलती थी, मछुआरों को राहत मिलती थी, हमारे प्रशासन उन सारी

सब्सिडियों को बंद कर दिया है । इन सारी सुविधाओं को बंद कर दिया है । दुखद तो यह है कि भारत सरकार द्वारा मत्स्य संपदा योजना का लाभ हमारे मछुआरों को नहीं मिल पा रहा है । प्रशासनिक लापरवाही के चलते मछुआरों को वर्ष 2022-23 और 2023-24 में जो 14 महीने के डीजल के वैट की सब्सिडी का पैसा भी नहीं मिला है । तौकते तूफान से मछुआरों को जो नुकसान हुआ है, उसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है । मछुआरों के उत्थान के लिए जो कॉपरेटिव सोसायटी बनायी गयी है, उस पर भी प्रशासन ने कब्जा कर रखा है । क्या ऐसे मछुआरों का उद्धार होगा?

महोदया, सरकार लोगों के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं लायी है । इन सारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने के लिए स्वराज्य संस्थाओं का, जैसे ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और नगर पालिकाओं का अहम रोल होता है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहां स्वराज्य संस्थाओं को संवैधानिक संशोधन 73 और 74 के द्वारा जो पावर दी गयी हैं, वह सारी पावर प्रशासन ने छीन ली है । वहां नौकरशाहों ने स्वराज्य संस्थाओं पर कब्जा कर रखा है । यहां तक की पिछले 6-7 साल से स्वराज्य संस्थाओं को बजट तक नहीं दिया जा रहा है । सालों से स्वराज्य संस्थाओं को बजट मिलता था, लेकिन पिछले 6-7 सालों से स्वराज्य संस्थाओं को बजट नहीं मिल रहा है ।

मैडम, दो-तीन बातें और आपके समक्ष रखना चाहता हूं । मैडम, मैं कहां अपनी बात रखूंगा? हमारे यहां असेम्बली नहीं है । राज्य सभा में भी कोई नहीं है । मुझे सिर्फ दो मिनट का समय दीजिए । मैडम, एक-दो दफा तो ऐसा हुआ है कि मार्च के महीने के आखिरी दिनों में सुबह स्वराज्य संस्थाओं के एकाउंट में पैसे डाले गए और शाम को उनके पैसे निकाल दिए गए । मैडम, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पास असेम्बली नहीं है, हमारे पास सिर्फ स्वराज्य संस्थाओं के नाम पर ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और नगर पालिकाएं हैं, जिनको पावरफुल बनाया जाए । उनको पूरा बजट देकर विकास करने का पूरा पावर उनको दिया जाए ताकि सरकार की सारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाया जा सके ।

मैडम, बिल्डिंग बनाने का काम प्रशासन करता है । घोटाला भी प्रशासन के लोग ही करते हैं । दारू भी प्रशासन ही बेचता है । स्वराज्य संस्थाएं भी प्रशासन ही चलाएगा तो लोगों को रोजगार कहां से मिलेगा? रेवेन्यू कहां से जनरेट होगा? सरकार विभिन्न योजनाओं द्वारा फ्री में बिजली देने का संकल्प कर रहा है । हमारे यहां प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में सस्ती बिजली मिलती थी, लेकिन उसको बेचकर हमारे यहां बिजली बिल बढ़ा दिए गए हैं ।

मैडम, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार रोजगार बढ़ाने का प्रयास कर रही है, लेकिन हमारा प्रदेश में बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, जिनको बचाना बहुत जरूरी है । अन्य राज्य 50 परसेंट जीएसटी के रूप में केन्द्र को रेवेन्यू देते हैं, जबकि हम सौ प्रतिशत जीएसटी के रूप में रेवेन्यू देते हैं । मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे प्रदेश की फैक्ट्रियों को बचाने के लिए 50 प्रतिशत जीएसटी केन्द्र भले ही ले, लेकिन राज्य का 50 प्रतिशत जीएसटी माफ करने की कृपा करे । हमारे प्रदेश की फैक्ट्रियों को बचाकर हमारे कामधंधों और रोजगार को सुरक्षित करने की कृपा करें ।

19.00 hrs

SHRI SALENG A. SANGMA (TURA): Madam Chairperson, I would like to thank you for giving me this opportunity. I also want to thank the Leader of Opposition, Shri

Rahul Gandhi ji and also Madam Sonia Gandhi ji for allowing me to take part in this discussion.

Madam Chairperson, I do not want to repeat the argument. In fact, I was always positive with the development and policies. But this Government seems to neglect the Budget that was supposed to be pivotal, ensure the goodwill of the masses, and re-affirm the trust shown on 4th June. It has been long, and the Government has proven that they are focussed on ?Sabka Naash, Apna Vikas?. It seems like they have not learnt the lesson from the Lok Sabha polls. Once again, the Budget has attempted to fix supply side factors without paying enough attention to firm up ways to bolster consumer demand. Instead, the whole Budget exercise for the Financial Year seems to concentrate solely on reducing the Fiscal Deficit from 5.1 per cent currently to targeted 4.9 per cent, for which now the maximum price will be paid by the taxpayer. The taxpayer bears the brunt. The tax on long-term capital gains have now been increased. It is something that our Finance Minister said would only simplify the tax structure.

Madam Chairperson, this Government, instead of rewarding all the other States like Tamil Nadu, Maharashtra, Telangana, West Bengal, etc., which have contributed most of their tax to the revenue of this Indian economy, have concentrated only on two States, that is, Bihar and Andhra Pradesh. The new tax rules for the LTCG are only beneficial if a citizen of India is earning close to the exempted value of Rs 1.25 lakh. However, as we move beyond the exempted figure, the tax on capital gains will increase disproportionately because 2.5 per cent increase in tax rate outweighs Rs. 25,000 exemption increase.

Now, why do we celebrate this Budget? This is a matter of great concern that has garnered significant attention in the recent years. There have been devastating results. There has been an increase in the number of Indian citizens renouncing their citizenship and an exodus of tax-paying employees of our nation who are relinquishing their citizenship from India. When you look at the MEA report, approximately 1.87 million Indians are renouncing. In 2022 post-COVID pandemic, about 2,25,000 individuals have renounced and relinquished their citizenship from India. In 2023, the figure was more than two lakh.

Now, when we come to the States like Meghalaya and Manipur in the North East, it seems to have been neglected in the Budget for irrigation and flood mitigation. The Government seems to have not even touched the North East as evidenced by the situation in Manipur. There has been a lack of initiative to ensure the health and

the well-being of the women in the region despite Assam having the highest maternal mortality rate. The Government prioritizes expanding only the banking. When the women themselves will die, what is the purpose of banking? Therefore, I urge the Government to address this disparity, provide immediate aid to the riot-stricken people, and at the very least, establish well-equipped health care or hospitals to meet their needs.

Ugly surprises and uncertainty occur with no hope of predicting them in real time. When you look at Manipur, there has not been much effort to weigh the situations. No common framework seems to exist to set the rules for doing so. The victims of Manipur could not have foreseen what was going to happen and how the Government was going to deal with the livelihood meltdown of thousands of Manipuris. The notion that livelihood meltdown are scarce and a mirage, since in no other State these kinds of incidents generally happen, have proven wrong. These are the failures of the Government and it is very much unfortunate.

Coming to Meghalaya, I would like to say that Meghalaya has adopted a Resolution on Garo-Khasi language to be included in the Eighth Schedule, where we could have portrayed the beautiful language in this wonderful diversified decorum of the country.

Another one is the Inner Line Permit (ILP) issue. A Resolution in that regard has also been taken up on the floor of the House.

Now, we know that in the North-East, the issue of illegal immigration has become quite alarming. We need to put a check on illegal immigration. Just a few days back, hundreds of Rohingya immigrants have already migrated to India. We do not have proper checking points. If we could do serious checking in the border region, such incidents could have been stopped.

Now, rampant smuggling is happening along the border. Not only Rohingyas, but other anti-social elements are also coming into our State. So, checking points can be put up in these border areas. Even smuggling of areca nuts, drugs, brown sugar and all other things is happening. That is why, the local people are facing a lot of problem. Thank you, Madam.

श्री दर्शन सिंह चौधरी **(**होशंगाबाद**) :** सभापति महोदया, आज आपने मुझे केन्द्रीय बजट पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं संपूर्ण होशंगाबाद, नरसिंहपुर और रायसेन की जनता-जनार्दन एवं नर्मदा की माटी की ओर

से आपका आभारी हूं । मोदी जी के नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रस्तुत किया है । यह विकासमुखी, सर्वव्यापी और सर्वव्यापक है । चाहे महिला हो, युवा हो, किसान हो या गरीब हो, यह हर वर्ग के कल्याण के लिए है । जो थीम बनाई गई है, उस पर विपक्ष ने आरोप लगाए हैं । ?हरो कमावे, खोटो खावे?, हमारे यहां कहावत चलती है । इसको किसान ने साकार किया है, लेकिन एक देसी कहावत है कि

करे न खेती पड़े न फंद

इस कारण ये मुसरचंद ।

इन्होंने कभी खेती नहीं की है । इस लिए इनको किसानों का दर्द पता नहीं था । एक वह हालत थी, जब कांग्रेस के पहले प्रधान मंत्री ने कहा था कि इस देश का विकास उद्योगों के माध्यम से संभव होगा । हम उद्योगों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन ?* उसने किसानों की खेती को घाटे में डालने का काम किया था । हमारी सरकार मूल चार थीम्स पर काम कर रही है ? किसानों की लागत को कम करना, उनकी फसल के उत्पादन को बढ़ाना, उनकी फसल की मूल्य की गारंटी होना, जब उन पर कोई प्राकृति आपदा आ जाए, तो उस प्राकृतिक आपदा के समय सरकार उस संकट से उनकी रक्षा करे । इन चारों आयामों में माननीय मोदी जी ने सफलतम काम किया है, जिसके कारण अब मैं दावा कर रहा हूं कि कांग्रेस के जमाने में हमारे जो किसान खेती छोड़ चुके थे, वे खेती से दूर भाग रहे थे, कोई भी किसान अपनी बेटी का विवाद किसान के घर में नहीं करना चाह रहा था, कोई भी अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन जब से मोदी जी किसान व्यापी और राष्ट्र व्यापी बजट लाए हैं, उसके बाद आईआईटी में पढ़ाई किए हुए बच्चे भी आज खेती की ओर लौट रहे हैं । मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं । आज जो बजट आया है, वह आनंद से भरा हुआ बजट है । यह अमृतकाल का बजट है । यह दूरदर्शिता, विजन और भारत के संकल्प का बजट है । यह बजट वर्ष 2047 का मॉडल तैयार कर रहा है । यह भारत को सशक्त, समृद्धशाली, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर बनाने का बजट है । आज इस बजट में कृषि की उत्पादकता हमारी पहली प्राथमिकता है । यह किसानों के लिए आज तक का सबसे बड़ा बजट है । इसके माध्यम से एक लाख, 52 हजार करोड़ रुपए केवल किसानों के लिए दिए गए हैं । दलहन और तिलहन के लिए मिशन मोड तैयार किया है । अगले दो वर्षों में जिस आयाम को लेकर, क्योंकि मैं किसान मोर्चा का अध्यक्ष होने के नाते, मध्य प्रदेश में किसानों की सरकार लगातार बन रही है, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में 5 वीं बार और हमारे केन्द्रीय कृषि मंत्री जी ने लगातर इस काम को किया है । प्राकृतिक खेती के लिए जो बढ़ावा दिया है, एक करोड़ किसानों को दो वर्षों में जोड़ने का जो काम किया है, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं । खेती में उच्च पैदावार और जलवायु अनुकूल वाली 32 फसलों की 109 नई किस्में तैयार करने का जो लक्ष्य सरकार ने लिया है, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं । फसलों के उत्पादन, भंडारण, विपरण को और मजबूत बनाया जाएगा । सब्जी उत्पादन और आपूर्ति की श्रृंखला के लिए नए कलस्टर बनाए जा रहे हैं । राज्यों के साथ मिलकर कृषि के लिए डिजिटल और जो विपक्ष आरोप लगाता है, यह किसी राज्य तक सीमित नहीं, बल्कि यह पूरे भारत का बजट है । वर्ष 2024 तक 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल सर्वे किया जाएगा तथा उसको और उन्नत करने का काम किया जाएगा । आज प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय को चरितार्थ करने वाला, सर्वव्यापक, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी बजट है । वर्ष 2047 के रोडमैप में अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल पड़ी है और हमारा सुनहरा भविष्य हमको दिख रहा है । भारत फिर से विश्व गुरु, इसी दीवाने खास में जो लिखा है कि ?

?गर फिरदौस बर रुए ज़मीं अस्त;

हमीं अस्तो, हमीं अस्तो, हमीं अस्त ।?

यदि संसार में कहीं पर स्वर्ग है तो वह केवल मेरे भारत में है, केवल मेरे भारत में है । लेकिन मैं अपने विपक्षी मित्रों को कहना चाहता हूं?

?ऊंगलियां छोटी पड़ गईं, नाखून इतने बड़ गए ।

कुछ जुगनुओं के काफिले, मोदी जी के पीछे पड़ गए॥?

हमको समझना पड़ेगा । क्योंकि इन्होंने जो-जो करने का काम किया है ।? (व्यवधान) माननीय विपक्ष के नेता कहते हैं कि हमको डर लगता है, तुमको लगना भी चाहिए । क्योंकि डर उनको लगता है, जिनके कर्मों में दाग हैं । हम तो किसान के बेटे हैं, हमारे सीने में आग है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में चूंकि नम्न माटी का क्षेत्र है, गन्ना क्षेत्र के लिए मैं चाहता हूं कि हमारे नरसिंहपुर को गन्ना क्षेत्र घोषित करते हुए सहकारिता मिल का वहां पर गठन किया जाए । मध्य प्रदेश में नर्मदांचल लोक बनाया जाए, लोकों की बाढ़ आ गई है । ओंकारेश्वर से लेकर महाकाल तक, नर्मदांचल लोक बनाया जाए । धान को जीआई टैग दिया जाए । हमारा गेहूं का क्षेत्र है, इसलिए हम चाहते हैं कि गेहूं और मूंग की प्रोसेसिंग के यूनिट्स वहां पर लगने चाहिए । हर खेत को पानी मिले । इसके लिए छोटे-छोटे स्टॉप डैम बढ़ने चाहिए । पर्यटन के विकास की दृष्टि से आगे काम बढ़ना चाहिए । इसके लिए पंचमढ़ी को ज्यादा ? (व्यवधान) नदी से नदी को जोड़ने का जो बहुआयामी, दूरगामी निर्णय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिया था, मैं चाहता हूं कि हमारे यहां भी इस योजना को लागू करके हर खेत को पानी देने का काम करे । इसी के साथ जो यह बजट है, हमारा बजट इनोवेशन और प्रौद्योगिकी के माध्यम से कल्याणकारी बजट है । अभूतपूर्व स्पीड और स्केल का बजट है । समृद्धि और विरासत के समन्वय वाली सरकार का बजट है । वैश्विक पटल पर भारत को विश्व बंधुत्व बनाने का काम करने वाली सरकार है । इसलिए

सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ।

सबका ध्यान, सबका उत्थान,

यही है हमारे राष्ट्र का अनुष्ठान और मोदी जी का अनुष्ठान ।

इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि भारतमाता की जय । आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम, जय बलराम, नर्मदा मैया की जय ।

SHRI AMAR SHARADRAO KALE (WARDHA): Hon. Chairperson, Madam, this is my first term as a Member of Parliament. I would like to thank you for giving me an opportunity to speak on the Union Budget.

आज सर्वप्रथम मैं अपने वर्धा जिले के सभी मतदारों का यहां पर आभार मानना चाहूंगा । उन्होंने देश की सर्वोच्च सभागृह में अपना आशीर्वाद देकर मुझे यहां पर भेजा है । इसलिए सर्वप्रथम मैं उन सब मतदाताओं का यहां पर

आभार मानूंगा । यहां पर जो बजट पेश किया गया है, वह देश के सभी किसानों के लिए घोर निराशा का बजट है । ऐसा हमारा मानना है ।

Hon. Chairperson, around 11% of funds were allocated for agriculture in the 2010-11 budget. In 2020-21 budget, around 9.5% funds were given for agriculture but in this 2024-25 budget only 3.15% funds are allocated and it is a grave injustice done to the farmers. I heard the views of many Hon. Members on this Union Budget.

I represent Vidarbha region of Maharashtra and few years back, this region was infamous for farmers? suicides. Our Hon. Prime Minister had also visited Yavatmal in 2014 and he organized Chai-pe-Charcha programme at Dabhadi Borgaon village. हाँ, हमारा देश कृषि प्रधान देश है । In that programme, he had promised to do something for the betterment of agriculture and these farmers. He had expressed his concern over farmers suicides. जब तक मैं यह परिस्थिति बदल नहीं दूँगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगा । He had also promised to offer MSP on the basis of production cost. उन्होंने हमको बताया था । He had also promised to double the income of farmers and implement the recommendations of Dr. Swaminathan Commission.

आने वाले 20 मार्च, 2025 को मोदी जी की सारी घोषणाओं के 11 साल पूरे हो रहे हैं । मैं यहाँ पर माननीय मोदी जी को आह्वान करता हूँ कि पिछली बार आपने चाय पर चर्चा का आयोजन यवतमाल के दाभाड़ी में किया था । इस बार भी आप एक ?चाय पर चर्चा? का आयोजन दाभाड़ी में कीजिए । इन 11 सालों में आपने देश के किसानों के लिए क्या उपलब्धियाँ दी है, इन 11 सालों में देश के किसानों के लिए आपने क्या किया है, उनके बारे में आप देश के किसानों को बताइए ।

Today, we are getting only Rs. 7000 per quintal for cotton and Rs. 4500 per quintal for soyabean. Had he fulfilled his promise, we would have been received Rs. 15000 per quintal for our cotton. But, his promises are found to be feeble and futile. I would like to request Modi ji to organize that ?Chai-pe-Charcha? programme once again at same village called Dabhadi and explain what he did for farmers during the last 11 years. Farmers? suicides have not stopped and few cases can be seen even today. माननीय मोदी जी ने जिस गांव में ?चाय पर चर्चा? की थी, वर्ष 2014 से आज 2024 है, वहाँ हर साल दो या तीन किसान आत्महत्या करते हैं । वास्तव में इसको कोई झुठला नहीं सकता । इसलिए देश और देश का किसान मोदी जी से उत्तर चाहता है कि पिछले 11 सालों में आपने देश को क्या दिया है?

I would like to raise few issues related to my constituency Wardha. Oranges are grown at large scale in my constituency. We used to export oranges to Bangladesh from Vidarbha. हमारा संतरा बांग्लादेश को भेजा जाता था । जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, वर्धा-अमरावती से, Around 1 lack hectare land in Wardha-Amravati region, 25 lac hectare in Nagpur region and 25 hectare of rest of Maharashtra which adds up to 1.5 lac hectares of land which is exclusively used for cultivation of oranges in Maharashtra.

That is why, I would like to request you to kindly look into it. One last issue, I would like to raise. You have promised to construct 3 crore houses under PMAY, but you give only Rs. 1.20 lac for house construction in rural area.

तीन लाख हैक्टेयर संतरा हम बांग्लादेश को इम्पोर्ट करते थे । पिछले कुछ सालों में जिस तरह से इम्पोर्ट ड्यूटी बांग्लादेश ने बढ़ाई है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं । वर्ष 2019 में संतरे पर 20 टका इम्पोर्ट ड्यूटी थी, वर्ष 2020 में वह बढ़कर 30 टका हो गई, वर्ष 2021 में 51 टका हो गई, वर्ष 2022 में 63 टका हो गई, वर्ष 2024 में 88 टका हो गई और जुलाई, 2024 में फिर से बांग्लादेश ने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 101 टका कर दी है ।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा सवा लाख मीट्रिक टन संतरा बांग्लादेश को जाता, परंतु आज की स्थिति में सिर्फ 25 हजार मीट्रिक टन संतरा ? (व्यवधान) Madam, this is my maiden speech. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude in one minute.

? (*Interruptions*)

श्री अमर शरदराव काले **:** मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि सरकार को इस बारे में सोचने की आवश्यकता है । हमारे वरुड, मोर्शी और नागपुर के जो संतरा उत्पादक कास्तकार हैं, वे सब लोग इस सदन से आशा लेकर बैठे हैं कि उनके संतरे के बारे में कुछ पॉजिटिव सॉल्यूशन निकले । हम पीएम आवास योजना में एक लाख 20 हजार रुपये देते हैं । This amount should be increased. एक टॉयलेट बनाने के लिए भी एक लाख बीस हजार रुपए कम पड़ते हैं । I would also like to mention that Smt. Nirmala Sitharaman has completely disappointed women of India. She has done nothing for them. Women working as part time Attendants (PTA) in Health Centres get Rs. 3000 per month The State share is about Rs. 2900 and Central Government is contributing only Rs. 100. That is needed to be increased. Thank you.

SHRI PHANI BHUSAN CHOUDHURY (BARPETA): Madam Chairperson, thank you for giving me the opportunity to speak a few lines.

Madam, I am a newcomer in this august House, but I was a Member of the Assam Legislative Assembly since 1985. Actually, I was MLA for 38 years and six months, and now I am a MP. I must support the Budget which was presented by the hon. Finance Minister and I must quote a line from this Budget speech. I quote:

?Assam grapples with floods every year by the Brahmaputra River and its tributaries, originating outside India. We will provide assistance to Assam for flood management and related projects.?

In this regard, I want to say something regarding floods and erosion of Assam.

The geographical area of Assam is 78,438 sq. kms. out of which, flood prone area is 31,500 sq.kms., i.e., 39.5 per cent of total land of Assam is flood prone. If we go through the national statistics, in percentage terms, the flood prone area of Assam is four times the national mark of the flood prone area of the country. The report shows that the average annual area affected by flood is 9.31 lakh hectares. The flood affected area of the State of Assam is 16,500 sq.kms. till date.

*Respected Madam Chairperson, this year, two waves of flood have created havoc in Assam, resulting in the loss of 98 lives. Assam has 35 districts, and 34 districts have been affected by floods. The state has 26,395 villages, with 7,279 (27.5%) hit by recent floods. We are receiving financial assistance from the central government to address the flood situation, totaling Rs 4,600 crores so far. However, financial aid alone is insufficient to tackle the flood problem. The people of Assam demand a permanent solution to this perennial issue of flood and erosion. As a representative of the regional political party, Assam Gana Parishad, I convey the opinion of my party and the people of Assam. Even our Hon'ble Chief Minister has tweeted that, although we have received an amount of Rs. 4,600 crores as financial assistance from the central government, this will not help in solving the flood problem. We need a comprehensive project to find a permanent solution we want that to this critical issue. We want that the problem of floods and erosion be solved permanently, as mentioned in the budget. To address floods and erosion, we require a comprehensive project, including strengthening embankments, river training, watershed management and measures to enhance the depth of the Brahmaputra river. Through you, Madam, I request the Hon'ble Prime Minister and concerned minister to constitute a committee comprising technical experts to find a permanent solution to this serious problem of floods and erosion. Thank you for giving me the opportunity to speak. I conclude with these few words.

श्री जयन्त बसुमतारी **(**कोकराझार**) :** सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभारी हूं । मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को अपनी पार्टी यूपीपीएल की ओर से बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना प्रगतिशील और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला बजट पेश किया है । बजट में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए 5900 करोड़ रुपये की बड़ी घोषणा की गई है जिसके लिए असम और बोड़ो लैंड के लोगों की ओर से धन्यवाद करता हूं । बजट में बोडो लैंड टेरेटेरी काउंसिल काउंसिल, जो कि सिक्स्थ शेड्यूल काउंसिल है, इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी 174.66 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जो कि पिछली बार से 74.66 करोड़ रुपये से अधिक है । देश में टी बोर्ड के

लिए बजट को 5 गुना बढ़ाया गया है और इस वर्ष 721.50 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं जो असम के चाय उत्पादकों के लिए एक बड़ी मदद है । बजट में प्रधान मंत्री जी ने एक हजार करोड़ रुपये चाय वर्कर्स की वेलफेयर के लिए घोषणा की है । असम राज्य को 31174 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं जो कि राज्य के विकास में अधिक सहायक होंगे और असम के ट्राइबल इलाके के विकास के लिए प्रधान मंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना लाई गई है, जिससे आदिवासी इलाकों में विकास तेजी से हो सकेगा । नरेन्द्र मोदी जी द्वारा सहकारी क्षेत्र में निरंतर विस्तार देकर ग्रामीण अर्थ तंत्र को मजबूत बनाने का काम किया जा रहा है । बजट में सहकारी नीति के निर्माण की घोषणा देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर इसकी पहुंच को मजबूत करने का काम करेगी । इन निर्णयों के लिए मैं सभी भाइयों और बहनों की ओर से मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं ।

सभापति महोदया, बजट में ग्रामीण विकास के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का ऐलान किया है । बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए 11.11 करोड़ रुपये के बजट का एलोकेशन किया है जो देश की जीडीपी का 3.7 फीसदी है । वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में कृषि और इससे जुड़े सेक्टर्स के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं । शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में तीन करोड़ किफायती आवासों के निर्माण के लिए सहायता छोटे और मझोले उद्योगों को कर सहायता प्रदान की गई है । गरीबों के लिए तीन करोड़ नए घर बनाना तय हुआ है । जनजातीय उन्नत ग्राम विजन से नई अप्रोच के साथ पांच करोड़ आदिवासी परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ेगा । इसके अलावा ग्राम सड़क योजना 25 हजार नए ग्रामीण क्षेत्रों को ऑल वेदर रोड से जोड़ेगी । इसका लाभ देश के सभी राज्यों के दूर दराज गांवों को मिलेगा । केंद्रीय बजट में खेल मंत्रालय के लिए 3442.32 करोड़ रुपये में से खेलों इंडिया के लिए 900 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं । खेल मंत्रालय के बजट में पिछले सत्र की तुलना में 45.36 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है । यह आम बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट है । इसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया है । यह बजट पूरी तरह से समृद्धि और निष्पक्षता की ओर इशारा कर रहा है । यह बजट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उल्लेखनीय कदम साबित होगा । माननीय सभापति जी, बिना गारंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को दस लाख से बढ़ाकर बीस लाख रुपये किया गया है । हर शहर, हर गांव, हर घर एंटरप्रोन्योर बनाना है । इसी उद्देश्य के बिना गारंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को दस लाख रुपये से बढ़ाकर बीस लाख रुपये किया गया है । इससे छोटे कारोबारियों विशेष रूप से महिलाओं, दलित, पिछड़े आदिवासी परिवारों को स्वरोजगार मिलेगा ।

महोदया, यह बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है । यह देश के गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है । पिछले दस वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं । यह नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है । यह मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है । यह बजट जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने के लिए मजबूत योजनाओं के साथ आया है । इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी ।? (व्यवधान)

मैडम, संसदीय कार्य मंत्री जी से मेरी बात हुई है । सिंगल मेम्बर वाली पार्टी के मेम्बर को समय मिलना चाहिए ।? (व्यवधान)

श्री मुरारी लाल मीना **(दौसा) :** आदरणीय सभापति महोदया, सबसे पहले मैं अपने लोक सभा संसदीय क्षेत्र दौसा की जनता के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस सदन में भेजा । साथ ही, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

सभापति महोदया, यह बजट विभाजनकारी, सत्ता बचाने का और कुछ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाला बजट है । यह बजट सिर्फ अपने सहयोगियों को खुश करने वाला बजट है । देश के कई बी.जे.पी. शासित राज्य, जिसमें हमारा राजस्थान राज्य भी सम्मिलित है, इसके बारे में मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां इनकी सत्ता है, विशेषकर राजस्थान के नेता रोज ?डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार? कहते थे, लेकिन इस बजट में राजस्थान का नाम एक बार भी नहीं आया ।

सभापति महोदया, ये किसानों की बात करते हैं । हमारा देश कृषि प्रधान देश है । हमारा देश मजदूरों का देश है, युवाओं का देश है । ये किसान निधि की बात करते हैं, किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते हैं । मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इन्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये केवल दो काम कर दें । जैसा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी कह रहे थे, एक तो एम.एस.पी. को लीगल गारंटी दे दीजिए, जिससे हम ऑटोमैटिक अपने हिसाब से काम कर लेंगे । दूसरा काम, जो मेरा स्वयं का सुझाव है कि कृषि को मनरेगा से जोड़ दिया जाए । मनरेगा की मजदूरी दर, जो हमारी पार्टी के एजेंडे में भी था कि इसे 400 रुपये कर दीजिए । फिर किसान अपने आप ही सम्पन्न हो जाएगा । लेकिन, बड़ी सोची-समझी नीति के तहत, इनकी जो मूल भावना है, वह यह है कि ये कृषि का भी निजीकरण करना चाहते हैं । बजट में इन्होंने पूंजीपतियों को साथ लेकर उत्पादकता बढ़ाने का और अनुसंधान करने का मार्ग प्रशस्त किया है । उत्पादन बढ़ाने और अनुसंधान करने के नाम पर ये पूंजीपतियों को कृषि में शामिल करना चाहते हैं, ताकि किसानों की खेती का जो मामला है, वह भी धीरे-धीरे किसानों के हाथों से निकल जाए ।

सभापति महोदया, इस देश में मुख्य समस्या बेरोजगारी की है । स्किल या कौशल के नाम पर ये चाहते हैं कि गरीबों, एस.सी., एस.टी. के जो बच्चे हैं, वे इतना ही रोजगार करें, जिससे वे कोई बड़ी बात सोच ही न सकें । वे बस 10,000-15,000 रुपये की ही नौकरी करें ।

सभापति महोदया, ये सारे लोग अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं कि इनके बच्चे पढ़-लिख कर सरकारी नौकरी करें, लेकिन ये बड़ी सोची-समझी नीति के तहत सरकारी नौकरियों को खत्म कर रहे हैं । आज की तारीख में मैं समझता हूं कि पूरे देश में करीब 30 लाख सरकारी नौकरियां बकाया हैं । यह अच्छा होता अगर ये कहते कि आने वाले समय में हम इन 30 लाख पदों को भरेंगे, जिससे किसानों के बच्चों को, एस.सी., एस.टी. के बच्चों को नौकरी मिलती और वे अपना जीवन-यापन करते। अगर ये बैकलॉग भरने की बात करते तो हम समझते कि ये हमारे पक्ष में हैं, किसानों के पक्ष में हैं।

सभापति महोदया, सबसे बड़ी बात निजीकरण की है । जब लोक सभा चुनाव शुरू हुए, तो प्रारम्भ में ये संविधान संशोधन की बात कर रहे थे, आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे थे । लेकिन, जैसे ही इन्हें यह पता लगा कि जनता का मूड क्या है, तो इन्होंने तुरन्त ही ?यू-टर्न? लिया और फिर ये आरक्षण बचाने की बात करने लग गए । ये कहने लग गए कि हम आरक्षण के पक्ष में हैं । यदि आप आरक्षण के पक्ष में हैं तो आप इन सारे पब्लिक सेक्टर्स को खत्म क्यों कर रहे हैं? ये कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म नहीं करेंगे, पर ये पब्लिक सेक्टर्स को खत्म कर रहे हैं । इन्होंने एयर इंडिया को बेच दिया । इन्होंने हवाई अड्डे बेच दिए और पब्लिक सेक्टर्स को बेच दिया । सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने बैंकों का मर्जर किया है । हमें, सबको और आपको पता है कि पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था । उससे पहले पूरा देश और किसान सूदखोरों के चक्कर में फंसे रहते थे । जैसे ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, देश के विकास में और रोज़गार के मामले में लाखों लोगों को फायदा हुआ । लेकिन आपने वापस बैंकों का मर्जर कर के प्राइवेट बैंकों को बढ़ावा दिया और लाखों नौकरियां खत्म कर दीं ।

-

<u>19.40 hrs</u> (Hon. Speaker *in the Chair*)

यह आपकी इस बात का द्योतक है कि आप चाहते नहीं हैं कि गरीब परिवारों के लोगों की नौकरियां लगें । आपने बंदरगाह बेच दिए । आपने एयर इंडिया बेच दिया । आप सारी सरकारी संपत्तियों को धीरे-धीरे बेचते जा रहे हो । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** मुरारी लाल जी, अब समाप्त करें ।

? (व्यवधान)

श्री मुरारी लाल मीना **:** सर, अभी तो मेरी मूल बात रह ही गई है । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आप मूल बात बोल दो, बाकी बातें छोड़ दो ।

? (व्यवधान)

श्री मुरारी लाल मीना **:** सर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि यदि आप वास्तव मे हमारा भला चाहते हैं तो एक तो जातिगत जनगणना करवाइए । दूसरा, कई विभाग ऐसे हैं, जिनमें अभी आरक्षण की व्यवस्था नहीं है । विशेषकर देश के जितने भी टॉप पद हैं, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चीफ सैक्रेट्रीज़ एवं बड़े-बड़े पदों पर हमारे लोग नहीं हैं और कई जगहों पर आरक्षण की व्यवस्था है भी नहीं । इसलिए मैं आपके माध्यम से यह चाहता हूँ कि जिस तरह से आईएएस के एग्ज़ाम होते हैं, उसी तरह से भारतीय न्याय सेवा के एग्ज़ाम भी हों, ताकि जो गिने-चुने चार-पांच परिवार के लोग आज़ादी से ले कर आज तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनते आ रहे हैं, वह न हो । इसलिए न्यायिक सेवा भी होनी चाहिए, जिससे हमारे लोगों को इससे फायदा होगा । ? (व्यवधान)

सर, मैं राजस्थान के मुद्दे पर कहना चाहता हूँ कि सरकार ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का नाम लिया है, सूखाग्रस्त क्षेत्रों का नाम नहीं लिया है । हमारे राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है । पूरे राजस्थान के अंदर ईआरसीपी ? ईस्टर्न राजस्थान कैनाल नाम से प्रोजेक्ट है, मेरा आपसे निवेदन है कि जब आपकी सरकार राजस्थान में थी, वर्ष 2016-17 में ईआरसीपी का प्रोजेक्ट बढ़ा कर भारत सरकार को भेजा गया था । पांच साल तक उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया गया । अभी थोड़े दिन पहले जैसे ही सरकार दोबारा बनी तब केपीसी नाम से उस प्रोजेक्ट का एमओयू हुआ है । उस एमओयू का आज तक हमको पता नहीं है । हमारा जो पहले प्रोजेक्ट था, वह 50 पर्सेंट डिपेंडेबिलिटी पर था । अभी जो एमओयू हुआ है, वह 75 पर्सेंट डिपेंडेबिलिटी पर हुआ है । उसमें हमको पीने का पानी नहीं मिलेगा, सिंचाई का पानी नहीं मिलेगा । आपसे निवेदन है कि उस प्रोजेक्ट को दोबारा बनवाया जाए, ताकि हमारे किसानों का भला हो सके ।

धन्यवाद ।

डॉ**.** शिव पाल सिंह पटेल **(**प्रतापगढ़**) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया है । मैं आप सबका ध्यान वर्ष 2014 में एक साजिश के तहत चंद कॉर्पोरेट्स के द्वारा सारी मीडिया को हैक कर के एक प्रोपोगैंडा, जो झूठ का पुलिंदा था, जो पूरे देश में फैलाया गया था, उसकी

तरफ दिलाना चाहता हूँ कि अच्छे दिन आएंगे, काला धन वापस आएगा, 15 लाख रुपये खाते में आएंगे, दो करोड़ नौकरियां मिलेंगी, किसानों की आय दोगुनी होगी । ? (व्यवधान) लेकिन कुछ भी नहीं हुआ । वह सब झूठ का पुलिंदा था । ? (व्यवधान) उसी पर मैं एक शेर कहना चाहूंगा कि

?वह झूठ भी सच की तरह बोलता है ।

अगर धोखे से वह कभी सच भी बोले तो ऐतबार मत करना ।? ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्य, एक चीज़ का अंतर समझो । यह चर्चा बजट पर हो रही है, राष्ट्रपति अभिभाषण पर नहीं हो रही है । गौरव जी, सबको समझाओ ।

? (व्यवधान)

डॉ**.** शिव पाल सिंह पटेल **:** अध्यक्ष जी, बोल तो सभी ऐसे ही रहे हैं । सत्ता पक्ष से भी न जाने क्या-क्या नहीं बोला गय है । मैं यही कहना चाहूंगा कि यह किसान विरोधी, युवा विरोधी, पिछड़ा वर्ग विरोधी, और दलित विरोधी बजट है । आप देखें कि पिछड़ा वर्ग और दलित की अगर सबसे बड़ी उपेक्षा हुई है, अगर सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, तो इस सरकार में हुआ है । आप देंखे कि अभी पूरे देश में 27 परसेंट का आरक्षण है, लेकिन इस समय आँकड़े कहते हैं कि 17-18 परसेंट लोग ही पदों पर हैं । 10 परसेंट लोग कहाँ चले गए? बैकलॉग के जरिए उनको भरा जाए । इसी तरह से दलितों का भी यही हाल है । उनके भी बहुत से पद खाली हैं । उनके सभी पदों को बैकलॉग के जरिए भरा जाए ।

महोदय, प्रतापगढ़ की जो भी समस्याएं हैं, विशेषकर मैं कहूंगा कि इस समय वहां जरा सा भी पानी बरसता है तो पूरे जिले में, विशेषकर मुख्यालय पूरा जलमग्न हो जाता है । इसके लिए अगर यू.पी. को कुछ बजट दिया जाए तो हमारे प्रतापगढ़ को भी पैसा मिल जाएगा । इससे वहां भी कुछ काम हो सकता है ।? (व्यवधान)

महोदय, बस मैं एक संशोधन के लिए प्रस्ताव रखना चाहता हूं । आपने मुझे बोलने के लिए जरा सा ही समय दिया । नये बजट में एक प्रोविजन किया गया है कि पार्टनरशिप फर्म अब अपने भुगतान पर पार्टनर्स का टीडीएस काटेगा । यह हास्यास्पद बात है । सभी जानते हैं कि अपने पार्टनर्स के अलावा पार्टनरशिप फर्म में फर्म का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है । तकनीकी रूप से कहा जाए कि पार्टनर्स अपने द्वारा प्राप्त भुगतान पर स्वयं ही टीडीएस काटे, जो कि गलत है और टीडीएस का रिटर्न दाखिल करे । यदि इनकम टैक्स देना ही होगा तो वह भरेगा ही, उस पर जो भी पैसा लेगा । इसमें अलग से टीडीएस काटते हैं । टीडीएस का मतलब होता है ? टैक्स डिडक्शंस ऑन सर्विसेज । हम खुद पार्टनर हैं । पार्टनरशिप फर्म का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए हम अपने खुद का टीडीएस काटें, यह गलत है । इससे ऊर्जा नष्ट होगी, समय की बर्बादी होगी और उन्हें टैन नंबर लेना होगा । उन्हें टीडीएस रिटर्न भी दाखिल करना होगा । इसके अलावा और कुछ नहीं है ।? (व्यवधान)

महोदय, मुझे और एक मिनट का समय दे दीजिए । इसमें सबके हित की बात है । लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर और लोगों ने भी मुद्दा उठाया है । उसका मैं सपोर्ट करता हूं कि इंडेक्सेशन को हटाया जाए । इससे सभी का नुकसान होगा । इससे केवल ब्लैकमनी को बढ़ावा मिलेगा, और कुछ नहीं होगा । इंडेक्सेशन को जरूर हटाया जाए, बस यही आपसे निवेदन है । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्य, आप घड़ी देख लें और अपनी बात को तीन मिनट के अंदर समाप्त कर दें ।

DR. NAMDEO KIRSAN (GADCHIROLI-CHIMUR): Thank you Speaker Sir for giving me this opportunity.

The Budget proposals are devoid of strategy to deal with any problem of unemployment, price rise and the farmers? distress. It grossly neglects education, health and other crucial public services.

Sir, inflation remains a big concern for most of the families. The Finance Minister glossed over the problem by claiming price rise was within the target and non-core inflation was low. But, in reality, in June, the food inflation crossed 9.5 per cent and the price rise is such that the vegetables and fruits are beyond the reach of the common people. After ten years, people expect more of strengthening of the supply chain to counter the price rise than platitudes. An analysis of household consumption survey shows that more than 80 per cent of the population are spending less than Rs. 200 per day while almost 34 per cent of the people spend less than Rs. 100 per day. The vast population has nothing to gain from this Budget.

Another thing is that this Budget is a tacit acknowledgement of the Government?s failure over the last decade. Promises were made in the last decade that हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन वह दोगुनी नहीं हुई । इस बारे में वर्ष 2022 तक का टारगेट दिया गया था । उसके बाद बोला गया कि किसानों की फसल को उसके उत्पादन खर्च से डेढ़ गुना एमएसपी दी जाएगी, लेकिन उनको ड़ेढ़ गुना तो दिया नहीं । अब जो उत्पादन खर्च था, उसमें खादों की कीमत बढ़ गई, पेस्टिसाइड की कीमत बढ़ा दी गई । डीजल की कीमत बढ़ने से खेती करने का खर्च बढ़ गया । आज खर्च डबल हो गया है, लेकिन आय डबल नहीं हुई है ।

It is a Naxalite-infested area. It is a very backward region in the State of Maharashtra. यहां 10 दिनों से बाढ़ की सिचुएशन के कारण लोगों का जीवन अस्त-व्यवस्त हो गया है । यहां हर साल ऐसा ही होता है । अभी परसों ही एक खटिया पर लिटाकर मरीज को दो लोग 18 किलोमीटर तक लेकर गए एक जगह पानी भरा हुआ था, तो जेसीबी के बकेट के माध्यम से गर्भवती महिला को पहुंचाया गया ।

माननीय अध्यक्ष **:** आप राज्य सरकार को लिख दीजिएगा ।

डॉ**.** नामदेव किरसान **:** सर, वहां बहुत प्रॉब्लम्स है । अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए डायरेक्ट फंडिंग हो और हर साल 5 से 10 हजार करोड़ रुपये दिए जाएं और एक डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाए तो इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र दुरुस्त हो सकता है । महोदय, अर्थ मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी अभी सदन में नहीं है । मैं आपके माध्यम से उन तक यह बात पहुंचाना चाहते हैं कि एक बोर्ड की स्थापना की जाए । ... (व्यवधान)

SHRI G. KUMAR NAIK (RAICHUR): Thank you, Speaker, Sir, for giving me this opportunity. I would like to thank the people of Raichur and Yadgir districts and the leaders of my Party for giving me this opportunity to continue to serve the people beyond my retirement. Yes, Sir, it gives me joy to be joining the list of civil servants who had the opportunity to be Members of this august House.

Sir, I come from a very special land, Raichur and Yadgir. It is a land of gold. It has Hatti Gold Mines. It is the only operational large gold mines in India today. This region is called the rice bowl of Karnataka. It is a land of cotton. However, the dismaying fact of Raichur and Yadgir is also very, very distressing. I would like to come to that part in a minute.

I had been in my constituency in the last two days. There is a widespread dismay in my constituency. The common citizens are asking why this kind of ill-treatment is there with Karnataka and why this kind of partisan attitude is being shown by the Finance Minister. The Party, which has been in power for ten years, could have walked the talk. *Sabka saath sabka vikas* has been the slogan of this Government. However, everybody is feeling that it is *apno ke saath aur mitro ka vikas*.

Another Constitutional mandate which is often quoted is cooperative federalism. The feeling that one gets after listening to the Budget speech is that of whimsical and partisan centralism.

HON. SPEAKER: Hon. Member, please conclude.

SHRI G. KUMAR NAIK: Sir, this is my first opportunity to speak. Kindly give me a couple of minutes more.

माननीय अध्यक्ष **:** सभी को पहली बार मौका मिल रहा है । आप कंक्लूड करिए । आपके और भी माननीय सदस्य है, सबको बुलायेंगे । आप अपनी डिमांड रखिए ।

SHRI G. KUMAR NAIK: Forget about the special status or special package. Does Karnataka get even fair and regular treatment? We contribute a maximum share of GST to this country. But we get only 24 paise of every rupee which is being contributed. This kind of feeling could have been assuaged by the Budget proposition.

Sir, we have not got anything. Bangaluru requires investment for infrastructure. The Central Government is reluctant to support us in any way. Karnataka is a land of contrast. As I said, my constituency is called the rice bowl of Karnataka. But at

the same time, we have very, very distressing statistics, which I would like to bring to the notice of this august House.

The per capita income of my constituency is less than 50 per cent of the average of the State. The stunting among the children under five years is 58 per cent in Yadgir and 40 per cent in Raichur. Anaemia among women of 15 to 18 years is 62 per cent in Yadgir and 64 per cent in Raichur. According to the Multidimensional Poverty Index, about 26 per cent poverty is there in Yadgir and 21 per cent is in Raichur. The State?s average is just 7.5 per cent. My region is very backward.

We have only two specific demands which have already been realised but not been fructified. One is AIIMS. An AIIMS has already been granted by this Government in 2021-22. But still, it is not functional. It is high time that it is made functional. I request the Ministry to take it up immediately.

Another long-pending demand is for an airport. Our former Prime Minister Nehru ji made an emergency landing in our airport way back. We have enough available area. The Ministry of Civil Aviation could have announced it in the Budget.

श्रीमती कमलजीत सहरावत (पश्चिम दिल्ली) : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे 18 वीं लोक सभा में बजट के पक्ष में बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद । मैं सर्वप्रथम पश्चिमी दिल्ली की जनता का बहुत धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने मौका दिया कि मैं इस ऐतिहासिक लोक सभा का हिस्सा बन पायी । मैं दिल्ली की जनता का भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं जिन्होंने राजधानी क्षेत्र के सातों सांसदों को तीसरी बार दिल्ली में जीता कर इस बात को साबित किया कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी देश को जिस दिशा में लेकर जा रहे हैं, देश उससे सहमत हैं ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, वित्त मंत्री जी ने ऐतिहासिक रूप से सातवीं बार बजट पेश किया है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि बजट भी बहुत ऐतिहासिक है । देश 11 वें नम्बर से 5 वें नम्बर पर पहुंचा है । इन पिछले पांच सालों में उनके द्वारा प्रस्तुत बजट से हमारा देश स्टार्ट-अप का पांचवें नम्बर का सबसे बड़ा इको-सिस्टम बनकर विश्व के सामने आया है । मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं ।

एक महिला होने के नाते मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं । आधी आबादी को अपने निर्णयों से आर्थिक विकास के साथ आत्मसम्मान दिलाने का प्रयास अगर किसी प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से दिखाया है तो वह देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी हैं । अगर दस साल पहले महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का बजट देखें तो वह मात्र 20 हजार करोड़ रुपये होता था, जिसे इन दस सालों में बढ़ाकर 26 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है । पहले फेज में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वीमेन डेवलमेंट के ऊपर बात होगी, अब नया फेज है, इसमें वीमेन लेड डेवलपमेंट के ऊपर बात रखी गई है, केवल बात नहीं रखी गई है बल्कि अपने निर्णयों में उन्होंने इस बात को साफ किया है जिसे आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने रखा है ।

मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट वर्किंग वूमेन हॉस्टल के साथ क्रेचेज भी बनेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप में 83 लाख सेल्प हेल्प ग्रुप बने हैं । उसमें 9 करोड़ महिलाएं खुद को इन्वोल्व कर पायी हैं, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष वृद्धि हुई है । एक करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, उसे वित्त मंत्री जी ने रखा है । हमारा बजट उस तरफ अग्रसर है, यह हम देख पा रहे हैं । विश्व की सबसे बड़ी योजना स्वास्थ क्षेत्र की आयुषमान योजना है, उसमें आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स, जिसमें सबसे ज्यादा महिलाएं थीं, 10 लाख महिला आशा वर्कर्स और 13 लाख आंगनबाड़ी बहनों को इससे फायदा होगा । पीएम मुद्रा लोन योजना 10 लाख से 20 लाख की है, मैं विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं क्योंकि 27 लाख करोड़ रुपये का लोन दिया गया, उसमें 70 प्रतिशत महिलाओं ने इस लोन को खुद के लिए रजिस्टर किया है, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

तीन करोड़ पीएम आवास योजना के अंतर्गत घर दिए गए और यह बहुत खुशी की बात है कि इसमें 70 प्रतिशत ज्वाइंट 26.6 अकेली महिलाओं के नाम घर का इंटाइटलमेंट हुआ है, जो महिलाओं को आत्मसम्मान की तरफ ले जाता है । एलपीजी कनेक्शन 10 करोड़ 33 लाख उज्ज्वला कनेक्शन मिला, जिसमें बचत और स्वास्थ्य भी है । अनेक ऐसे काम हुए हैं, पीएचडी की इनरॉलमेंट एक करोड़ हुई है, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगी, क्योंकि समय बहुत कम है, आपने जो समय दिया है, उसमें कन्कलूड करते हुए यह बात जरूर कहूंगी सिर्फ बजट में आर्थिक रूप से महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता । आत्मसम्मान प्रधानमंत्री जी ने दिया है, हज पर हमारी मुस्लिम बहनें अकेले नहीं जा सकती थीं, उन्हें पुरुष और समूह में जाना कम्पलसरी था, इस कन्डीशन को हटाकर वर्ष 2023 में हमारे देश की मुस्लिम बहनें जो हज पर गई हैं, उनकी संख्या चार हजार है । लेडी विदाउट मेहरम स्कीम के अंतर्गत गई हैं, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देती हूं ।

20.00 hrs

दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल के नाम पर दिल्ली सरकार ने लोगों को भगवान भरोसे छोड़ने का काम किया । दिल्ली में एम्स, आरएमएल, सफदरजंग आदि सात अस्पताल हैं, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने इस संबंध में 10,500 करोड़ रुपये का बजट प्रोविजन किया है, मैं उनका धन्यवाद करती हूं । दिल्ली में 1080 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें 300 में साईंस नहीं है, लेकिन दिल्ली वाले सौभाग्यशाली हैं कि छ: संस्थाओं के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी आदि के लिए 5200 करोड़ रुपये दिए गए हैं ।

महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी पर सामने से बहुत सवाल उठाए गए हैं । उनके किए हुए कर्मों से आज हम तीसरी बार यहां पर हैं । मैं एक बात कहना चाहती हूं-

शब्दों का एक सवेरा हूं, इंकलाब लिखता हूं,

अपने स्वर्ण हिंद के विकास का सच्चा ख्वाब लिखता हूं ।

माना सवाल बहुत उठाते हैं मुझ पर ये सामने वाले,

लेकिन मैं अपने कर्मों से उनका जवाब लिखता हूं ।

महोदय, मैं केवल दो बातें कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी । दिल्ली में प्रदूषण के जो हालात हैं, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जिस तरह से मेट्रो के लिए बजट दिया है, रेल के लिए 3000 करोड़ रुपये का बजट दिया है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूं ।

महोदय, सामने से बोला गया कि सरकार ने क्या किया है । मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि सामने वालों को पोलियो की दवाई लाने में 18 साल लग गए, लेकिन कोविड के दौरान कोविड की दवाई लाने का यह सदन गवाह बना, आप भी गवाह बने । हम भाग्यशाली हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार के समय में तीन गुना शक्ति और तीन गुना गति से विश्व की तीसरी अर्थव्यस्था बनने की तरफ बढ़ेंगे । आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 30 जुलाई, 2024 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

20.02 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Tuesday, July 30, 2024/Sravana 8, 1946 (Saka).

———

---

* Not recorded as ordered by the Chair.

* Expunged as ordered by the Chair.

* Expunged as ordered by the Chair.

*Not recorded as ordered by the Chair.

* Expunged as ordered by the Chair.

* Not recorded.

* Not recorded as ordered by the Chair.

?. English translation of this part of speech was originally delivered in Assamese.